चीन की आर्थिक चुनौतियाँ एवं स्वदेशी

प्रोफेसर भगवती प्रकाश

स्वदेशी जागरण मंच

'धर्म क्षेत्र' शिव शक्ति मन्दिर,

सेक्टर 8, आर. के. पुरम, नई दिल्ली

ई-पुस्तक प्रस्तुति

स्वदेशी विचार केन्द्रम्

708/14E ,मारवाड़ अपार्टमेन्ट,जोधपुर (राज) सम्पर्क-9414126770

लेखक की लघु पुस्तिकाएं

1. स्वदेशी
2. विश्व व्यापार संगठन
3. आर्थिक वैश्वीकरण: बाहरी दबाव जन्य रीतिनीति
4. आर्थिक वैश्वीकरण: वैश्विक षडयंत्र की रीतिनीति
5. स्वदेशी का शंखनाद
6. Disinvestment
7 Reasons of Global Meltdown & Lessons for India
8 वैश्विक आर्थिक संकट: कारण व समाधान
9. चीन एक सुरक्षा संकट
10 Nuclear Programme of India
11 फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश
12 विकास की भारतीय अवधारणा
13 चीनी गुसपैठ और हमारी सुरक्षा व्यवस्था
14 Chinese Aggression: Need for Deterrent Action
15 Economic Resurgence through: Made by India "A Strategic Mix for Economic Turnaround of the Indian Economy
16 Economic Reforms and Made by India
17 FDI in Insurance & Pension Sectors

18 एकात्म मानव दर्शन

19. आर्थिक सुधार बनाम ''मेड बाई इंडिया''

20. मेड बाई इण्डिया

21 Made By India

22 सौर ऊर्जा तकनीकी राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता

23. Solar Power: Need for Techno Nationalistic Approach

24 आर्थिक सुधारों के 25 वर्ष

25 चीन की चुनौतियाँ और समाधान

26 अजेय राष्ट्र

27 हिन्दुत्व की पहचान - समरस समाज

28 पर्यावरण और हम

29 स्वदेशी से बनायें समृद्ध भारत

30. अजेय भारत

भूमिका

चीन ने 1962 में आक्रमण करके अक्सई चिन में भारत की 38,000 वर्ग किमी. भूमि बलात हड़प ली थी। विगत 50 वर्षों में भी वह सीमा पर निरन्तर घुसपैठ करता रहा है और भारतीय सीमा में अनेक नवीन स्थानों पर छुट-पुट अतिक्रमण करता ही जा रहा है। वर्ष 2013 में 14-15 अप्रेल की रात्रि में तो उसने 40-50 सैनिकों के एक प्लाटून व कुछ कुत्तों के बल पर 'दौलत बेग ओल्डी' के, रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र पर 21 दिन तक अपना अधिकार जमा लिया था। भारत सरकार ने उन 40-50 घुसपैठियों को सैन्य बलों की सहायता से निकाल बाहर करने के स्थान पर, चीन की अनेक अपमान जनक शर्तें मान कर ही उन्हें वापस जाने पर सहमत किया था। वह निर्णय भी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था।

चीन से निरन्तर बढ़ रहे सुरक्षा संकटों देश में चीनी वस्तुओं की उत्तरोत्तर बढ़ रहीं बिक्री और देश में चीन को प्राप्त हो रही उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यापार व निवेश सुविधाओं से चीन के बढ़ते आर्थिक सशक्तिकरण देश का प्रत्येक सजग नागरिक अत्यन्त चिन्तित है। इन्हीं चिन्ताओं पर केन्द्रित लेखक की चीन पर प्रकाशित 4 पुस्तकों का विविध प्रान्तों में कई बार पुनः मुद्रण हुआ। देश हित में इस पुस्तक के यथावत शब्दशः मुद्रण व प्रसार के लिये सब लोग व संगठन स्वतंत्र हैं। ऐसा होने से इस पुस्तक का देश भर में व्यापक प्रसार हुआ है। चीन की हाल की ताजा घुसपैठ की घटनायें व 1962 से भी अधिक बुरा हाल करने जैसी धमकियाँ चीन के और भी गम्भीर शत्रुतापूर्ण व्यवहार की द्योतक है।

चीन द्वारा निरन्तर एवं बार-बार घुसपैठ के माध्यम से उत्तरोत्तर नये-नये क्षेत्रों में भारतीय भू-भाग पर अनवरत अतिक्रमण, जल व थल सीमा पर चारों ओर से अमित्रतापूर्ण घेराबन्दी, वायु सीमा का आये दिन अतिक्रमण, हमारे दक्षिणी तटीय क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ाने के लिये और वियतनाम में तेल खोज से दूर रहने की चेतावनी देने के उद्देश्य से श्रीलंका के बन्दरगाहों पर अकारण आणविक पनडुब्बियों की कवायद आदि जैसी अनगिनत शत्रुवत कार्यवाहियाँ जारी हैं। तथापि, हमारे द्वारा चीन को

अनवरत व बिना किसी पारस्परिक आर्थिक प्रति-लाभ के व्यापार व निवेश की सुविधाएँ देते चले जाने की नीति आत्महीन समर्पण से कम नहीं है। चीन के साथ हमारे 70 अरब डालर के व्यापार में हमें, 40 अरब डालर के वार्षिक व्यापार-घाटे का सामना करना पड़ रहा है। विश्व के किसी भी देश के साथ हमारे व्यापार-घाटे की तुलना में यह सर्वोच्च व्यापार-घाटा हम चीन से सह रहे हैं। विश्व इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ, कोई देश इस प्रकार की आक्रामक व शत्रुता पूर्ण कार्यवाही में निरन्तर सक्रियता पूर्वक लिप्त हो और उससे पीड़ित देश अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना कर हम उसके साथ इस व्यापार में सर्वोच्च 52 अरब डालर का घाटा भी सहन कर रहा है। चीन से इस घाटे के कारण ही रुपये की कीमत में विगत 5 वर्षों में भारी गिरावट आयी है।

चीन द्वारा की जा रही इन अनवरत शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के उपरान्त भी, भारत द्वारा चीन को सर्वाधिक व्यापार सुविधाएँ देना, और भी आत्मघाती कदम है। देश का 2015-16 में सर्वाधिक 52 अरब डालर का व्यापार घाटा, चीन के साथ ही है। आवश्यकता इस बात की है कि चीन का जो 4-5 लाख करोड़ रूपये का माल हम देश में आयात करते हैं, उसे हमें बन्द करना चाहिये।

आम जनता में जो लोग चीनी फर्नीचर, विद्युतीय साज सामान, टेक्सन का चीनी केल्कुलेटर, लीनोवो का कम्प्यूटर, चीनी मोबाइल फोन, बल्ब आदि खरीदते रहे हैं। उन्हें भी इसे बन्द करना चाहिये। आज चीन का 60 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन निर्यात आधारित है। ऐसे में चीन के द्वारा अपने देश सहित, तिब्बत व अफ्रीका में कई देशों के साथ औपनिवेशिक व्यवहार एवं मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है और सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से विश्व के लिये पर्यावरण संकट उत्पन्न किया जा रहा है। इन सबके आधार पर यदि उसके विरूद्ध देश में व विश्व समुदाय को भी चीनी माल के बहिष्कार का आवाहन किया जाये तो विश्व के लिये सुरक्षा संकट के रूप में उभर रहे चीन को अच्छा पाठ पढ़ाया जा सकता है। अस्तु, इन्हीं सारे विषयों पर यह लघु पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। आशा है पाठकों को पसन्द आयेगी।

आशा है, पाठकों को यह पुस्तक पसन्द आयेगी व सभी विद्वान व राष्ट्रनिष्ठ पाठक इस विषय पर राष्ट्र जागरण हेतु भी यथेष्ट प्रयास करेंगे।

देवशयनी एकादशी वि.स. 2074 भगवती प्रकाश

मंगलवार, जुलाई 4, 2017 bps992@gmail.com

विषय सूची

1. चीनी वस्तुओं से बढ़ती उद्यम बन्दी व बेरोजगारी

2. गंभीर संकट में चीन - ऐसे में भारत क्यों बने तारनहार

3. ''वन बेल्ट वन रोड़'' - भारत की सम्प्रभुता को चुनौति

4. चीन की भारत विरोधी व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियाँ

5. समाधान

विस्तृत सूची

अध्याय - 1

चीनी वस्तुओं से बढ़ती उद्यम बन्दी व बेरोजगारी

- चीन की अनवरत शत्रुता पूर्ण कार्यवाहियां व हमारा बढ़ता व्यापार घाटा
- चीन की भारत को गम्भीर ताजा गीदड़ भभकी -1962 से भी बुरा हाल करेंगे
- चीनी आयातों से देश को गम्भीर आर्थिक क्षति
- चीनी से बढ़ते आयात कई उद्योगों में संकट :
- कुछ प्रमुख उद्योगों पर चीनी आयातों के प्रभाव
    - मशीन टूल्स व भारी उपकरण
    - सौर ऊर्जा उपकरण
    - घरेलू सौर ऊर्जा उपकरण उद्योग के विकास के लाभ
    - एलबल्ब.डी.इ.
    - बस व ट्रकों के टायर
    - औषधि उद्योग
    - खिलौना उद्योग चैपट
    - साइकिल व साइकिल पाट्र्स

- विद्युत उपकरण एवं विद्युत संयंत्र
- कृषि रसायनों में चीन पर बढ़ती निर्भरता घातक
- टैक्सटाइल मशीनरी उद्योग बन्द होने के कगार पर
- स्मार्ट फोन

- देश के अनेक उद्योग संकुल संकट में
  - फिरोजाबाद का शताब्दियों पुराना काँच उद्योग संकुल चैपट
- रणनीतिक तरीके से भारत के विदेश व्यापार पर आघात

1 सूती वस्तु उद्योग पर आघात

2 भारत के नाम से अफ्रीका में नकली दवाओं का निर्यात

छद्म व्यापार

- चीन विरोधी अभियान के सुखद परिणाम
  - चीन अब भी कच्चे माल ही भारत से आयात कर रहा है
  - व्यापार घाटे की समस्या यथावत
  - हम भारतीय बना रहे हैं चीन को आर्थिक महाशक्ति

अध्याय - 2

गंभीर संकट में चीन - ऐसे में भारत क्यों बने तारनहार

- संकट में चीन
- ऋण जाल व मन्दी में फँसी चीनी अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण क्यों ?
- अगला वैश्विक वित्तीय संकट चीन के कारण हो सकता है
- चीन का आर्थिक सशक्तिकरण अनुचित
- चीन को आगे बढ़ाने के स्थान पर हमें आगे बढ़ना होगा
- चीन दक्षिण कोरिया-विवाद से भी सीख लेने की आवश्यकता

अध्याय - 3

''वन बेल्ट वन रोड़'' - भारत की सम्प्रभुता को चुनौति

- चीन की प्रस्तावित सिल्क रूट आधारित वन बेल्ट वन रोड परियोजना भारत के लिये गम्भीर चुनौति होगी
    - देश की सम्प्रभुता व क्षेत्रीय अखण्डता को चुनौति
- भारत को घेरने का भी साधन

- चीन आर्थिक रूप से भी अत्यन्त शक्तिशाली हो जायेगा
    - 1400 अरब डालर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का स्वरूप
- सात देशों की अर्थव्यस्था से चीन जुड़ भी चुका है
- बीसीआईएम के लिये भी चीन का अनुचित दबाव
- OBORको आंशिक टक्कर भारतरूस का ग्रीन का ॅरिडोर देगा।-
- चीन का बढ़ता औपनिवेशिक विस्तार:
    - संसाधनों पर नियंत्रण और आर्थिक, तकनीकी व सामरिक उपनिवेशवाद
- चीन वर्तमान में चार प्रकार के लक्ष्यों पर काम कर रहा है -
    - चीन के औपनिवेशिक विस्तार के समाजशास्त्रीय आयाम
- भूराजनैतिक सन्तुलन की आवश्यकता-
    - पर्यावरण और मानवाधिकार संकट

अध्याय - 4

चीन की भारत विरोधी व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियाँ

(1)घुसपैठ व बार-बार सीमा का अतिक्रमण कर सामरिक घेराबन्दी

1. बॉर्डर पर 60 वर्षों से तनाव एवं बुलडोजर लगाकर अभी जून 2017 में भारत के दो बंकर तोड़ना

चीन का उल्टा मिथ्या आरोप

2. नवम्बर 3 को अरूणाचल में भारतीय सीमा निर्माण में बाधा डालना

3. अरूणाचल में सितम्बर 9, 2016 घुसपैठ

4. जून 10, 2016 को 250 सैनिकों की घुसपैठ

5. मार्च 8, 2016 को फिंगर टप्प्प् - सिरजेप - प् से 5.5 किमी घुसपैठ

6. जुलाई 2016 में उत्तराखण्ड में घुसपैठ

भारत के सीमा क्षेत्र में विकास की आवश्यकता

(2)भारत में आंतकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान व पाक आंतकियों को सर्मथन

1. मौलाना मसूद अजहर के बचाव में भारत के प्रस्ताव पर अनेक बार वीटो

2. लखवी के मामले में वीटो

3. जमात उद दावा, लश्कर ऐ तैयबा व अल अख्तर ट्रस्ट के मामलों में वीटो

भारत का अवमाननाकारक उपहास

(3) पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जल रोकना

(4) आणविक आपूर्ति समूह में विरोध

(5) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विरोध

(6) पाक अधिकृत कश्मीर में सैन्य उपस्थिति व निर्माण

अध्याय - 5

समाधान

स्वदेशी के सन्दर्भ में हमारा स्वरूप व सामर्थ्य: चीन को पीछे छोड़ेंगे हम

विकेन्द्रित नियोजन व समावेशी विकास

चीन के सन्दर्भ मे प्रभावी रीति-नीति आवश्यक

अध्याय - 1

चीनी वस्तुओं से बढ़ती उद्यम बन्दी व बेरोजगारी

चीन की अनवरत शत्रुता पूर्ण कार्यवाहियां व हमारा बढ़ता व्यापार घाटा

चीन में 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के समय से ही चीनी साम्यवादी सरकार भारत के विरूद्ध निरंतर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त रही है। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके लगभग पूरे स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल (41,000 वर्ग किमी.) जितने 38,000 वर्ग किमी. क्षेत्रफल के अक्साई-चिन पर अधिकार कर लिया था, जो आज तक उसी अधिकार में है। इसके साथ ही विगत 10 वर्षों से वह प्रतिवर्ष 150 से 400 बार हमारी सीमा में घुसपैठ करता रहा है और इन्हीं घुसपैठों के माध्यम से इंच दर इंच आगे बढ़ते हुए हमारे कई अत्यंत उर्वरा चारागाह क्षेत्रों व ऊंचाई वाले रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा है। दूसरी और पाकिस्तान के साथ हुये भारत के 1965, 1971 और 1999 के खुले युद्ध में भी चीन पाकिस्तान का समर्थन देता रहा है। चीन की ये भारत विरोधी कार्यवाहियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में भी चीन ने जून 2017 में सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसकर बुलडोजर से सेना के दो बंकर भी तोड़ दिये है। इसी प्रकार चीन द्वारा इन विगत 10 वर्षों में अनेक अवसरों पर भारत द्वारा आतंकवादियों के संबंध में लाये प्रस्तावों का संयुक्त राष्ट्र में विरोध, आणविक आपूर्ति समूह में प्रवेश का विरोध, ब्रह्मपुत्र का जल रोकना व आये दिन की घुसपैठ आदि सभी भारत के विरूद्ध घोर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां हैं। वस्तुतः, चीन में 1949 में साम्यवादी सरकार के बनने के बाद से ही भारत के प्रति वह निरन्तर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा है। आज वह भारत के विरूद्ध आर्थिक, सामरिक, आतंकवादी व कूटनीति प्रेरक द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त हो प्रत्यक्ष व परोक्ष में सब प्रकार से हानि पहुँचाने के कार्य कर रहा है। स्वयं चीन की भारत विरोधी गतिविधियाँ

तो चरम पर हैं ही, वह पाकिस्तान को भी हर प्रकार की भारत विरोधी कार्यवाही के लिये सभी वैध व अवैध तरीकों से सहयोग कर रहा है।

चीन की भारत को गम्भीर ताजा गीदड़ भभकी -1962 से भी बुरा हाल करेंगे

सीमा विवाद पर सिक्किम में सीमा पर जून के उपजे तनाव के बीच भारत के सख्त रूख से चीन बौखला गया है। जुलाई 5, 2017 बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को एडवाइजरी जारी कर सिक्किम के सीमार्द्ध इलाकों से सेना हटाने को कहा है। चीन ने कहा है कि भारत लोगों में यह संदेश देकर भ्रम फैला रहा है कि चीनी सैनिक सिक्किम सेक्टर से सटी सीमा में सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने कहा कि भारत को एक फिर से सबक सिखाने का समय आ गया है। इस बार भारत का 1962 से भी ज्यादा बुरा हाल किया जाएगा। संपादकीय में यहाँ तक लिखा है, 'भारतीय सेना चाहे तो सम्मान के साथ अपनी सीमा में लौट सकती है, वरना चीन के सैनिक उसे खदेड़ देंगे।' अखबार ने कहा है कि यदि विवाद का उचित तरीके से समाधान नहीं तलाशा, तो दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। भारत ने भी कड़ा रूख करते हुये कहा है कि चीनी सैनिक जहाँ पहले थे, वही स्थिति बनी रहे और उन्हें भूटान के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

चीनी आयातों से देश को गम्भीर आर्थिक क्षति

लेकिन, ऐसी सब प्रकार की घोर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त चीन से हम प्रति वर्ष 63 अरब डालर (4.25 लाख करोड़ रूपये तुल्य) मूल्य की वस्तुओं का ज्ञात रूप में एवं बड़ी मात्रा में छद्म रूप में बिना बिल या अल्प मूल्य के बिल पर वस्तुएँ जिनका कुल मूल्य 6 लाख करोड़ रूपयों से भी अधिक है, का आयात कर उसका (चीन का) आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज भारत के 27 देशों के साथ कुल 106 अरब डालर के घाटे में सर्वाधिक 52 अरब डालर का अर्थात लगभग आधा घाटा 2015-16 में केवल चीन से ही अंधाधुंध आयात किये जा रहे उत्पादों के कारण रहा

है। इसी घाटे के कारण रूपये की कीमत जो 2011 में 50 रूपये प्रति डालर थी वह घट कर आज 67 रूपये प्रति डालर ही रह गयी है। यदि हम केवल चीनी वस्तओं का अंधाधुंध आयात नहीं करते, तो भारतीय रूपये की कीमत आज 50 रूपये ही बनी रह सकती थी। और देश में जो कई हजार उद्यम बंद हुये एवं एक करोड़ से अधिक श्रमिक बेरोजगार हुए वे नहीं होते। यदि आज भी हमने सचेत हो कर चीन की वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया तो भविष्य में चीन भारत को हर प्रकार से आहत करता रहेगा और देश के उद्योग, व्यापार व वाणिज्य पर गंभीर व स्थायी दुष्प्रभाव होंगे।

कुछ वर्ष पूर्व ही फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) ने लघु और मध्यम उद्योगों का एक सर्वे किया था। उसमें व्यक्त सम्भावनाओं के अनुसार ही आज देश में व्यापक स्तर पर उद्यम बन्दी के रूप में उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इस सर्वेक्षण में 74 प्रतिशत उद्यमियों ने तब यह कहा कि उनको चीन के उत्पादों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और 62 प्रतिशत ने यह सम्भावना व्यक्त की, कि चीन के सस्ते उत्पादों के कारण सम्भव है कि आने वाले 3-4 वर्षों में हमें किसी भी दिन अपना कारखाना बन्द करना पड़े, क्योंकि चीन के अत्यन्त सस्ते उत्पाद देश में आ रहे है। आज वह सही हो रहा है। अब चाहे वे प्रिन्टिंग मशीनें या अभियान्त्रिकी के व इलेक्ट्रानिक उत्पाद हों या कोई रसायन व औषधियाँ हो, लगभग सभी प्रकार के चीनी उत्पाद इतने सस्ते आ रहे हैं कि एक-एक कर देश के कारखाने बन्द हो रहे हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश हम संभवतः चीन को यह सोच कर अधिकाधिक व्यापारिक सुविधाएँ दे रहे हैं कि अगर हम उदार व्यापारिक सुविधाएँ देते चलेंगे तो वह सीमा पर थोड़ा कम दबाव बनायेगा, तो यह एक दिवा स्वप्न है। वहीं देश के उद्यमियों ने जो सम्भावना व्यक्त की, वह आज सही सिद्ध हो रही है। देश के अनेक उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गये हैं। बिजली, इलेक्ट्रानिक्स व कई रसायनों के उद्योग देश में बन्द हो गए है। देश का रसायन उद्योग व दवा उद्योग भी चीनी स्पर्द्धा से समाप्त होता जा रहा है। देश में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के बंद होते चले जाने से छात्रों ने इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में तो प्रवेश लेना ही कम कर दिया है। चीनी लीनोवो कम्प्यूटर ही आज

देश में सर्वाधिक बिकता है। इससे देश की जो मात्र 2 कम्प्यूटर हार्डवेअर बनाने वाली इकाईयाँ थीं, वे भी बन्द हो गयीं।

देश में आज चीन के सौर ऊर्जा उपकरण, एल.ई.डी. बल्ब, दूरसंचार उपकरण, विविध इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक साज-सामानों, रसायनों, औषधियों आदि उच्च प्रौद्योगिकी जन्य उत्पादों के ही नहीं जूते, फर्नीचर, वस्त्र, सेरेमिक उत्पाद, साइकिलें आदि आम उपभोक्ता उत्पादों तक के आयात बेलगाम बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्तमान में भारत के ये आयात तो विकट आर्थिक मन्दी से जूझ रहे चीनी उद्योगों व चीनी अर्थव्यवस्था के लिये जीवन रेखा सिद्ध हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन से बढ़ते आयातों से देश में उद्योग व रोजगार दोनों चैपट हो रहे हैं। ये बे लगाम बढ़ते आयात देश में औद्योगिक रुग्णता, उद्यम बन्दी, बैंकों के अधिकाधिक ऋणों के डूबने व बैंकों की निरन्तर बढ़ रही अनिष्पादनीय आस्तियों (नॉन परफार्मिंग एसेट्स) का प्रमुख कारण सिद्ध हो रहे हैं। आज देश में नये निवेश व रोजगार सृजन में भी ये बढ़ते चीनी आयात सबसे बड़ी बाधा बने हुये हैं। चीन द्वारा इन उत्पादों की अपनी घरेलू कीमतों की तुलना में अल्प मूल्य पर भारत में बेचने अर्थात राशि पतन (डम्प) करने के लिये, इन पर दिये जा रहे भारी सरकारी अनुदान को देखते हुये भारत द्वारा इन चीनी उत्पादों पर सुरक्षात्मक प्रशुल्क (सेफगार्ड ड्यूटी), समतुल्यकारी प्रशुल्क (काउण्टरवेलिंग ड्यूटी) एवं राशिपतन रोधी प्रशुल्क (एण्टी डम्पिंग ड्यूटी) लगा कर देश में उद्योगों व रोजगार को संरक्षण दिया जाना परम आवश्यक है। वर्ष 2013 में सोलर उपकरणों की डम्पिंग के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के अन्वेषणों में डम्पिंग के स्पष्ट प्रमाणों के बाद भी चीनी सौर पेनलों पर एण्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाने की अधिसूचना जारी नहीं होने से घरेलू सौर उपकरण उद्योगों को भारी संकट झेलने पड़ रहे हैं और दूसरी ओर चीनी उद्यमों को फलने फूलने के भारी अवसर मिल रहे हैं। देश में धारणक्षम ऊर्जा के विकास के नाम पर किये जा रहे इस सारे निवेश का लाभ आज देश के उद्योगों के स्थान पर चीन को मिल रहा है। अमेरिका, यूरोप आदि सभी देशों ने अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने हेतु चीनी सौर पेनल आदि पर 238 प्रतिशत तक की भी एण्टी डम्पिंग ड्यूटी लगायी है। आज देश में इन उत्पादों की ऊंची मांग व उपभोग के दौर में

भी घरेलू उद्यमों को विकास का अवसर नहीं मिला तो इन उद्यमों की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में होने वाले कई गुने मूल्य संवर्द्धन व उसकी प्रौद्योगिकी के विकास से देश स्थायी रूप से वंचित रह जायेगा। जबकि, इन सभी क्षेत्रों में देश के उद्योग न्यूनाधिक रूप में अपनी उपस्थिति भी बनाये हुये हैं और आवश्यकता बस उन्हें वांछित संरक्षण व समर्थन दिये जाने की है। केवल सौर पेनल आयात में ही देश से 42 अरब डालर (2.77 लाख करोड़ रुपये) की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय होगी। दूसरी ओर देश में ही इनके उत्पादन की दशा में सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में इस राशि से कई गुना कारोबार व उत्पादन वृद्धि हो सकेगी। सौर उपकरणों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। विश्व के 27 देशों से हमारे व्यापार घाटे में चीन से हमें सर्वाधिक 52 अरब डालर का व्यापार घाटा हो रहा है। विदेश व्यापार में घाटे के कारण ही रूपये की विनिमय दर या मूल्य में गिरावट आती है। वर्ष 2011 में एक अमेरिकी डालर बराबर 50 रुपये होते थे, आज अब 66 रुपये बराबर एक डालर हो गया है। अब उस घाटे के समाधान के रूप में चीन को भारत में पूंजी निवेश कर, यहीं उत्पादन करने का जो निमंत्रण दिया जा रहा है वह संकटों को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। आयात व्यापार पर तो फिर भी अंकुश लगाया जा सकता है। निवेश को लौटाना संभव नहीं होता है। दूसरी ओर भारत के में अपने निवेश पर वे भारी मात्रा में लाभ देश से बाहर ले जायेंगे व लाभों का पुनर्निवेश भी करेंगे। मध्यमावधि में यह लाभों का बहिर्गमन कहीं अधिक होगा। यहां चीन से हमारे कुछ प्रमुख आयातों की चर्चा भी आवश्यक है।

चीनी से बढ़ते आयात कई उद्योगों में संकट :

आज चीनी आयातों से देश के अनेक उद्योगों पर भारी संकट के बादल छाये हुये हैं। इससे उद्यम बन्दी, बेरोजगारी, बैंक ऋणों को डूबना आदि अनेक आर्थिक संकट बढ़ रहे हैं। विश्व के सकल विनिर्माणी उत्पादन अर्थात वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में आज भारत का अंश मात्र 2.1 प्रतिशत है जबकि चीन का अंश 22.6 प्रतिशत है। वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में चीन ने अमेरिका को भी 17.2 प्रतिशत अंश के साथ दूसरे स्थान पर

धकेल दिया है। हम यदि चीनी ब्राण्ड ही खरीदते चले जायेंगे तो वर्ल्ड मेन्युफेक्चरिंग में हमारा अंश और घट कर सर्वथा हास्यास्पद स्तर पर चला जायेगा।

चीन से बढ़ते आयातों से देश के पूरे के पूरे उद्योग वर्ग एक-एक कर चैपट हो रहे हैं। इनकी सूची ही इतनी बड़ी है, जिससे लगता है कि कुछ गिने चुने उद्योग ही होंगे जो चीनी आयातों से प्रभावित नहीं हुये हैं। चीनी आयातों से बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित कुछ उद्योगों की निम्न सूची से ही अनुमान हो जायेगा कि इनसे देश का छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा सभी प्रकार के उद्योग चैपट हो रहे हैं।

तालिका चीनी आयातों से चोपट होते कुछ उद्योग

- हाई टेन्शन इन्सुलेटर्स उद्योग
- साइकिल व साइकिल पाटर्स उद्योग
- पी वी सी व प्लास्टिक सूटकेस उद्योग
- बिजली संयंत्र व बायलर उद्योग
- ग्लास शीट व काँच के साजसामानों के उद्योग-
- मोबाइल फोन और सहायक उपकरण सहित टेलीफोन उपकरण इंडस्ट्रीयल चेंस
- मिक्सर एण्ड ग्राइण्डर्स
- आटो एंसीलरी और पाट्र्स उद्योग
- पैकेजिंग मशीनरी उद्योग
- सीकास्टिंग्स .आई.
- रंग व रसायन उद्योग
- मेग्नेट उद्योग
- इलेक्ट्रीक वेल्डिंग मशीन उद्योग
- फाइबर आप्टिक केबल उद्योग
- पेन व स्टेशनरी उद्योग

- काँच के सजावटी सामानों का उद्योग
- सेरेमिक उद्योग
- चमड़ा उत्पाद उद्योग
- मशीन टूल उद्योग
- हेण्ड टूल उद्योग
- सौर ऊर्जा उपकरण उद्योग
- कम्प्यूटर व कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग
- बायोमेडिकल उपकरण उद्योग-   प्लाईवुड उद्योग
- इलेक्ट्रानिक उद्योग
- टिन कंटेनर्स उद्योग
- स्पात उद्योग
- इंडस्ट्रियल चेंस (चेन उद्योग)
- एयर एण्ड गैस कंप्रेसर्स उद्योग
- टैक्सटाईल मशीनरी उद्योग
- एल्युमीनियम शीट्स प्लेट्स/
- एग्रीकल्चर मशीनरी उद्योग
- कंस्ट्रक्शन मशीनउपकरण उद्योग/
- इंडस्ट्रियल ब्लोवर
- इस्पात संरचना उद्योग
- खाद्य संसाधन मशीनरी
- हास पाइप
- प्लास्टिक एवं मशीनरी, माउल्डिंग मशीनरी सहित
- एंटीबायोटिक्स और इसकी इनग्रेडिएण्ट्स
- क्राकरी उद्योग
- फर्नीचर उद्योग

- प्रिण्टिंग मशीन उद्योग
- थोक दवा उत्पादन उद्योग
- पावर ग्रिड
- डीजल पम्प उद्योग
- कम्बल उद्योग
- वस्त्र उद्योग
- हस्तकला (हेण्डीक्राफ्ट उद्योग)
- कृषि रसायन उद्योग

कुछ प्रमुख उद्योगों पर चीनी आयातों के प्रभाव

मशीन टूल्स व भारी उपकरण: मशीन टूल्स व भारी उपकरणों में जहाँ हम उदारीकरण के पूर्व एक बड़ी सीमा तक स्वावलम्बी थे। वहीं इनमें हम आज बड़ी सीमा तक चीन व अन्य देशों से आयातों पर निर्भर होते जा रहे हैं। कई उद्योगों में हम 80 प्रतिशत या 100 प्रतिशत तक भी आयातों पर निर्भर होते जा रहे हैं। मशीन टूल्स व भारी उपकरण में हमारा विदेशों एवं चीन से आयातों का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। आज 1.5 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के मशीन टूल व औद्योगिक उपकरण आदि हम आयात कर रहे है। इससे हमारा सुविकसित घरेलू मशीन टूल सेक्टर विनष्ट हो रहा है। चीन से लगभग 30,000 करोड़ के मशीन टूल व उपकरण 2014-15 में आये थे। 2016-17 में ये आयात 41,000 करोड़ रूपये के हो गये। देश का घरेलू मशीन टूल सेक्टर एक बार विलोपित हो जायेगा, उसके बाद उसे पुनः विकसित करना कठिन हो जायेगा। हाल ही में पिछले वर्ष मशीन टूल आयातों के सम्बन्ध में भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री जी.एम. सिद्धेश्वर का राज्य सभा में दिया लिखित उत्तर यहाँ उद्धृत किये जाने योग्य है:

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises

10-March-2016 17:55 IST

Machine tools and equipments being imported

A number of Indian users of Capital Goods are importing Heavy Industrial Equipment like Electrical Equipment, Machine Tools, Textile Machinery, Printing Machinery, Plastic Processing Machinery, Metallurgical Machinery, Earthmoving & Construction Machinery, etc. from China.

The details of import for the last year (2014-15) from China are as under:

SI. No.	Item	2014-15 China Import (Rs. Crore)	2014-15 Total Import (Rs. Crore)	China import Percentage on total import during 2014-15 (%)
1	Boiler, Turbine, Generator & Transformer	6297.96	16430.92	38.33
2	Construction and Mining machinery	6192.17	24245.9	25.54
3	Textile machinery	3698	10912.98	33.89
4	Printing Machinery	3167.39	7653.18	41.39
5	Machine Tool	1982.58	12218.18	16.23
6	Process Plant Equipment and Machinery including pumps & compressors	1772.62	7225.89	24.52
7	Metallurgical Machinery	1314.96	4567.81	28.78
8	Plastic Machinery	1029.14	4206.45	28.78
9	Paper and Pulp Machinery	552.57	1834.64	30.12
10	Agriculture Machinery	298.32	806.19	37
11	Leather Machinery	161.38	623.08	25.9

(Source: Department of Commerce website).

This information was given by Minister of State in the Ministry Heavy Industries and Public Enterprises, Shri G.M. Siddeshwara in a written reply in Rajya Sabha today.

सौर ऊर्जा उपकरण: देश में एक वर्ष में ही वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में, सौर ऊर्जा सेल व माड्यूल का आयात तीन गुना हुआ है। आयातित सौर ऊर्जा माड्यूल में आज 88 प्रतिशत चीन से आ रहे हैं, जो 2014-15 में 73 प्रतिशत ही थे एवं अब दूसरा स्थान मलेशिया का है। देश में सौर ऊर्जा उपकरणों का आयात प्रति वर्ष 40-45 प्रतिशत बढ़ रहा है और दिसम्बर 2016 में तो विगत 2015 के दिसम्बर की तुलना में सौर आयात 74 प्रतिशत से बढ़ कर पौने दो गुने हो गये हैं। केवल भारतीय घरेलू सौर उपकरण उद्योग को चैपट करने के उद्देश्य से वह भारत में इनका निर्यात

0.40 अमेरिकी डालर प्रति वाट की दर से कर रहा है, जबकि उसकी बेलेन्स शीट लागत उससे 27 प्रतिशत अधिक, 0.51 डालर प्रतिवाट है। यही स्थिति रही तो हम स्थायी रूप से चीन पर अवलम्बित हो जायेंगे। आज जापान की घरेलू लागत 0.65 डालर प्रतिवाट होने पर भी वह घरेलू पेनल का ही उपयोग कर रहा है। अब बाजार पर चीनी पकड़ के कारण भारतीय उद्यम भी, चीनी कम्पनियों से भागीदारी तक के लिये बाध्य हो रहे हैं।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने विगत 10-15 वर्षों में 15-20 हजार करोड़ रूपयों का निवेश किया है। पूर्व में हम अपने उत्पादन का 70 प्रतिशत तक निर्यात भी करते रहे हैं। लेकिन, आज चीनी कम्पनियों द्वारा हमारे उद्यमों को रूग्ण करने के लिये अपनी लागत से अल्प मूल्य पर जो भारी मात्रा में राशि पतन अर्थात डम्पिंग की जा रही है। उससे देश के अधिकांश घरेलू सौर ऊर्जा उद्यम रूग्ण हो कर बन्द होने को हैं। अमेरिका तक ने चीनी सौर ऊर्जा उपकरणों पर 238 प्रतिशत तक की एण्टी डम्पिंग ड्यूटी तक लगायी है। भारत द्वारा ऐसा नहीं करने से हमारे देश में सौर ऊर्जा उपकरणों के उत्पादन सम्बन्धी उद्योग विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसके विपरीत जो स्थापित उद्योग थे वे भी रूग्ण हो रहे हैं।

दूसरी ओर सोलर पार्क लगाने के जो ठेके चीनी कम्पनियों को जा रहे हैं, वे यहाँ से अनवरत पैसा देश से बाहर ले जायेगी। उदाहरणतः मध्यप्रदेश में एक सोलर पार्क का जो काम चीनी कम्पनी हेरोन को गया है। वहाँ उसे पौने सात रूपये प्रति kwh दर मिलेगी। इसमें कुछ व्यय जो स्थानीय स्तर पर होगा उसे छोड़ सारी राशि वर्षों तक वह इस देश से ले जायेंगी। हमारी एक पीढ़ी यह विदेशी कम्पनियों द्वारा लगाये सोलर पार्कों का भुगतान करेगी, जो पैसा देश से बाहर जायेगा। आज सौर ऊर्जा की लागत 3रूपये प्रति kwh के आस-पास आ गयी है। यही 2014 में हमने 6.45 रूपये तक स्वीकृत की है।

आज यदि देश में हमें सौर ऊर्जा के लिये सिलिकांन उत्पादन, सिलिकोन की पतली वेफर बनाने, उनसे फोटो वाल्टाइक सेल, माड्यूल व पेनल बनाने तक की

सम्पूर्ण निम्नवर्ती मूल्य श्रृंखला में उत्पादन प्रोत्साहन व प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन देकर भी देश में इस उद्योग का विकास करना पड़े तब भी करना चाहिये। आगामी पूरे एक दशक में यह विश्व भर में एक उदीयमान उद्योग बना रहेगा। हम देश-विदेश में बड़ा काम कर सकेंगे।

घरेलू सौर ऊर्जा उपकरण उद्योग के विकास के लाभ - भारत यदि चीन से आयातों के स्थान पर देश में सौर ऊर्जा उपकरण उत्पादन को संरक्षण व समर्थन दे तो वैश्विक परामर्श संस्थान के.पी.एम.जी. के 2015 के एक प्रतिवेदन के अनुसार देश 2030 तक 42 अरब डालर (2.8 लाख करोड़ रूपये) की विदेशी मुद्रा बचा कर 1.75 लाख रोजगारों (50000 प्रत्यक्ष व 1.25 लाख परोक्ष) का सृजन कर सकता है। प्रतिवेदन के अनुसार आज सस्ते चीनी आयातों से 40 प्रतिशत भारतीय सौर ऊर्जा उत्पादकों को अपने उद्यम बन्द करने पड़े हैं। के.पी.एम.जी. के उक्त अध्ययन की अवधि में बचे हुये घरेलू उत्पादक भी अपनी क्षमता का 21 प्रतिशत उपयोग ही कर पा रहे थे।

आज हम यदि सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन के क्षेत्र में ‘मेड बाई भारत‘ के लक्ष्य के साथ अपने स्वदेशी उद्यमों का समर्थन नहीं करेंगे, विदेशी निवेशकों को देश में उत्पादन का ही आमंत्रण देते रहेंगे और आयातों को नियन्त्रित नहीं करेंगे, तो विदेशी निवेशक व अपने देश के भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर्ता बाहर से साज सामान लाकर हमें पूरी तरह से पुर्जे जोड़ने वाले या ऐसेम्बली लाइनों वाले देश (Assembling country) में रख देंगे और सारा लाभ विदेशी उत्पादक उठायेंगे, प्रौद्योगिकी उनकी विकसित होगी। आज एक पावर प्लांट या किसी स्मार्ट सिटी के लिये साज सामान या बुलेट ट्रेन या अन्य भी रेलों का साज सामान चीन या जापान से आता है, तो हमारा धन विदेशों में जायेगा। वस्तुतः उस ऊर्जा संयंत्र, स्मार्ट शहर या रेल को बनाने में उसकी लागत के 10-20 गुने तक राशि का जो कारोबार, सहायक उद्योग व कम्पोनेण्ट के विकास से सेक्टर विकसित होता है। वह अपने देश में नहीं हो सकेगा। इन सबका उत्पादन व विकास देश में होने से जो रोजगार व सहायक उद्योगों का विकास देश में हो सकता है, वह यहाँ नहीं हो सकेगा। अगर हमारे पावर प्लांट हम देश में नहीं बना रहे हैं तो देश में संबंधित सहायक उद्योग व उनका कम्पानेण्ट सेक्टर, उस कम्पोनेण्ट सेक्टर में

विकसित होने वाले रोजगार और उनके धन के बहुत सारे हाथों में क्रमिक हस्तान्तरण से होने वाली उसकी दस पन्द्रह गुनी गुणकीय आय के लाभ से भी हम वंचित रह जायेंगे। एक पावर प्लांट देश की टाटा सोलर या महर्षि सोलर अथवा भेल (BHEL) या एल. एण्ड टी. (L & T) या अन्य किसी भारतीय कम्पनी में बनता है तो उनको जो कम्पोनेन्ट आपूर्ति करने वाली कम्पनियाँ है, जिनको हम सहायक उद्योग कहते हैं उनको भी बड़ी मात्रा में काम मिलता है। इसलिये सौर ऊर्जा संयंत्र देश में बनने से हजारों छोटे-बड़े सहायक उद्योग पनपेंगे। उदाहरणार्थ यदि एक पॉवर प्लाण्ट को कोई ताम्बे के तार (enamelled wire) चाहिये, तो काइल बनाने वाली कम्पनी का काम मिलेगा। पुनः उस काइल का बनाने में एनामल्ड वायर (enamelled wire) चाहिए, तो वायर एनामलिंग करने वाली कम्पनियाँ को काम मिलेगा। जब वायर एनामलिंग वाली कम्पनी उसके लिये कॉपर वायर खरीदेगी, तो वायर ड्राइंग मशीन वाली कम्पनियों को काम मिलेगा। इस प्रकार ये संयंत्र देश में बनने पर 1000-1200 सहायक उद्योगों का कम्पोनेन्ट सेक्टर खड़ा होगा। उसके कारण इस प्रकार के मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से देश में ही पावर प्लाण्ट उद्योग के सहायक उद्योगों का जाल अर्थात् उसके कम्पोनेन्ट सेक्टर में 1000-1200 सहायक उद्योग विकसित होते है और चलते हैं, उससे मूल उद्योग का भी 7-8 गुणा रोजगार सृजित होता है और 8-10 गुना कारोबार विस्तार होता है। इससे लोगों की आय बढ़ती है, जिससे सभी प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों की मांग व उत्पादन बढ़ता है। इससे वृद्धि दर तेजी से बढ़ती है व बढ़ती ही जाती है। मध्यमवर्ती कम्पोनण्ट बनाने वाली कम्पनियों के कर्मचारियों को जो वेतन प्राप्त होता है। उससे अन्य सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, उससे पुनः समपार्श्विक उद्योगों (Callateral Industries) में उत्पादन, निवेश व रोजगार बढ़ता है। इससे अनवरत विकास का चक्र प्रारम्भ होता हैं।

इसे समझाने के लिये मैं बिल्कुल एक गाँव का उदाहरण लेता हूँ उससे कम्पोनेन्ट सेक्टर में गुणन प्रभाव से रोजगार व कारोबार विस्तार और सरलता से समझ में आ जायेगा। यथा, यदि किसी गाँव या कस्बे में किसी व्यक्ति ने 200 रुपये का जूता वहाँ के मोची से खरीदा तो 100-100 रुपये के दो नोट उस मोची की जेब में चले जायेंगे, उस

मोची ने गाँव के लोहार से जूता बनाने का औजार 200 रूपये का खरीदा तो वे ही 100-100 रुपये के दो नोट उस लोहार के पास चले जाते है। लोहार अगर दर्जी से 200 रुपये के कपड़े सिलवाता है तो वे ही 100-100 के दो नोट उसके पास चले जाते हैं और दर्जी अगर वहाँ के किसान से 200 रूपये के कृषि उत्पाद खरीदता है तो वे 100-100 रूपये के दो नोट उसके पास चले जाते हैं। ऐसे यदि उस कस्बे, तहसील, तालुका या गाँव में वह 100-100 रुपये के दो नोट पचास लोगों के बीच में घूम जाते हैं तो (200 गुणा 50 की दर से) वहाँ उस कस्बे में 10,000 रुपये की आय सृजित होती है दूसरी ओर अगर हमने वही जूता स्थानीय मोची के स्थान पर बाटा का जूता पहन लिया तो बाटा इण्डिया लिमिटेड, इंग्लैण्ड की कम्पनी है और वे 200 रुपये जब इंग्लैण्ड चले जायेंगे या उनका लाभ इंग्लैण्ड चले गये तो एक प्रकार से वह मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से 200 रुपये से उस तहसील में 10,000 रुपये की आय और 50 लोगों को योगक्षेम मिल सकता था वह 200 रूपये की राशि या उसका एक भाग देश से बाहर चला जायेगा। इसी क्रम में अगर देश में थर्मल या सोलर पावर प्लांट चीनी, अमरीकी या जर्मन कम्पनियाँ सप्लाई करती है तो इनका कम्पोनेन्ट सेक्टर उन्हीं देशों में विकसित होगा। वहीं प्रौद्योगिकी व रोजगार का विकास होगा आय वृद्धि होगी, निवेश बढ़ेगा आर्थिक वृद्धि होगी यदि रूपये 1000 करोड़ के पावरप्लांट के आर्डर किसी भारतीय उत्पादक के पास है और वह कम्पोनेन्ट की सोर्सिंग (अर्थात हिस्से पुर्जों की खरीददारी) अगर अपने देश से करता हैं तो मेड बाई इण्डिया के गुणन (Multiplier) प्रभाव से कम से कम 20 हजार करोड़ रूपये तक का निम्नवर्ती मूल्य श्रृंखला (डाउन दि लाइन वेल्यू चेन) में रोजगार व कारोबार विस्तार होता है। कोषों का प्रवाह या फ्लो आफ फण्ड नीचे तक जाता हैं और सोलर सहित विविध पावर प्लांट व रेल्वे के साज सामान आदि बाहर से आ जाते है, तो वह लाभ उन देशों को जाता है। यदि चीनी व अन्य विदेशी कम्पनियों को विदेशी निवेश के लिये निमंत्रण देकर बुलाया जाता है तो वे सारा साज सामान बाहर से लाकर, हिस्से पुर्जे जोड़ने का काम करेंगी। सौर ऊर्जा का काम भी विदेशी कम्पनियों को दिया तो यही होगा। थर्मल पावर प्लाण्ट की दशा में भी यही हुआ है। विदेशी निवेश व आयातों से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से भी यही होगा।

आज देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छोटे-छोटे स्टार्ट अप से लेकर टाटा सोलर जैसे 5000 करोड़ रूपये वार्षिक कारोबार वाले सभी प्रकार के अनगिनत उपक्रम हैं। सभी प्रकार के इनके मध्यवर्ती आदाय (Intermedicate inpurts) उत्पादन करने वाले उद्यम और भी बड़ी संख्या में है। यदि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की आपूर्ति के आदेश भारतीय उत्पादकों को मिलेंगे तो इन हजारों स्थानीय उद्यमों का विकास होगा, उनका उत्पादन बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी समुन्नत होगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी उससे अन्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न होगी, वहाँ भी उत्पादन बढ़ेगा, निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा और देश आर्थिक वृद्धि व विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।

इसके विपरीत आज जिस प्रकार बड़ी संख्या में इन सौर ऊर्जा संयंत्रों का अधिकांश काम या तो विदेशी निवेशकों को या विदेशों से आयातित साज सामान लाकर उन्हें यहाँ स्थापित कर देने वाले उद्यमों को जा रहा है। उससे देश में उपरोक्त प्रकार से होने वाले विकास व वृद्धि के क्रम से हम सदा के लिये वंचित रह जायेंगे। अधिकांश काम सौर ऊर्जा संयंत्रों के मूल उत्पादकों (original equipment manufactures) को या स्थानीय साज सामान का उपयोग करने की शर्त पर दिया जाना चाहिये। इसमें विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स सम्बन्धी समझौते की बाधा आने पर सीधे-सीधे स्थानीय पुर्जों की शर्त लगाने के स्थान पर संयंत्र स्थापना का आदेश देते समय आदाय आपूर्तिकर्ताओं (component suppliers) को चिन्हित कराया जा सकता है। वस्तुतः विदेशी आपूर्तिकर्ताओं या विदेशी आयातित अदायों के उपयोगकर्ता कम्पनियों को ये आदेश जाने पर वे यहाँ पर केवल पावर प्लांट या अन्य वस्तुओं को एसेम्बल मात्र करेंगे। पिछले 23 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में यही हुआ है।

हम हम चीनी व विदेशी सौर ऊर्जा संयंत्रों के साज सामानों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे, तो हमारी कीमत पर उनकी प्रौद्योगिकी समुन्नत होगी, उनका उत्पादन व रोजगार बढ़ेगा, आय का सृजन वहाँ होगा, उससे मांग का सृजन वहीं होने से पुनः निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय व मांग का सृजन भी वहीं होगा। हम तो उससे विदेशी मुद्रा संकट, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, पूंजी के अभाव एवं नये निवेश के अभाव में त्रस्त

होंगे। विदेशी निवेश से लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर विद्युत की विक्रय प्रत्याय (Sales Revenue) के रूप में वर्षों तक देश का धन विदेश जायेगा। ऐसा होने पर हम देश को आर्थिक संकट व तकनीकी पिछड़ेपन से नहीं उबार पायेंगे और अपनी भावी पीढ़ी को आसन्न बेरोजगारी, आर्थिक अराजकता व परावलम्बन से बचा ही नहीं पायेंगे। इसलिये सौर ऊर्जा सहित उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें 'मेड बाई इण्डिया' के स्वदेशी के अभियान को ही आगे बढ़ाना होगा।

एल.इ.डी.बल्ब- ऐसी ही स्थिति एल.ई.डी. बल्ब में भी आयातों पर निर्भरता की है। एल.ई.डी. के क्षेत्र में 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्द्धन संभव है। आज देश इतनी भारी मात्रा में इन बल्बों का आयात करके घरेलू उद्योग के विकास का अवसर ही स्थायी रूप से खो रहा है। देश में बजाज, अजन्ता, विप्रो, एवरेडी, मोजर बेअर आदि 25 एल.ई.डी. बल्ब निर्माता हैं। सरकार के 'मेक इन इण्डिया' अभियान में सूचीबद्ध उद्योगों में विद्युतीय उपकरण व उत्पाद भी सम्मिलित हैं। तथापि, ऐसे भी समाचार प्रकाशित हुये है कि पिछले वर्ष ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समूह ने दो करोड़ एल.ई.डी. बल्ब चीन से उत्पादित करा (आयात कर) सरकार को आपूर्ति का आदेश फिलिप्स कम्पनी को दे दिया था। स्वदेशी उद्योगों को यह क्रय आदेश दिया जाता तो देश में यह प्रौद्योगिकी विकसित होती, देश के उद्यम विकसित होते और देश का धन भी बचता। आपूर्ति के आदेश में उन्हें चीन में बनवाने का लिखने का कोई औचित्य नहीं था। कम्प्यूटर हार्डवेयर में भी क्रय समर्थन नहीं मिलने से विप्रो व जेनिथ जैसे घरेलू उद्यमों के बंद हो जाने से पर्सनल कम्प्यूटर के क्षेत्र में हम पूर्णतः विदेशों पर निर्भर हो गये हैं। अतएव अब देश में सर्वाधिक बिकने वाला पी.सी. चीनी लीनोवो ही हो गया है। यदि हम सावधानी पूर्वक चीनी व अन्य विदेशी ब्राण्ड के एल.ई.डी. बल्ब खरीदना बन्द कर भारतीय ब्राण्डों को ही क्रय करेंगे तो देश में इनकी प्रौद्योगिकी उन्नत होगी, हम उनका अधिक मितव्ययता पूर्वक उत्पादन कर सकेंगे। ऐसा होने पर देश-विदेश में भारतीय ब्राण्डों की बिक्री बढ़ेगी और बल्ब के काँच के खोल, सर्किट आदि पूर्जे भी भारत में बनेंगे। अन्यथा बल्ब के सारे भारतीय उद्यम बन्द हो जाने पर तो हम बल्ब जैसे साधारण उत्पाद में भी पराश्रित हो जायेंगे। आज

बिजली की सजावटी लड़ो जैसे अतिसाधारण उत्पाद में ही हम चीन पर आश्रित हो गये हैं। पूरे देश में छोटी सजावटी लड़ों के छोटे-बड़े 40,000 उद्यम थे। इनमें से एक भी नहीं बचा है, और हम चाह कर भी एक भी स्वदेशी सजावटी लड़ बाजार में नहीं पाते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर सौर ऊर्जा उपकरण, एल.ई.डी. बल्ब आदि के आयात में इतनी बड़ी राशि चीन के हाथों में सौंप कर उसके विकास व आर्थिक सशक्तिकरण में लगाने के स्थान पर भारत एक बार भू-गर्भिक कोयला गैसीकरण (अण्डरग्राउण्ड कोल गैसीफिकेशन) की ओर आगे बढ़ सकता है। कोयले के गैसीकरण भू-गर्भिक से भी हम अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। देश में 300 खरब टन कोयले के भण्डार हैं। आज देश के ताप विद्युत ग्रहों में 75 करोड़ टन वार्षिक कोयले का उपयोग होता है। भूगर्भ में कोयले को गैस में रूपान्तरण करके, अल्प कोयले के दहन से अपेक्षाकृत अधिक व स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। देश सौर उपकरण उद्योगों का विकास होने तक यह किया जा सकता है। इसी बीच हम यदि पूंजी अनुदान या सरकारी इक्वीटी व अन्य प्रकार से प्रोत्साहन देकर देश में सिलिकान इनगाट उत्पादन व वेफर निर्माण प्रारम्भ कर दें तो चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। रेत को 1000 डिग्री तापमान पर ले जाकर सिलिकान निर्माण व उसकी पतली वेफर बना कर फोटोवोल्टाइक सेल व पेनल बनाये जा सकते हैं। सौर पेनल के साथ ऊर्जा संग्रहण हेतु सौर तंत्र हेतु आवश्यक इनवर्टर के लिये घरेलू प्रौद्योगिकी विकासार्थ भी सरकार को उद्योगों को समर्थन देना होगा। प्रौद्योगिकी विकासार्थ उदार शासकीय सहयोग से स्पर्द्धा-पूर्व अनुसन्धानों (Precompetitive Research) के लिये देश में 'विशिष्ट उद्योग सहायता संघ' (इण्डस्ट्री कन्सोर्टियम) भी विकसित करने होंगे। यूरोप, अमेरिका, जापान, ताईवान, मलेशिया आदि में प्रौद्योगिकी, विकासार्थ ऐसे अनेक उद्योग सापेक्ष-उद्योग सहायता संघ है। अमेरिका में सुपर कम्प्यूटर व नेनो टेक्नोलोजी से ले कर जैव प्रौद्योगिकी एप्पल फोन व इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों तक सभी उत्कृष्ट उत्पादों में शासकीय व्यय से सम्पोषित, उद्योग सहायता संघों का सर्वोच्च योगदान रहा है। अमेरिकी अर्थशास्त्री मेरियाना मेज्जुकेटो ने उनकी पुस्तक ''दी एण्टरप्रिन्यरिअल स्टेट: डी

बंकिंग प्राइवेट वर्सस पब्लिक सेक्टर मिथ्स'' में यही सब बताया है कि अमेरिकी निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी व उत्पादों का विकास, किस प्रकार 90 प्रतिशत तक उद्योग सहायता संघों को प्रदत्त शासकीय सहायता से हुआ है।

बस व ट्रकों के टायर:- टायरों के चीन से बढ़ते आयातों से देश में टायर उत्पादन का सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ही छिन्न-भिन्न होता जा रहा है। टायरों के चीन से बढ़ते आयात के साथ ही देश में रबर उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। देश में 2009 में 82 लाख टन रबर उत्पादन होता था, वह घटकर आज 50 लाख टन से भी कम रह गया है। देश में 2013-14 में मात्र 40,000 रेडियल टायर प्रतिमाह चीन से आते थे। 2007 के पूर्व यह संख्या शून्य थी। वही संख्या अब 1.35 लाख टायर प्रतिमाह से भी ऊपर पहुंच गई है। चीनी टायर बिना वारंटी के होते हैं इससे वाहन दुर्घटना दर भी बढ़ती है, जान-माल का नुकसान होता है, बीमा दावों में वृद्धि होती है और कई परिवार अनाथ हो जाते हैं। टायर उत्पादन में 70 प्रतिशत रबर का उपयोग होता है। टायर उत्पादन में गिरावट के उपरांत भी टायर आयात पर मात्र 10 प्रतिशत आयात शुल्क है जो कुछ समझौतों के अधीन 0 से 5 प्रतिशत तक ही रह जाता है। दूसरी ओर रबर आयात पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क है। इससे देश में टायर उत्पादन के स्थान पर आयातों को बढ़ावा मिलता है। देश का टायर उद्योग इससे रूग्ण हो रहा है। एक बार तो टायर आयात 1.5 लाख टायर प्रतिमाह से भी ऊपर निकल गया था। लेकिन नोट बन्दी से कुछ कम हुआ था। इनमें कर चोरी आदि की चलन अधिक होने से इनका क्रय-विक्रय रोकड़ भुगतान से अधिक होता रहा है। इसलिये यह घटकर 1.35 लाख टायर प्रतिमाह रह गया।

आज देश में विगत 2-3 वर्षों में टायर उद्यमियों ने लगभग 35,000-40,000 करोड़ रूपयों का नया निवेश किया है। यदि देश में ये बस व ट्रक के टायर चीन से ही आयात होते रहे तो देश के रूग्ण हो रहे टायर उद्यम धीरे-धीरे बन्द होते जायेंगे, उनमें भारी मात्रा में बैंकों के ऋण डूब जायेंगे। देश में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारी टायर निर्माण की प्रौद्योगिकी विलोपित हो जायेगी। टायर उत्पादन में लगने वाले नायलान टायर आदि के उद्यम भी बन्द होंगे।

औषधि उद्योग:- औषधि उद्योग में भी घरेलू औषधि उत्पादन में अपनी बल्क ड्रग व इन्टरमिजिएट्स के लिए विगत 5-6 वर्षों से हम पूरी तरह चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। पूर्व में हम बहुत अधिक मात्रा में आत्म निर्भर थे। भारत विश्व की फार्मेसी कहलाता है। लेकिन, आज हमारे दो तिहाई एक्टिव फार्मास्यूटीकल इनगे्रडिएण्ट (ए.पी.आई.) चीन से ही आते हैं। एमोक्सिसीलिन व पेरासिटामोल जैसी सामान्य औषधियों के ए.पी.आई. भी आज चीन से आ रहे हैं। वर्ष 2016-17 में भारत ने 9121 करोड़ रूपये की बल्क ड्रग्स चीन से आयात की थी। आज देश की लगभग 60 प्रतिशत बल्क ड्रग्स चीन से आ रही है। चीन से आने वाली दवाईयों पर पूर्व में दी जा रही आयात शुल्क छूट को समाप्त करने से इस पर थोड़ा अंकुश तो लगा है। अन्यथा वर्ष 2015-16 में चीन से हमारा बल्क ड्रग्स का आयात 16800 हजार करोड़ रूपयों का था। कुछ प्रमुख औषधियों ओफ्लोक्सासिन और लिवो फ्लोक्सासिन जैसी दवाओं का 90 प्रतिशत बल्क चीन से आयात किया जा रहा है।

अब हमारी पूरी निर्भरता चीन पर होने के बाद चीन जब चाहे इन बल्क ड्रग्स के दाम बढ़कार हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा को चैपट कर सकता है। चीन से आयातों से पूर्व देश का बल्क ड्रग्स उद्योग अत्यंत उन्नत अवस्था में फल-फूल रहा था। दिसम्बर 12, 2015 में इकानामिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तो आज हमारा जेनेरिक दवा उद्योग अपनी थोक उत्पादित दवाओं (बल्क ड्रग्स) में मामले में 90 प्रतिशत तक चीन के सस्ते आयातों पर निर्भर हो गया है। इसके कारण पूर्व में जो हम विश्व के अत्यन्त प्रतिष्ठित थोक दवा उत्पादक देश थे। आज हमारा वह उद्योग पूरी तरह चैपट हो गया है। अनेक कम्पनियाँ आज अपने बैंकों के ऋण भुगतान में भी डिफाल्टर होती जा रही है। कभी चीन में 40-50 ही थोक दवा उत्पादक (Bulk Drug Producers) थे, वे आज बढ़ कर 4000 हो गये हैं। भारत जो विश्व की फार्मेसी कहलाता था, वहीं आज 1 लाख करोड़ के दवा उद्योग में हमारी भारतीय ए.पी.आई. उत्पादकों (एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इन्ग्रेडिएण्ट्स) का अंश मात्र 8 प्रतिशत रह गया है। इससे भविष्य में हमारी स्वास्थ्य रक्षा सुरक्षा भी प्रभावित होगी। एक बार देश में ए.पी.आई. व थोक दवा उद्योग के चैपट हो जाने के बाद चीन कीमतें बढ़ाकर हमारा शोषण प्रारम्भ कर देगा।

वर्ष 1970 से विगत 47 वर्षों के परिश्रम से हमने औषधि उद्योग में हमारी आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी,अब चीनी हमारी विवशता का शोषण करेंगे। उन्होंने अभी से ही हमारी विवशता का शोषण प्रारम्भ कर दिया है। संक्रामकरोधी (एण्टी इन्फेक्टिव) औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त आदायों व अन्तर्वर्ती सामग्रियों (इन्ग्रेडिएण्ट्स एण्ड इण्टरमीडिएट्स) के मूल्य 1 वर्ष में ही दुगुने कर दिये हैं। मल्टी विटामिन्स के सम्बन्ध में भी उन्होंने हमारा शोषण प्रारम्भ कर दिया है। फोलिक एसिड के मूल्य 2015 के 12 महीनों में ही उन्होंने 4500 रूपये प्रति किलों से 11 गुने बढ़ाकर 50,000 रूपये प्रति किलो कर दिये थे। एक बार देश में घरेलू उत्पादकों के विलोपन के बाद पुनः इन उद्यमों को पुनर्जीवित करना आसान नहीं होगा। उस दिशा में हमारा अनुसंधान भी नगण्य हो जायेगा। देश की बड़ी-बड़ी स्वदेशी दवा कम्पनियाँ यथा आर्क फार्मालेब्स, आर्चिड, इण्ड स्विफ्ट, सूर्या फार्मा, पेराबालिक ड्रग्स, वानबरी जैसे अनेक कम्पनियों को कार्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग तक का सहारा लेना पड़ रहा है। कई कम्पनियाँ इस उद्योग से ही बाहर निकल रही हैं। अपनी लागत से भी अल्प मूल्यांकन पर कई दवा कम्पनियाँ बिकी भी हैं। चीनी कम्पनियाँ भी भारत में चलती हुयी दवा कम्पनियों को खरीदने के प्रयास में है। यथा चीनी कम्पनी ‘फोसन’ ने भारतीय दवा कम्पनी ‘ग्लाण्ड फार्मा लिमिटेड’ को 126 करोड़ डालर (8320 करोड़ रूपयों) में खरीदने का प्रस्ताव भी कर रखा है।

मात्रा के आधार पर (बाई वोल्यूम) भारत में विश्व की 10 प्रतिशत औषधियों का उत्पादन होता है। इसी कारण भारत विश्व की फार्मेसी कहलाता रहा है। अब चीन उन बल्क ड्रग्स व उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रेडिएण्ट्स सुनियोजित तरीके से लागत से भी अल्प मूल्य पर बेच कर देश के उद्यमों को कारोबार बन्द करने को विवश कर रहा है। अन्य उद्योगों की तरह औषधि उद्योग को भी चैपट करके चीन दाम बढ़ा कर हमारा शोषण आरम्भ कर देगा। विगत 40 वर्षों में भारी निवेश व अनुसन्धान से जो औषधि उद्योग हमने देश में खड़ा किया है, वह चैपट हो जायेगा। उच्च तकनीक आधारित होने व नये पेटेण्ट कानून की बाधा से इस उद्योग को पुनर्जीवित करना आसान नहीं होगा।

खिलौना उद्योग चोपट:- भारत का फलता फूलता खिलौना उद्योग चीनी आयातों से पिछले 15 वर्षों में पूरी तरह चैपट हो गया है। सर्वाधिक शिशु व बाल जनसंख्या वाले देश में चीन से आ रहे खिलौनों के कारण स्थानीय खिलौना व खेल सामग्री उद्योग विलोपन की ओर बढ़ रहा है। खिलौनों में लगभग ''मैकिंग इन चाइना-मार्केटिंग इन इण्डिया'' अर्थात चीन में बनाओं भारत में बेचों। देश का अपना खिलौना उद्योग लघु व मध्यम स्तरीय उद्योगों के क्षेत्र में था। अब वह पूरी तरह समाप्त प्रायः है। देश में खिलौने या तो चीनी हैं या फिर केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ब्राण्डेड खिलौने हैं।

चीनी आयातों के कारण देश के 60 प्रतिशत खिलौने के कारखाने बन्द हो चुके है व 20 प्रतिशत और बन्द होने को हैं। आज देश के खिलौनों के बाजार में 20 प्रतिशत से भी अल्प खिलौने देश के उत्पादकों के बचे हैं। कभी 85 प्रतिशत खिलौने या 90 प्रतिशत तक भी भारतीय उत्पादकों के हुआ करते थे। आज विश्व के खिलौना उत्पादन में चीन का अंश 45 प्रतिशत है, वहीं भारत का अंश मात्र 0.51 प्रतिशत रह गया है। चीनी खिलौने के रंग व अल्प सामग्री स्वास्थ्य के लिये भी सुरक्षित नहीं है।

साइकिल व साइकिल पार्टस्:- भारत साइकिल, साइकिल रिक्शों व साइकिलों व उनके पुर्जों के उत्पादन व निर्यात का एक बहुत बड़ा केन्द्र था पंजाब में लुधियाना सहित अनेक स्थानों पर साइकिल व साइकिल के पुर्जों का उद्योग फल-फूल रहा था। आज बड़ी मात्रा में साइकिलों के आयात के कारण यह विकेन्द्रित उद्योग सिमटता चला जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा आयात शुल्क लगाने के बाद भी भारी मात्रा में चीनी साइकिलें देश में आ रही है। चीनी साइकिलें श्रीलंका, बांग्लादेश व मलेशिया के मार्ग से आ रही हैं जहाँ आयात शुल्क कम है। उद्योग जगत के लोग इस प्रकार अन्य देशों के रास्ते से चीन से आ रही सस्ती साइकिलों के लिये ''एस्केप रूट'' कूट शब्दों का प्रयोग करते है। आज भारतीय उत्पादक ही उन्नत साइकिलों व सभी प्रकार के साइकिल के पुर्जों के मामले में चीन पर अवलम्बित हो गये है। साइकिल के छर्रें, बास्केट, तानियाँ (स्पोक्स), एयर पंप, हब के कम व कोण, केरियर, साइकिल चेन, हैण्डल बोल्ट, ब्रेक्स, मँहगे स्टील फ्रेम आदि सब कुछ जो पंजाब में घर-घर लघु व कुटीर उद्योगों में बनते थे, वे आज चीन से आ रहे है। ये सभी सामान चीन अभी 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

सस्ते निर्यात कर रहा है। एक बार हमारे घरेलू उद्योग बन्द हो जायेंगे, तब चीन इनकी कीमत डेढ़ गुनी कर देगा। ऐसे कई रोजगार प्रधान उद्योग देश में चैपट हो रहे है। एक बार इन उद्योगों के कुशल कर्मचारी और इनकी निम्नवर्ती आपूर्ति श्रृंखला समाप्त हो जाने के बाद इन उद्योगों को पुनः खड़े करना अत्यन्त कठिन हो जायेगा।

विद्युत उपकरण एवं विद्युत संयंत्र: देश में विद्युत मशीनरी व विद्युत जनन संयंत्र भी बड़ी मात्रा में चीन से आ रहे है। इनके कारण देश का यह रोजगार प्रधान उद्योग भी भारी मात्रा में प्रभावित हुआ है। वर्ष 1996 में मात्र 1.5 अरब डालर के बिजली के सामान आयात होते थे। वर्ष 2011 में विद्युत मशीनरी का आयात 32.8 अरब डालर हो गया। पुनः चीनी विद्युत जनन संयंत्रों के उपकरणों की गुणवत्ता अत्यन्त संदिग्ध होने से 2013-14 के आते-आते देश में डेढ़ से दो लाख करोड़ रूपयों के मूल्य के विद्युत संयंत्र अत्यन्त असंतोषप्रद तरीके से चल रहे है। इतना बड़ी निवेश व्यर्थ जाने से चीनी आयातों पर कुछ अंकुश लगा है। हाल ही में सरकार ने पारस्परिकता व सुरक्षा के आधार पर चीनी कम्पनियों के विरूद्ध कुछ प्रतिबंध लगाने प्रस्तावित किये है। चीन अपने यहाँ विद्युत ग्रिड में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देता है। भारत सरकार ग्रिड में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देता है। इसलिये मई 22, 2017 के इकोनोमिक टाइम्स के अनुसार सरकार ऐसा मेमोरेण्डम जारी करने वाली है। जिसमें विद्युत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में उन देशों की कम्पनियों पर रोक लगाएगी जो देश अपने यहाँ पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देते है। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में विदेशी निवेश उचित भी नहीं है। साइबर आक्रमण के माध्यम से पुरे देश या देश के बड़े भू-भाग में विद्युत व्यवस्था को चोपट किया जा सकता है। पूर्व में भी उत्तर भारत में ग्रिड फेलियोर हो चुका है। विद्युत उपकरणों का आयात विगत 10 वर्षों में अत्यंत तेजी से बढ़ा है। चीनी उपकरणों की गुणवत्ता सर्वथा अविश्वसनीय होने से देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ मूल्य के विद्युतीय साज सामान और विद्युत जनन उपकरणों के घटक असंतोषप्रद रूप से चल रहे हैं।

कृषि रसायनों में चीन पर बढ़ती निर्भरता घातक:- भारत विश्व का सबसे चैथा बड़ा कृषि रसायनों के उत्पादन का देश है। वर्ष 1970 में पेटेण्ट बदलाव के कानून के साथ

ही उत्पादन मात्रा के बदलाव के आधार पर एक बार तो भारत विश्व के तीन प्रमुख देशों में एक हो गया था। लेकिन आज भारत कृषि रसायनों के अपने टेक्नीकल पदार्थों के दो तिहाई चीन से आयात कर रहा है। चीन आज विश्व के कृषि रसायनों के टेक्निकल पदार्थों की मांग का 90 प्रतिशत उत्पादन करता है। ऐसे में हमें चीनी आयातों से अपने देश के कृषि रसायन उद्योग को भी बचाना होगा। हम धीरे-धीरे जैविक कृषि की तरह बढ़े यह आवश्यक है, लेकिन रासायनिक खाद व कृषि रसायनों के मामले में चीन पर निर्भर होते चले जाना सुरक्षित नहीं है। इन उत्पादों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर इनसे देश में जल व मिट्टी का प्रदूषण एवं केंसर जैसी बीमारियाँ तेजी से फैल सकती है।

टैक्सटाइल मशीनरी उद्योग बन्द होने के कगार पर:- देश में 1500-2000 टैक्सटाइल मशीनरी के निर्माता फल-फूल रहे थे। कताई, बुनाई के लूम, निटिंग मशीनें व प्रविधेयन मशीनरी सहित आज 4-5 हजार करोड़ रूपये की मशीनें चीन से आने लग गयी हैं।

स्मार्ट फोन:- आज देश का स्मार्ट फोन का तो 50 प्रतिशत बाजार अब चीनी कम्पनियों के हाथ में चला गया है। जो एक वर्ष पूर्व मात्र 21 प्रतिशत व 2 वर्ष पूर्व 15 प्रतिशत था। भारतीय ब्राण्डों का बाजार अंश तेजी से गिर रहा है। वर्ष 2013 तक 12 चीनी ब्राण्ड देश में आ रहे थे। आज 57 चीनी ब्राण्ड देश में आ रहे हैं। आज जब कई चीनी कम्पनियाँ भारत में ही अपनी असेम्बली लाइन्स लगा रही है, तो उनकी भारतीय बाजारों पर पकड़ और सुदृढ़ हो जायेगी। वेसे आज देश में बिक रहे स्मार्ट फोन में घरेलू मूल्य योगदान (वेल्यू एडिशन) मात्र 6 प्रतिशत है। फोन की लागत के 90-94 प्रतिशत कार्य देश के बाहर मुख्यतः चीन में ही हो रहा है।

इंजिनीयरिंग उत्पाद, पंपसेट, स्पोर्टस के सामानों से लेकर हेण्डीक्राफ्ट के सामानों तक में हमारे छोटे व कुटीर उद्योग चैपट हो रहे हैं। मशीन से बने लेकिन हैण्डीक्राफ्ट जैसे लगने वाले उत्पादों से लाखों कारीगर चैपट हो रहे हैं।

देश के अनेक उद्योग संकुल संकट में :

देश में 400 प्रमुख सूचीबद्ध उद्योग संकुल (Industry Clusters) है। उनमें से 150 से अधिक उद्योग संकुल सस्ते चीनी आयातों से चैपट हो सकते है। सुई, रेजर, ब्लेड और स्टील के छर्रों से लेकर खिलौने, गर्म पानी की बोतलें, कांच के फ्लावर पोट, इलेकट्रोनिक उत्पाद, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर हार्डवेयर, विद्युतीय उपकरणों और भारी मशीनरी तक चीनी आयात आज देश के अनेक उद्योग संकुलों को चैपट कर रहे है। चीन अपने माल को प्रारम्भ में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक सस्ता बेच कर एक बार भारतीय उद्यमों को अपना उत्पादन बन्द करने पर विवश कर देता है। उसके बाद वह अपनी कीमतें बढ़ा कर हमारा शोषण प्रारम्भ कर देता हैं।

फिरोजाबाद का शताब्दियों पुराना काँच उद्योग संकुल चोपटः- फिरोजाबाद में शताब्दियों पुराना काँच के उत्पादों का उद्योग संकुल (इण्डस्ट्री क्लस्टर) था। वहाँ 400-500 कुटीर, लघु व मध्यम आकार के काँच के उत्पाद बनाने वाले उद्यम थे। आज 300 से अधिक कारखाने सस्ते चीनी आयातों से बन्द हो चुके हैं। देश की अपनी एक कला विलुप्त हो रही है, हजारों लोग बेरोजगार हुये हैं, उन उद्यमों को फर्नेन्स व अन्य साज-सामान की आपूर्ति करने वाले उद्योग भी चोपट हो रहे हैं। न्यूनाधिक रूप से ऐसी ही स्थिति देश के अन्य 400 प्रमुख उद्योग संकुलों व 2000 से अधिक छोटे संकुलों की हो रही है।

चाहे मोरवी का सेरेमिक उद्योग हो या राजकोट का पम्प सेट अथवा लुधियाना का कम्बल उद्योग हो या फिरोजाबाद का काँच उद्योग। सब प्रकार के उद्योग व उद्योग संकुल (इण्डस्ट्री क्लस्टर्स) चीनी उत्पादों से त्रस्त होते रहे हैं। वे सम्हलते हैं, पुनः चीनी गला काट स्पर्द्धा के शिकार होते हैं। इनके अतिरिक्त देश में छोटे-छोटे भी अनेक उद्योग व उद्योग संकुल प्रभावित हो रहे है। वैसे देश में शायद ही कोई उद्योग हो जो चीन के सस्ते आयातों से प्रभावित न हो रहा है। एक-एक उद्योग श्रेणी में हजारों की संख्या में लघु व मध्यम उद्योग बन्द हुए है। उदाहरण के लिये पिछले दो वर्षों में खिलौनों की ही 2000 इकाईयाँ बन्द हुई है। जालन्धर, लुधियाना, ठाणे, भिवण्डी, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, फिरोजाबाद अंकलेश्वर, वापी से लेकर कोयम्बटूर व चेन्नई तक कई-कई हजार उद्योग बन्द हुए है। इनमें कार्यरत लाखों लोग बेरोजगार हुए है। बैंकों द्वारा इन रूग्ण

होते उद्योगों को प्रदान किये ऋण डूब रहे है। देश से प्रौद्योगिकी का विलोपन हो रहा है। ऐसे में हमारे लिये आवश्यक है कि चीन से कोई विद्वेष रखे बिना भी अपने देश के उद्योगों को व उनमें रोजगार आदि को बचाने के लिये हम चीनी उत्पादों के स्थान पर मेड बाई भारत या भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित भारतीय ब्राण्ड की वस्तुएँ ही खरीदें। चीन समेत हजारों बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने अधिकांश उत्पाद बाहर से लाकर उनकी केवल मात्र असेम्बलिंग ही भारत में कर लेती हैं। और उन पर मेड इन इण्डिया लिख देती हैं। इसलिये हमें मेड इन इण्डिया से भ्रमित नहीं होना चाहिये। वस्तुओं के ब्राण्ड देखकर विदेशी ब्राण्डों के स्थान पर भारतीय ब्राण्ड ही खरीदने चाहिये।

सरकार ने चीन से आने वाले दूध व दूध के उत्पादों में स्वास्थ्य के लिये घातक रसायनों का सम्मिश्रण होने व जिन स्मार्ट फोन में इण्टरनेशनल मोबाइल स्टेशन अइडेण्टीफिकेशन नम्बर नहीं होता है उन पर प्रतिबन्ध के साथ ही चीनी पटाखों व पतंग के माझे जैसे उत्पादों पर भी सुरक्षा कारणों से अवश्य प्रतिबंध लगाया है। लेकिन ये सभी प्रतिबन्ध तो नाम मात्र का प्रभाव रखते हैं। कुल चीनी आयातों में आज 80 प्रतिशत विद्युत मशीनरी विद्युत जनन संयंत्र व दूर संचार उत्पाद जैसे उच्च प्रौद्योगिकी आधारित है। वर्ष 2016 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 50 अरब डालर के करीब था जबकि भारत के चीन को निर्यात मात्र 11 अरब डालर के थे और वह भी अधिकांश कच्चे माल के निर्यात थे।

रणनीतिक तरीके से भारत के विदेश व्यापार पर आघात

चीन केवल उसके व्यापार को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहकर भारत के आर्थिक हितों पर भी रणनीतिक तरीके से आक्रमण प्रारम्भ कर रखा है। इसके 2 उदाहरण यहाँ जाने समीचीन ही हैं:-

सूती वस्तु उद्योग पर आघात:- भारत विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक व निर्यातक देशों में एक है। चीन ने 2011 में भारत के सूती वस्त्र उद्योग को चैपट करने के लिए देश में उत्पन्न अधिकांश कपास को अत्यन्त ऊँचे दाम पर खरीद लिया था। जब देश में कपास का मूल्य 4000/- रूपये क्विटल था तब उसने 7000/- रूपये प्रति क्विंटल

खरीद कर भारतीय वस्त्र उद्योग को चैपट करने का प्रयत्न किया था। तब भारत सरकार को कपास निर्यात पर रोक लगा कर व निर्यात शुल्क लगा कर देश में सूती वस्त्र उद्योग को बचाना था। लेकिन यह नहीं किया इससे देश के सूती वस्त्र उद्योग कपास की कमी से रूग्ण हुआ। दूसरी ओर चीन ने हमारे पारम्परिक सूती वस्त्र निर्यात बाजारों में सस्ते कपड़ों की डम्पिंग कर वह बाजार हमसे छीन लिया। दूसरे वर्ष देश में किसानों ने, यह सोच कर व्यापक स्तर पर कपास बोया कि पिछले वर्ष कपास 7000 रूपये प्रति क्विण्टल बिका था। लेकिन उस वर्ष सरकार कपास निर्यात पर रोक लगा दी। इससे कपास के दाम 4000 रूपये से भी नीचे चले गये व किसानों को उनका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाया।

भारत के नाम से अफ्रीका में नकली दवाओं का निर्यात:- भारत के दवा निर्यात को चोपट करने व 'मेड बाई इण्डिया' वस्तुओं को बदनाम कर भारत के आर्थिक हितों को हानि पहुंचाने के लिए चीन ने अफ्रीका में 'मेड इन इण्डिया' ब्राण्ड की वस्तुएं विशेष कर दवाईयाँ भी प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। इसका स्पष्ट उद्देश्य अफ्रीका में भारतीय वस्तुओं को बदनाम करना था।

छद्म व्यापार:- भारत सरकार ने पतंग की डोर व पटाखों जैसे कुछ उत्पादों के खतरनाक सिद्ध होने पर पांच चीनी उत्पादों के आयात पर रोक भी लगाई है। लेकिन चीन छद्म रूप से अपनी वस्तुएँ भारत में बेच लेता है। ऐसे कन्टेनर भी पकड़े गये है, जिनमें चीन से रिवाल्विंग चेयर के लिये आयात किये जाने बताए थे। उनमें पटाखे पकड़े जा चुके है।

चीन विरोधी अभियान के सुखद परिणाम

लेकिन सर्वाधिक सुखद समाचार है कि देश में पिछले वर्ष स्वदेशी जागरण मंच द्वारा इस व्यापार घाटे को लेकर किये चीनी वस्तुओं के परित्याग के आवाहन से घबराकर, चीन ने भारत से अपने आयातों में भारी वृद्धि की है। चीन को भारत के निर्यात 2017 में खूब बढ़े जहाँ भारत से चीन को निर्यात, 2017 के पहले चार महीनों में बढ कर 5.57 अरब डॉलर के हुये है। निर्यात के मामले में भारत के लिए एक अच्छी

खबर है और चीन इसी प्रकार सही रास्ते पर आ सकता है। आंकड़ों के अनुसार 2017 के शुरूआती 4 महीनों के दौरान भारत से चीन को निर्यात तेजी से बढ़ा है। जनवरी से अप्रैल के दौरान भारत का चीन को निर्यात 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.57 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत ने कई साल की गिरावट के बाद यह तेजी दर्ज कराई है। हालांकि भारत का उच्च व्यापार घाटा अभी भी बना हुआ है।

चीन अब भी कच्चे माल ही भारत से आयात कर रहा है: चीन भारत से आज बहिष्कार के दबाव के बाद भी बड़ी मात्रा में केवल लौह अयस्क, रत्न, हीरे और कपास आदि कच्ची सामग्री का ही आयात कर रहा है। चीन के सीमा शुल्क विभाग के अनुसार जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक भारत चीन व्यापार 6 प्रतिशत बढ़कर 26.02 अरब डालर हो चुका है। भारतीय निर्यात इस दौरान 20 प्रतिशत बढ़कर 5.57 अरब डॉलर का हो गया है। चीन से भारत को निर्यात भी 14 प्रतिशत बढ़कर 20.45 अरब डॉलर रहा। लेकिन भारत के सारे आयात निर्मित माल के है।

व्यापार घाटे की समस्या यथावत:- चीन को निर्यात बढ़ने के बावजूद भारत का व्यापार घाटा उच्च स्तर पर बना हुआ है। साल के पहले 4 महीने में व्यापार घाटा 14.88 अरब डॉलर रहा। पिछले वर्ष 2016 में हमारा चीन से कुल व्यापार घाटा लगभग 52 अरब डॉलर का रहा था, जबकि कुल द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब डॉलर से कुछ अधिक का ही रहा था।

हम भारतीय बना रहे हैं चीन को आर्थिक महाशक्ति:- हम अपने उद्योगों को चैपट कर चीन जैसे शत्रु देश के ब्राण्डों को विश्व स्तरीय बना रहे हैं। स्मार्ट फोन हमारे ऐसे आत्मघाती कदमों का अच्छा उदाहरण है। देश में आज आधे से अधिक स्मार्ट फोन के ब्राण्ड बिक रहे थे। आज 57 चीनी ब्राण्ड बिक रहे हैं। इनमें कई ब्राण्ड केवल भारत में उनकी तेजी से बढ़ती बिक्री के कारण विश्वस्तरीय बने हैं। अन्यथा कई चीनी ब्राण्ड वैश्विक ब्राण्ड न बन कर चीन में ही सीमित घरेलू ब्राण्ड ही बने रहते। चीन के 4 स्मार्ट फोन ब्राण्डों जिओमी, विवो, ओप्पो व जिओनी की कुल वैश्विक बिक्री की क्रमशः 67 प्रतिशत, 73 प्रतिशत, 48 प्रतिशत व 25 प्रतिशत आज भारत में हो रहे है। जर्मन की

जीएफ के ग्लोबल हेण्डसेट अपडेट के मार्च 2017 के बिक्री के ये तथ्य अग्रानुसार है। जीयोनी के कुल बाजार की 25 प्रतिशत भारत में है। वर्ष 2017 में देश में 13 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन बिकेंगे। विश्व के मोबाइल फोन के बाजार में भारत का अंश 15 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका: चीन ब्राण्डों की वैश्विक बिक्री में भारत का योगदान

चीनी मोबाइल फोन ब्रांड	कुल अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री में भारत का योगदान
Vivo	73%
Xiomi	67%
Oppo	48%
Gionee	25%

मोबाइल फोन जैसी स्थिति और भी कई उत्पादों में है, जहाँ आज मन्दी में फंसी चीनी अर्थव्यवस्था को भारत उसके उत्पाद आयात कर उसे आक्सीजन दे रहा है।

अध्याय - 2

गंभीर संकट में चीन - ऐसे में भारत क्यों बने तारनहार

संकट में चीन: भारत के विरूद्ध सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त व भारी कर्ज में डूबी चीन की अर्थव्यवस्था, आज तीन दशकों के सर्वाधिक गंभीर संकट में फँसी हुई है। पच्चीस वर्ष बाद इस वर्ष 2017 के लिये चीन ने अपने लिये अब तक की सबसे न्यून आर्थिक वृद्धि दर आंकी है। अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐजेन्सी मूडिज ने भी 28 वर्षों में पहली बार चीन की साख के मूल्यांकन, अर्थात क्रेडिट रेटिंग में कमी की है। चीन में मन्दी के कारण हाल ही में अपने यहाँ पाँच लाख नौकरियों में भी कटौती की गयी है। ऐसे में कर्ज व मंदी से जूझते चीन की वस्तुओं को हम भारत में बड़ी मात्रा में व अधिकाधिक खरीद कर, अपने देश में उद्यमबंदी, बेरोजगारी, व्यापार घाटे व बैंकों के ऋणों के डुबते चले जाने जैसे कई संकटों को आमंत्रित करते हुए, मरती हुई चीनी अर्थव्यवस्था को जीवन दान दे रहे हैं। दूसरी ओर चीन विगत 65 वर्षों से सर्वाधिक भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वस्तुतः चीन से बढ़ रहे आयातों के कारण आज हमारे देश के छोटे-बड़े सभी प्रकार के उद्योग बड़ी संख्या में हुये हैं एवं और भी बन्द होते ही जा रहे हैं या मन्दी व संकटों में फंस रहे हैं। इससे देश में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुये हैं और होते ही जा रहे हैं। चीनी आयातों से संकटग्रस्त हो रहे उद्योगों में भारी मात्रा में देश के बैंकों के ऋण भी डूब रहे हैं। इसके साथ ही चीन से विदेश व्यापार में हुये जो भारी घाटा हो रहा हैं, उसके कारण विगत 6 वर्षों में रूपये की कीमत में 35 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयी है। ऐसा होने पर भी हम भारत में भारत के विरूद्ध सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त चीन के बड़ी मात्रा में चीनी वस्तुओं को खरीद कर इन संकटों से उबारने हेतु, आक्सीजन अर्थात् प्राणवायु की तरह अपना बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे द्वारा आज पेन, मोबाइल फोन व बल्ब आदि से लेकर सौर ऊर्जा पेनल, कम्प्यूटर, अन्य इलेक्ट्रोनिक उत्पाद, फर्नीचर व बस-ट्रक के टायरों तक विविध चीनी उत्पादों को अधिकाधिक खरीदते चले जाने से ही चीनी उद्योग

इस मन्दी में भी बन्द होने से बचे, हुये हैं व उसी से चीनी अर्थव्यवस्था, एक बड़ी सीमा तक चरमराने से बची हुयी है।

ऋण जाल व मन्दी में फँसी चीनी अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण क्यों ?

आज हम चीनी वस्तुएँ खरीदते जाकर ही उस देश का आर्थिक सशक्तिकरण करके अपने ही देश के लिये जटिल आर्थिक समस्याऐं व सामरिक संकट बढ़ा रहे हैं। चीन, जो विगत 65 वर्षों से सर्वाधिक भारत विरोधी व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त है। ऐसे समय में जब हम संकट में फँसी चीन की अर्थव्यवस्था को उसकी वस्तुओं का बहिष्कार करके चैपट कर सकते हैं, तब हम उसी की वस्तुयें खरीद कर उसे आर्थिक जीवन दान दे रहे हैं। चीन के सार्वजनिक ऋण पर एक दृष्टिपात से ही स्पष्ट हो जायेगा कि आज हम ही भारी कर्ज में डूबे चीन की वस्तुएँ खरीद कर ही चीन की अर्थव्यवस्था को संकटों से बचा रहे हैं, जो हमारे लिये ही सबसे बड़ी आर्थिक व सामरिक या रक्षा चुनौति बन जायेगा। ऐसे में यदि हमने वर्तमान मन्दी के दौर में, चीनी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार कर दिया तो उसके दिवालिया होने की सम्भावनायें काफी बढ़ जायेंगी। ऐसा हुआ तो भारत की सम्प्रभुता व सुरक्षा के लिये चुनौति बन रही चीन की ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) परियोजना भी धूल धूसरित हो सकती है। विशेषकर जब अमेरिका भी चीन से 347 अरब डालर के घाटे को समाप्त करने को प्रयत्नशील है। चीन, आज जिस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में शान्ति, मानवाधिकारों की रक्षा, आतंकवाद उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण एवं सामरिक संतुलन लिये गम्भीर चुनौती बना हुआ है और आज जब वह स्वयं एक गम्भीर आर्थिक व वित्तीय ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है तब यही अवसर के जब चीनी उत्पादों के बहिष्कार से चीनी अर्थव्यवथा को जमीन पर ला कर विश्व को राहत दिलायें। आज जब अमेरिका चीन के साथ उसके व्यापार घाटे पर नियंत्रण करने के लिये गंभीर कदम उठा रहा है। उससे चीनी अर्थव्यस्था के ध्वस्त होने की और भी पर्याप्त संभावना बन जाती है। चीन के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भी पूरी तरह से गंभीर हैं। चीन को अमेरिका के निर्यात वर्ष 2016 में मात्र 115.77 अरब डालर के ही थे। वहीं दूसरी और अमेरिका में चीनी उत्पादों का निर्यात 462.8

अरब डालर था। इस प्रकार अमेरिका के साथ व्यापार में चीन को जो 347 अरब डालर का भारी भरकम अतिरेक (Surplus) मिल रहा है, वही 347 अरब डालर का अमेरिका के लिये भारी भरकम व्यापार घाटा है। अब जब राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस अमेरिकी घाटे को समाप्त करने का संकल्प कर लिया है तो चीन के लिये अपने उद्योगों को पूरी क्षमता से चलाये रखना कठिन हो जायेगा। इससे चीन के लिये अपने विदेशी मुद्रा भण्डारों का स्तर भी बनाये रखना कठिन हो जाएगा। चीन के विदेशी मुद्रा भण्डारों में कमी होनी तो प्रारम्भ हो ही गयी है। जून 2014 में उसके पास 3,993 अरब डालर के विदेशी मुद्रा भण्डार थे वे ही जनवरी 2017 में 12.3 अरब डालर से घट कर पहुँच गये है।

चीन में सार्वजनिक ऋण बढ़ने का प्रमुख कारण यही है कि अब तक चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक विस्तार से कर्ज बांट कर अपनी जी.डी.पी. को तो बढ़ा लिया। लेकिन उसका कर्ज भयावह रूप से बढ़ गया है। चीन के कर्ज के अधिकारिक आंकड़े तो उसके सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक का कर्ज बता रहे है। कर्ज का यह स्तर भी अत्यन्त विस्फोटक सिद्ध हो सकता है। लेकिन चीन के नियमनरहित, कुख्यात छाया बैकिंग तंत्र के ऋणों को भी इसमें जोड़ लेने पर चीनी अर्थव्यस्था में कुल ऋणों का अनुपात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 400 प्रतिशत तक के अति विस्फोटक स्तर तक पहुँच जाते हैं। सामान्यतया उसके अधिकारिक आंकड़ों में इन्हें नहीं जोड़कर 28 खरब डालर के ऋणों को ही दर्शाया जाता है जिससे भी उसका ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 250 प्रतिशत हो जाता है। वस्तुतः 2001 में उसा जीडीपी 1094 अरब डालर था। जो 2016 के अंत तक 11,750 अरब डालर तक पहुँच कर 11 गुणा हो गया। लेकिन उसके वित्तीय तंत्र में ऋण की राशि जो 2001 में उसके सकल घरेलू उत्पाद के तुल्य ही थी, वह 40 गुनी हो गयी। इस तथ्य को मार्केट वॉच डाट काम (marketwatch.com) में इवान मार्टचेव ने अपने 20 फरवरी 2017 के लेख में स्पष्ट किया है।

अब जब चीनी अर्थव्यवस्था मंदी व ऋण जाल में फंसी हुई है। ऐसे में यदि अमेरिका चीन के साथ 347 अरब डालर के उसके व्यापार घाटे को शून्य पर ले आता है और

हम भारतीय नागरिक भी चीनी वस्तुओं को खरीदना बन्द करके अपने 52 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को शून्य कर लेते हैं तो चीनी अर्थव्यवस्था का जमीन पर आना अवश्यम्भावी है। इससे सम्पूर्ण विश्व राहत की सांस लेगा। चीन पर चढ़े कर्ज व वहाँ फैलती मन्दी को देखते हुये तो वर्ष 2008 में हुये अमेरिकी मेल्ट डाउन से भी अधिक भयावह मेल्ट डाउन जैसा आर्थिक संकट वहाँ मुँह बाये उसे निगलने को खड़ा है। आज चीनी कम्पनियाँ 180 खरब डालर अर्थात $18 Trillion Dollar (12060 खरब अर्थात 1206 लाख करोड़ रूपये तुल्य) कर्ज में डूबी हुयीं हैं। यह कार्पोरेट ऋणों की राशि उनके सकल घरेलू उत्पाद की 170 प्रतिशत है। पूरी चीनी अर्थ व्यवस्था आज 280 खरब (आस्ट्रेलियन) डालर अर्थात उसके घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत ऋण के बोझ तले चरमराने को है। इन भारी ऋणों के बोझ से दबी कम्पनियों के साथ ही चीन के सारे बैंकों सहित उसका मुद्रा तंत्र, उद्योग व वाणिज्य सब कुछ डूब सकता है। यदि भारत व अमेरिकी चीन से अपने आयात कम कर लेवें और अगले एक वर्ष और चीनी उत्पादों की बिक्री घटती रही तो यह होना ही है। लेकिन, यदि हम जो चीनी वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें खरीदना हमने जारी रखा और चीनी उद्यम बच गए तो चीनी अर्थव्यवस्था इस पूरे संकट से अत्यंत सहजता से पार पा जायेगी। थोड़ा समय और चीनी माल पर्याप्त मात्रा में बिकता ही रहा तो, चीन इस संकट से सहजता से उबर जायेगा। हमारा बाजार ही आज चीन के लिये प्राणवायु अर्थात आक्सिजन का काम कर रहा है। वैसे चीन ने अब इस पूरे संकट से पार पाने की योजना की घोषणा भी सोमवार 10 अक्टूबर 2016 को कर दी थी।

अपनी कम्पनियों को ऋणों से राहत देने की इस नवीन योजना के अधीन चीन उसकी केवल कुछ बहुत ही अकुशल कम्पनियों को छोड़कर अपनी शेष सभी कुशल कंपनियों, जिनके उत्पाद विश्व भर में बिकते हैं, के ऋणों को पूंजी में बदल देगा। कम्पनी को ऋण पर ब्याज चुकाना होता है और किश्त भी प्रतिमाह चुकानी होती है। लेकिन इस नवीन प्रस्ताव के अनुरूप उस ऋण को पूंजी में बदलते ही (debt-equity swap) कंपनी पर से किश्त व ब्याज के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में आज की मंदी में भी वह कम्पनी अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर

पाने पर भी जीवित रह सकती है, क्योंकि उसे अब न तो किश्त चुकानी है और न ही ब्याज। लेकिन यदि तब भी उसकी बिक्री ही नहीं हुयी तो उसे (कंपनी को) बन्द होना ही है। यदि चीनी माल का हमने पूर्ण बहिष्कार कर दिया और विश्व में भी हमने चीन की पर्यावरणक्षरण, मानवाधिकार हनन, आतंकवाद का संपोषण एवं विश्व शांति के संबंध में खड़ी की जा रही चुनौतियों का स्मरण कराकर सोशल मीडिया पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाहन करें तो अधिकांश चीनी कंपनियाँ बन्द होनी ही है। ऋण को पूंजी में बदलने के बाद भी बंद होगी। ऐसे में चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 170 प्रतिशत तक पहुंच चुके कंपनी ऋणों का दो तिहाई अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद तुल्य 120 खरब डालर ($12 Trillion) का डूबना तो निश्चित ही है। चीन में कुल बकाया ऋणों की राशि तो आज 280 खरब डालर $ 28 Trillion अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। यह राशि अमेरिका व जापान के संयुक्त वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र के तुल्य है। यदि वर्तमान में चीन ने अपनी कंपनी ऋणों की पुनर्रचना जिसमें ऋणों को पूंजी में परिवर्तन भी सम्मिलित है के सहारे अपने बैंकिंग तंत्र व बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादन तंत्र को बचा लिया तो वह 3-5 वर्ष में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ विश्व की क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति व सामरिक शक्ति बन कर खड़ा होगा।

दूसरी ओर अभी जब चीन की अधिकांश कंपनियां व सम्पूर्ण बैंकिंग तंत्र चरमराने को है। उसके कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तक में गतिरोध के अनुमान लगाये जा रहे हैं। ऐसे में यदि हम चीनी वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे व विश्व में भी ऐसा ही आवाहन करें तो उसका उत्पादन तंत्र व बैंकिंग तंत्र ध्वस्त होगा, निर्यात घटेंगे, विदेशी व्यापार में घाटा भी होगा, विदेशी मुद्रा भण्डार चुक जायेंगे और चीन के अर्थव्यवस्था के दिवालिया होते ही विश्व चैन की सांस लेगा। भारत का निकट पड़ोसी व उसके साथ गम्भीर सीमा विवाद होने व उसकी पाक से मैत्री होने से चीन का सबल होना भारत के लिये सर्वाधिक संकटकारक होगा। चीन बचेगा तो बड़ी सीमा तक भारत के बाजार से बचेगा। हमने चीनी माल खरीदते रह कर उसे बचा लिया तो अब ‘वन बेल्ट वन रोड़’ परियोजना पूरी हो जाने के बाद तो चीन महाशक्तिशाली देश बन जायेगा। लेकिन

1400 अरब डालर लागत की यह योजना धूल धूसरित हो जायेगी, यदि भारत चीनी माल को क्रय करना छोड़ दे व अमेरिका भी अपना चीन से व्यापार घाटा समाप्त कर लें।

अगला वैश्विक वित्तीय संकट चीन के कारण हो सकता है:- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित, विश्व की सभी प्रमुख वित्तीय अभिकृतियों (Financial Agencies) का मानना है कि चीन के कर्ज की समस्या को देखते हुए भविष्य में कोई बड़ा वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न होने की भी पर्याप्त संभावनाऐं है। चीन की जो ब्राड मनी सप्लाई अर्थात् एम-2 (M2) जिसमें देश की रोकड़ मुद्रा व बैकों की जमाओं को जोड़ा जाता है, वह उसके सकल घरेलू उत्पाद की 208 प्रतिशत है। वर्ष 2016 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुद्रा आपूर्ति विश्व में सर्वोच्च है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह M2 मुद्रा आपूर्ति 170 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। अमेरिका में यह अनुपात 80 प्रतिशत का ही है। जापान में यह अनुपात चाहे 240 प्रतिशत है, लेकिन जापान का वित्तीय तंत्र बैंक आधारित होने से यह उच्चानुपात चीन के जितना समस्याजनक नहीं है।

चीन का आर्थिक सशक्तिकरण अनुचित

चीनी वस्तुओं की खरीद से चीन का आर्थिक व सामरिक सशक्तिकरण भारत के लिये सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण होगा और हमें अपने संसाधन विकास के स्थान पर चीन-पाक से सुरक्षा में लगाने होंगे। इसके लिये भारत को अपने अबाध विकास के लिये चीन पर आर्थिक अंकुश लगाना सर्वाधिक आवश्यक है। चीन द्वारा की जा रही अनवरत शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के उपरान्त भी, भारत द्वारा चीन को सर्वाधिक व्यापार सुविधाएँ देना और भी आत्मघाती कदम है। देश का सर्वाधिक 52 अरब डालर (3.5 लाख करोड़ रूपयों) का व्यापार घाटा, आज केवल चीन के साथ ही है। चीन से घोषित रूप में 4.25 लाख करोड़ रूपये व बड़ी मात्रा में अघोषित व कम बिल का माल भी देश में आ रहा है। आज देश में 5-6 लाख करोड़ रूपये का माल देश में आ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि चीन का जो आज देश में हम 5-6 लाख करोड़ रूपये

का माल आयात करते हैं, उसे हमें तत्काल बन्द करना चाहिये। देश की जनता आज चीनी माल खरीदना बन्द कर दे, यह चीन के प्रति हमारा सर्वोत्तम कदम सिद्ध होगा। अतएव आज जब चीन एक आर्थिक, वित्तीय, बैंकिंग व कार्पोरेट संकट के ज्वालामुखी पर बैठा है, चीनी वस्तुओं का परित्याग ही इस संकट में विस्फोट की संभावना निश्चित करेगा। इससे चीन की संपूर्ण विश्व के लिए संकट उपजाने वाली गतिविधियों पर भी अंकुश लग सकेगा एवं विश्वभर में फैलते पर्यावरण संकट, विश्व के विभिन्न भागों में मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद पर नियंत्रण संभव होने से संपूर्ण विश्व की मानवता राहत की सांस लेगी।

चीन की आर्थिक व सामरिक बढ़त में आज एक बड़ा योगदान भारत सरकार व हम भारतीयों का है। हम भारत में चीनी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उपयोग जो करते हैं। आज चीन और भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर वार्षिक से अधिक है। इसमें 62 अरब डालर से अधिक के हमारे आयात हैं। यह 62 अरब डॉलर का माल लगभग चार लाख करोड़ रूपये से अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त चीन के उत्पाद बड़ी मात्रा में देश में बिना बिल के भी मिलते हैं या फिर कम बिल के भी मिलते हैं। बिना बिल का जो माल अपने देश में आ रहा है उसे जोड़ लें तो चीन से कुल आयात पाँच से साढ़े पाँच लाख करोड़ के हों तो कोई आश्चर्य नहीं है अगर 5.5-6.0 लाख करोड़ रूपयों का चीनी माल अपने देश में बिक रहा है, तो इसका कम से कम 10-12 प्रतिशत टैक्स तो चीन की सरकार को मिल रहा होगा। यदि हम 12 प्रतिशत टैक्स-जी.डी.पी. का अनुपात मानें तब, 60-70 हजार करोड़ रूपये के बराबर चीन की सरकार को राजस्व (Tax Revenue) की आय, हम भारतीय लोग, देश में चीनी माल खरीद कर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जो देश हमारे लिए रक्षा संकट है, हम उस देश की अर्थ व्यवस्था को, 6 लाख करोड़ रूपये का माल खरीद कर और सशक्त बना रहे हैं और उस देश की सरकार को 60-70 हजार करोड़ रूपये का कर राजस्व, उसका माल खरीदकर आप और हम दे रहे हैं। चीन इस 60-70 हजार करोड़ रूपये का राजस्व, जो उसे हम प्रदान कर रहे हैं, उसका एक भाग ही हमारे ऊपर सामरिक दबाव बनाने के लिए पर्याप्त है, एवं उससे ही वह पर्याप्त सामरिक दबाव बना लेता है। इस प्रकार

आज हम ही यह सुरक्षा संकट अपने लिये खड़ा कर रहे हैं। चीन का माल पूरे देश में कौने-कौने में छा रहा है, चाहे 'टैक्सन' का केलकुलेटर हो या टी.सी.एल का टी.वी. हो, 'लिनोवा' का कम्प्यूटर हो, या अन्य ब्राण्डों के पेन व बच्चों के खिलौने हों, छोटे बल्ब हों, या बड़े विद्युत जनन संयंत्र (जेनरेटर) अथवा टेलीफोन एक्सचेन्ज, ये सब बड़ी मात्रा में अपने यहाँ चीन से आ रहे हैं। इसलिए, आज आवश्यकता इस बात की है कि, हम चीन से आने वाले सभी उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार करें। चीन के उत्पादों को चिन्हित करने में भी कठिनाई नहीं है क्योंकि उस पर ''मेड इन चाईना'' लिखा हुआ है। आज देश में सर्वाधिक कम्प्यूटर चीनी लीनोवो ही बिक रहे हैं। विदेश व्यापार में सर्वाधिक 52 अरब डालर का घाटा चीन के साथ ही है। वर्ष 2011-12 में देश का कुल 184 अरब डालर का विदेश व्यापार घाटा था, उसमें चीन के साथ ही इतना 41 अरब डालर का घाटा रहा है। भारत-चीन व्यापार 2015-16 में 52 अरब डालर था। इसमें चीन हमारे यहाँ 62 अरब डालर का माल निर्यात करता है, पर हम चीन को 9.0 अरब डालर का माल ही निर्यात कर पाये थे। वर्ष 2012-13 में भारत-चीन व्यापार 68 अरब डालर का था, उसमें हमारे निर्यात घट कर 13.5 अरब डालर के ही रह गये, जबकि चीन के निर्यात 54.5 अरब डालर थे। 2015-16 में हमारे निर्यात घट कर 9 अरब डालर रह गये जो वर्ष 2012 में 17.03 अरब डालर के थे।

चीन का जिस प्रकार से आज हम पर सामरिक दबाव है, उसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी, दो प्रकार का दबाव बन रहा है। एक तो बड़ी संख्या में देश में कारखाने बन्द हो रहे हैं। छोटे-छोटे घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर रसायन व इन्जिनियरिंग के क्षेत्र पर्यन्त उद्योग एक के बाद एक चैपट हो रहे हैं। दूसरी और चीन ने अपना आर्थिक आधार इतना बढ़ा लिया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही चीन दुनिया की क्रमांक एक की अर्थव्यवस्था बन जायेगा। किसी जमाने में चीन दुनिया की सातवें क्रमांक की अर्थव्यवस्था था। वह बढ़ते-बढ़ते आज दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया है। जापान, जो दूसरे क्रमांक पर था, उसको पीछे छोड़कर चीन दूसरे क्रमांक पर आ गया है। चीन के कुल निर्यात आज अमेरिका से भी अधिक हैं और अब चीन विश्व का क्रमांक एक का निर्यातकर्ता देश बन गया है। वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में भी चीन सर्वोच्च

22 प्रतिशत अंश है। हमारा अंश मात्र 2.1 प्रतिशत ही है। अमेरिका भी आज 17.6 प्रतिशत के साथ क्रमांक दो पर आ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अमेरिका से अधिक निर्यात व्यापार आज चीन का है। ऐसे भी अनुमान हैं कि 2027 से 35 के बीच अमेरिका, जो आज आर्थिक दृष्टि से क्रमांक एक की अर्थ व्यवस्था है, उसे पीछे छोड़कर क्रय सामर्थ्य साम्य (परचेजिंग पावर पेरिटी) के आधार पर चीन विश्व की क्रमांक एक की अर्थ व्यवस्था बन जायेगा। यदि ऐसा होता है तो अमेरिका तो चीन से बहुत दूर है उसके लिए सीमा पर कोई तनाव की बात नहीं है। जबकि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, सीमा पर तनाव है और ऐसे में अगर चीन विश्व की क्रमांक एक की अर्थ व्यवस्था बनकर उभरता है तब हम पर सैन्य दबाव भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। इसलिये देशवासियों को चीनी वस्तुओं की खरीद अविलम्ब बन्द करनी चाहिये। सरकार पर भी दबाव बनाना चाहिये कि, चीन को दी जा रही व्यापारिक सुविधाएँ व परियोजनाओं के ठेके बन्द करें। हाल ही में पिछले वर्ष भारतीय कम्पनियों को चीनी मुद्रा 'युआन' में बाण्ड जारी कर ऋण जुटाने की जो छूट दी गयी है। उससे भी देश में चीनी पूंजीगत वस्तुओं का आयात बढ़ रहा है।

चीन को आगे बढ़ाने के स्थान पर हमें आगे बढ़ना होगा:

आज चीन, वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग व वैश्विक निर्यातों में क्रमांक एक की शक्ति बन कर आर्थिक सुपर पावर बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सामरिक व रक्षा तैयारी में भी वह तेजी से आगे बढ़ एक वैश्विक शक्ति का स्तर पाने का प्रयास कर रहा है। हम चीनी वस्तुयें खरीद कर स्वयं का आर्थिक नुकसान कर चीन को सुपर पावर बनाने में सहायता कर अपने लिये संकट बढ़ाने का ही काम करेंगे। चीन को आगे बढ़ाने का काम करने के स्थान पर हमें स्वदेशी अर्थात 'मेड बाई भारत' या 'मेड बाई इण्डिया' वस्तुएं व सेवाएँ खरीद कर स्वयं की सामर्थ्य बढ़ानी चाहिये। चीन व हमारे बीच आर्थिक व सामरिक अन्तर पर दृष्टि डालें तो हम सभी एक मत से सहमत होंगे कि हमें एक रूपये का भी कोई चीनी उत्पाद नहीं खरीदना चाहिये। नीचे तालिका

क्रमांक 1 में भारत व चीन के बीच आर्थिक अन्तर व 2 में सामरिक अन्तर के कुछ बिन्दु दिये जा रहे हैं।

तालिका 1: भारत व चीन के आर्थिक सूचकों की तुलना

Head	China		India	
GDP	2016	**$11.2 Trillion**	**$2.2 Trillion**	2016
GDP per capita	2016	**$8,113**	**$1,701**	2016
Expenditure	2015	**$3,515 billion**	**$629 billion**	2016
Expenditure (%GDP)	2015	**31.32%**	**27.90%**	2016
Expenditure Per Capita	2015	**$2,558**	**$475**	2016
Defence Expenditure (B.$)	2015	**$217.8 billion**	**$50.1 billion**	2015
Defence Expenditure P.C.	2015	**$159**	**$38**	2015
Moody's Rating [+]	5/24/2017	**A1**	**Baa3**	11/16/2016
S&P Rating [+]	12/16/2010	**AA-**	**BBB-**	1/30/2007
Fitch Rating [+]	11/21/2016	**A+**	**BBB-**	5/2/2017
Exchange Rate Euro / Chinese yuan	7/6/2017	**7.7443**	**73.7325**	7/6/2017
Inflation: CPI (overall index)	May-17	**1.50%**	**3.60%**	Nov-16
Motor vehicle production	2016	**2.8 crore**	**44.8 lac**	2016
Vehicles / 1,000 people	2014	**104.13**	**21.62**	2014
Exports [+]	2016	**$2098 billion**	**$264.0 billion**	2016
Exports as % GDP	2016	**18.70%**	**11.70%**	2016
Imports	2016	**$1587 billion**	**$359 billion**	2016

Imports as % GDP	2016	**14.15%**	**15.91%**	2016
Trade balance	2016	**Surplus of $510.7 billion**	**Deficit of $106 billion**	2016
Trade balance as % GDP	2016	**(+) 4.55%**	**(-) 4.21%**	2016
Population	2016	**1,382,710,000**	**1,326,802,000**	2016
Life expectancy	2015	**75.99**	**68.35**	2015
Number of homicides (Murder) [+]	2012	**11,286**	**41,623**	2014
Rate Homicides per 100.000 [+]	2012	**0.8**	**3.2**	2014
CO_2 Emission: Tons per capita [+]	2015	**7.73**	**1.87**	2015

Source: http://countryeconomy.com/countries/compare/china/india

भारत व चीन के सामरिक सूचकों में अन्तर

Title	**India**	**China**
1. Active Duty Military Personnel	Regular 1.3 Million	Regular 2.3 Million (World,s Largest)
	Reserve 1.1 Million	Reserve 2.3 Million
2. Armoured Strength:		
a. Main Battle Tanks	1500	7950
b. Other Tanks	2400	1200
c. Armoured Fighting Vehicles	6500+	4600+
3. Projectiles:		
a. Self Propelled Guns	290	1710
b. Towed Guns	7500+	6246+
c. Multiple Rocket Launchers	300+	1770

4. Air Force (Fixed Wing Aircraft):		
a. Air Superiority Fighters	370+	662
b. Other/Ground Attack Fighters	258	1115
c. Transport Aircrafts	240+	782+
5. Air Force (Rotary Wing Aircraft):		
a. Helicopters (Including Army)	600+	832+
b. Attack Helicopters (Including Army)	Around 30	240+
6. Naval Prowess:		
a. Aircraft Carries	1 (With 4th Gen Aircraft)	1 (with 5th Gen stealth Aircraft)
b. Destroyers	10	26
c. Frigates	14	47
d. Corvettes	26	25
e. Submarines	15	68
f. Other Vessels	Around 87	Around 450
g. Air Arm	Fighters 39 All Others 91	Fighters 324 All Others 245
	Helicopters 232	Helicopters 114
7. Strategic Missiles	54	In Hundreds
8. Nuclear Missiles	90-100	260+

Source : http://topyaps.com/india-vs-china-military-strength

इन तालिकाओं से हमें स्पष्ट हो जायेगा कि भारत के प्रति सब प्रकार से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे चीन का एक रूपये से भी हमें आर्थिक सशक्तिकरण नहीं करना चाहिये। आर्थिक व रक्षा शब्दावली के अंग्रेजी शब्द GDP या Ballistic

Missile आदि ही अधिक चलन में होने से इन तालिकाओं में अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग किया है।

चीन-दक्षिण कोरिया विवाद से भी सीख लेने की आवश्यकता: चीन द्वारा भारत के विरोध व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के क्रम में चीन अब तक केवल मौलाना मसूद अजहर को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर ही 6 बार वीटो कर चुका है। ताज होटल के हमलावर लखवी की जमानत के बारे में भी चीन भारत के विरूद्ध वीटो कर चुका है। भारत द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी कहने का भी चीन ने कड़ा विरोध किया है। जैश ए मोहम्मद के अगुवा संगठन अल अख्तर ट्रस्ट के मामले में भी भारत के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में विरोध कर चुका है। जमात उल्दावा के मामले में भी तीन बार वीटो करने के बाद चोथी बार ही वह वीटो का उपयोग करने से दूर रहा। लश्कर के आतंकी अब्दुर रहमान मक्की व आजम चीमा के मामले में भी चीन ने 2010 में वीटो उपयोग किया था। हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को भी वीटो किया था। चीन भारत की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर चुका है। बार-बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करता है और भारतीय सीमा के अन्दर निर्माण कार्यों को भी वर्ष में कई बार बाधित करता है।

भारत के, 48 देशों के आणविक आपूर्ति समूह (न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप) में प्रवेश का भी केवल चीन ने ही विरोध किया है। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश का विरोध भी चीन ही कर रहा है। इन सब के उपरांत भी आज भारत चीन को आगे बढ़कर व्यापारिक सुविधाएं दे रहा है, चीन के पूंजी निवेश का स्वागत कर रहा है और भारत में चीन द्वारा 5 औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा व सहयोग दे रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत द्वारा पाकिस्तान में जा रहे सिंधु नदी के भारत के हिस्से के जल को रोकने की बात करने मात्र पर और पाकिस्तान के सर्जिकल कार्यवाही के विरूद्ध उसने जेग्बो नामक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का भारत का पानी ही अवरूद्ध कर दिया था। हमारा 38,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल का अक्सई चीन क्षेत्र तो

आज भी चीन के नियंत्रण में है। जब चाहे हमारी सीमा में घुस आना सेना के बंकर तोड़ देना, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को आतंकित करना आदि आम बात हैं।

दूसरी ओर इसी 2017 के मार्च महीने के प्रारंभ में दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया से सुरक्षा के लिए जो टर्मिनल हाई अल्टीट्यूट एरिया डिफेन्स मिसाइल सिस्टम (थाड मिसाइल तंत्र) तैनात किया गया है, इतनी सी बात पर एक सप्ताह भर में ही चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित संचार माध्यमों ने कोरिया के आर्थिक बहिष्कार का व्यापक आह्वान कर दिया है और दक्षिण कोरिया के विरूद्ध एक प्रकार के अघोषित प्रतिबंध की सी स्थिति उत्पन्न कर दी है। दक्षिण कोरियाई कम्पनी लोट्टे, जिसके चीन में 99 स्टोर हैं और जो चीन में 260 करोड़ डालर की लागत में थीम पार्क का निर्माण कर रही थी उसको काम बंद करने का आदेश दे दिया और उसके 79 स्टोर्स भी सस्पेंड कर दिये हैं। चीनी नागरिकों द्वारा पर्यटन हेतु दक्षिण कोरिया में जाना भी बाधित कर दिया है। चीनी ट्रेवल एजेन्सियों पर यह दबाव भी बनाया है कि वे कोरिया भ्रमण के लिये समूह भ्रमण के पैकेज बेचना भी बंद कर दें। जबकि हम भारतीय आज बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष चीन भ्रमण पर जाते हैं। बड़ी मात्रा में चीनी वस्तुओं को क्रय समर्थन देते हैं। इस दृष्टि से हमें चीन द्वारा दक्षिण कोरिया के विरूद्ध दिखलायी चीनी राष्ट्रनिष्ठा व उनकी त्वरित प्रतिबद्धता पर गौर करना चाहिए कि मिसाइल स्थापना के 10 दिन में ही चीनी सरकार, सरकारी मीडिया, स्वैच्छिक संगठनों व जनता ने कोरिया का बड़े पैमाने पर आर्थिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया हैं। भारत के लिये भी आज, चीन के उत्पादों व निवेश के विरूद्ध आज अधिक तत्परतापूर्वक कार्यवाही का समय आ गया है।

यह अत्यन्त आश्चर्यजनक ही है कि भारत के विरूद्ध 60 के दशक से जारी चीन की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के बाद भी आज हम साधारण उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों तक भारत के बाजारों पर चीन का नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया से सुरक्षार्थ तैनात की गई मिसाइलों की प्रतिक्रिया में ही चीन के सरकारी मीडिया, सरकार व आम उपभोक्ताओं ने दक्षिण कोरिया के विरूद्ध लगभग एक अघोषित आर्थिक प्रतिबंध के से हालात उत्पन्न कर दिए हैं जबकि, दक्षिण कोरिया ने ये मिसाइलें चीन को लक्ष्य करके नहीं

उत्तर कोरिया से प्रतिरक्षा के लिये तैनात की है। बस कोरिया ने यह टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेन्स मिसाइल तंत्र अमेरिका से लिया है इतनी सी बात पर चीन ने इतनी कड़ी कार्यवाही कर ली है। इसके विपरीत भारत द्वारा अपने आर्थिक व सामरिक हितों की सर्वथा अनदेखी कर हर प्रकार से चीन का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। ऐसे में दक्षिण कोरिया द्वारा तैनात मिसाइलें चीन के विरूद्ध न होकर उत्तर कोरिया से रक्षार्थ तैनात करने पर भी चीन ने दक्षिण कोरिया के विरुद्ध एक अघोषित व्यापार व वाणिज्यिक युद्ध ही घोषित कर दिया है। यह भारत के लिये एक उत्तम अनुकरणीय उदाहरण है। यदि चीनी अर्थव्यवस्था हमारे द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे बाजार के कारण वर्तमान संकट से उबर गयी, तो उसके लिये 'वन बैल्ट वन रोड़' परियोजना को पूरा करना सहज हो जायेगा। तब चीन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। इसलिये हमें चीनी वस्तुओं का परित्याग करना ही होगा। इस 'वन बेल्ट वन रोड़' परियोजना का संक्षिप्त विवेचन आगे किया जा रहा है।

यदि आज भारत अपने चीन के साथ व्यापार घाटे को शून्य कर लेता है, तो 52 अरब डालर है। साथ ही यदि, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी कर रहे है कि वे चीन के साथ जो अमेरिका का 345 अरब डालर का व्यापार घाटा है, उसे शून्य कर लेंगे। ऐसा होने पर चीन का वह सारा व्यापार अतिरेक (ट्रेड सरप्लस) ही समाप्त हो जायेगा, जिसका उपयोगकर वह आज अफ्रीका-एशिया आदि में उसकी नव उपनिवेशकारी गतिविधियों में कर रहा है। उस सरप्लस के कारण ही चीन 'वन बेल्ट वन रोड' का निर्माण कर रहा है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्ला देश, केन्या, जाम्बिया सहित एशियाई व अफ्रिकी देशों में उपनिवेशकारी निर्माण व अन्य आर्थिक सहायता के कार्यक्रम चला पा रहा है। दूसरा, यदि हम आज चीनी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, तो आज की मन्दी के दौर में कई चीनी कम्पनियाँ आज निर्यात आधारित हैं। ऐसे में यदि हम चीनी माल का बहिष्कार कर देते है एवं विश्व में अन्यत्र भी सोशल मीडिया पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाहन करते हैं। ऐसा होने पर चीन में व्यापक उद्यमबन्दी, बेरोजगारी व बैंकों के दिवालिया होने की शुरूआत हो सकती है। अब

अगले अध्याय में ‘वन बैल्ट वन रोड’ परियोजना व भारत पर उसके प्रभाव की समीक्षा की जा रही है।

अध्याय - 3

''वन बेल्ट वन रोड़'' - भारत की सम्प्रभुता को चुनौति

चीन की प्रस्तावित सिल्क रूट आधारित वन बेल्ट वन रोड परियोजना भारत के लिये गम्भीर चुनौती होगी

चीन की ''चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर'' (सी.पी.ई.सी.) परियोजना भारत के लिये पहले ही एक गम्भीर चुनौति बनी हुयी थी और अब यह 'वन बेल्ट वन रोड' के नाम से जिस सिल्क रूट को चीन बनाना चाह रहा है, उसके मार्ग में भारत का पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी आता है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के बाद चीन विश्व की सर्वाधिक ताकतवर महाशक्ति बन जायेगा। विश्व के मानचित्र पर एशिया, अफ्रिका और यूरोप तक 65 देशों को व्यापार व परिवहन की दृष्टि से जोड़ने वाले सिल्क रूट का निर्माण करने की चीन की परियोजना की बैठक में हाल ही में 100 देश सहभागी हुये हैं। इस सिल्क रूट के केन्द्र में चीन ही रहेगा और इसे लागू करने के लिये 14 और 15 मई को बीजिंग में विश्व के 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी सम्मिलित हुए। पूरे विश्व में अपनी पहुंच व प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 65 देशों को जोड़ने की चीन की इस परियोजना को 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना का नाम दिया गया है। इसी को 'न्यू सिल्क रूट' का नाम भी दिया जा रहा है। इस बैठक में भारत ने भाग भी नहीं लिया है। नेपाल, अमेरिका आदि भी भाग नहीं लेने वाले थे। लेकिन अब वे भी सम्मिलित हो गये हैं।

देश की सम्प्रभुता व क्षेत्रीय अखण्डता को चुनौति:- अतः चीन का सिल्क रूट का सपना भारत के लिये गम्भीर खतरे की घंटी बन गया है। पहले जहाँ चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही भारत के लिये मुश्किल का कारण था जहाँ चीन भी एक पक्षकार जैसी स्थिति में आ रहा है। अब 'वन बेल्ट वन रोड' के अन्तर्गत भी

पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी आता है। उस परियोजना में 65 देशों के हित जुड़ जाने से हमारा 68,000 वर्ग किमी. का सम्पूर्ण पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा और भी समस्यामूलक हो जायेगा। आज लगभग 100 देशों ने इस 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना की प्रारम्भिक बैठक में भाग लिया है। अतएव भारत को इस मुद्दे पर चीन पर दबाव भी लाना चाहिये। लेकिन भारत की सम्प्रभुता के सम्मुख इस चुनौति के बाद भी हमें चीनी उत्पाद व ब्राण्ड खरीदने चाहिये क्या? क्या प्रत्येक भारतीय को इस मुद्दे पर सम्पूर्ण विश्व में सोशल मीडिया पर भी जनमत को अपने साथ करने के प्रयास नहीं करने चाहिये क्या?

यह प्रॉजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय इलाके गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरेगा और गिलगित बाल्टिस्तान कानूनन भारत का भाग है, जो जम्मू-कश्मीर में आता है। हमारे भू-भाग को चीन अनेक देश के हित वाली परियोजना में उलझा रहा है। पहले ही पाकिस्तान वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेजकर दशकों से आतंकवाद का युद्ध चला रहा है। पहले ही चीन, पाकिस्तान को लंबे समय से वहाँ सब प्रकार का समर्थन देता रहा है। अब OBOR के चलते दक्षिण एशिया में चीनी सेना का दखल भी बढ़ेगा। यह भारत की सबसे अधिक समस्याएँ खड़ी करेगा। चीन आज जब पीओके में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, तब फिर कश्मीर को लेकर चीन भी एक पार्टी के तौर पर आने वाले वक्त में खड़ा हो कर अड़ंगा लगा सकता है। ओबोर से तो वह हमारे लिये जटिताएँ और बढ़ा देगा।

भारत को घेरने का भी साधन

आज भारत के सभी पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश आदि चीन के इस सिल्क रूट का समर्थन कर रहे है। क्योंकि चीन, बांग्लादेश को हथियार और पैसा दोनों दे रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भारी भरकम निवेश कर रहा है। श्रीलंका में चीन के बंदरगाह निर्माण के कदम से कुछ भारतीय विश्लेषक चिंतित हैं और वह इसे 'मोतियों की डोरी' (स्ट्रिंग आफ पर्ल्स) बताते हैं, जो भारत को घेरने के लिये है। भारत ने सार्क के माध्यम से दक्षिण एशिया में जो अपनी पकड़ बनायी है, सिल्क रूट के जरीये चीन उसमें भी सेंध लगाना चाह रहा है.

चीन आर्थिक रूप से भी अत्यन्त शक्तिशाली हो जायेगा

विश्व मानचित्र पर चीन के नियन्त्रण वाले व 65 देशों को जोड़ने वाले इस सिल्क रुट के पूरा होने से विश्व के बाजार पर चीन का और भी सशक्त कब्जा। इसके छह कॉरिडोर होगें जो आपस में मिलेगें और विश्व के सबसे बड़े बाजार का निर्माण करेंगे। ये छः कॉरिडोर निम्न होंगे।

(1) चीन, मंगोलिया, रुस, कॉरिडोर

(2) न्यू यूरोशिया लैंड कॉरिडोर

(3) चीन, सेन्ट्रल एशिया, पश्चिमी एशिया कॉरिडोर

(4) चीन, पाकिस्तान, इकोनॉमिक कॉरिडोर

(5) बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार कॉरिडोर

(6) चीन-इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर

इस योजना के सहारे चीन विश्व के 65 देशों में सीधे निवेश कर सकेगा और उनकी अर्थव्यवस्था को अपने हितों के अनुसार संचालित करने में सफल होगा। यदि विश्व अर्थव्यवस्था में चीन अपने सामानों को बेचने के लिए स्थायी बाजार बना लेगा। चीन के अंदर निर्मित माल पूरी दुनियाँ में छा जायेगा। इन्हीं कॉरिडोरों के लिये अब बीजिंग में 50 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते संचार, ऊर्जा और ट्रासपोर्टेशन के क्षेत्र में 29 देशों से साथ के साथ होंगे।

पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ का भारत दशकों से सामना कर रहा है और इस 'वन बेल्ट वन रोड' के कारण आने वाले वर्षों में सिर्फ भारत की सुरक्षा चुनौतियों को ही बढ़ाएगा और चीन की इन चालों के काट के लिए रीति-नीति खोजनी होगी। गिल्गिट बाल्टीस्तान में भारत की सम्प्रभुता को चुनौति देते हुये यह सब चीन, भारत के

विरोध के उपरान्त भी कर रहा है। चीन ने तो ईरान के साथ हुये चाबहार समझौते को भी भारत से छीनने के पूरे प्रयास किये थे।

चीन के दुनिया पर दबदबा बनाने के लिये अभी भी एक ऐसी चाल चली है, कि वहाँ साम्यवादी शासन की 2049 में एक शताब्दी पूरी होने तक उसे विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाने में अचूक सिद्ध होवे। चीन की इस नई चाल का लाभ है OBOR यानि वन बेल्ट वन रोड।

अपनी योजना में चीन बड़ी सीमा तक सफल भी हो गया है उसने प्रमुख यूरोपीय देशों फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलंड, बेलारूस, रूस, व अमेरिका सहित कजाखस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल तक को इस योजना में शामिल कर लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों का मानना है कि वन बेल्ट वन रूट के बहाने चीन विश्व पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, और उसे यूरोप तक घुसपैठ सफलता मिल गयी है। इसमें उसने 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, 70 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों, दुनिया भर के 100 मंत्रिस्तरीय अधिकारियों, विभिन्न देशों के 1200 प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित किया था। मना करते करते भी अमेरिका तक इस बैठक में सम्मिलित हो गया है।

1400 अरब डालर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का स्वरूप: यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर चीन की विश्व अर्थव्यवस्था पर सशक्त पकड़ करा देगा। यह ओबीओआर लगभग 1,400 अरब डालर की परियोजना है। चीन इस ड्रीम प्रोजेक्ट को 2049 तक पूरा करना चाहता है। 2014 में आई रेनमिन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नई सिल्क रोड परियोजना करीब 35 वर्ष में यानी 2049 तक पूरी होगी। इस प्रकार चीन उसके साम्यवादी शक्ति बनने की अपनी 100 वीं वर्षगांठ को अभिमान व गौरव के साथ मनाने की तैयारी कर रहा है।

इस ओबीओआर के दो मार्ग (रूट) होंगे। पहला भूतल मार्ग अर्थात लैंड रूट होगा जो चीन को मध्य एशिया के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगा, इसे कभी सिल्क रोड

कहा जाता था। दूसरा मार्ग (रूट) सामुद्रिक होगा जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका होते हुए यूरोप से जोड़ेगा, जो न्यू मैरिटाइम सिल्क रोड कहा जायेगा।

सात देशों की अर्थव्यस्था से चीन जुड़ भी चुका है-:

हाल ही में 29 अप्रैल 2017 को प्रयोग के रूप में 12 हजार किलोमीटर लंबा फासला तय कर पहुंची अपनी ट्रेन का चीन ने भारी समारोहिक स्वागत किया है। विश्व के इस दूसरे सबसे लम्बे रेल मार्ग पर लंदन से चली यह ईस्ट विंड मालगाड़ी 20 दिनों में पूर्वी चीन के यिवू शहर पहुंची। 30 डिब्बों वाली ट्रेन में व्हिस्की, सॉफ्ट ड्रिंक, विटामिन और दवाइयां थी। यह मालगाड़ी फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस और कजाखस्तान से होते हुए चीन पहुंची। पहला सबसे बड़ी रूट भी चीन केन्द्रित ही है।

अभी चीन के यिवु शहर से स्पेन के मैड्रिड तक बना रेलवे रूट आज विश्व का सबसे लंबा रेल रूट है, इसकी लंबाई करीब 13 हजार किलोमीटर हैं। अब चीन इसे दक्षिण पूर्व एशिया से भी जोड़ लेगा। इससे पहले चीन ने 18 नवम्बर 2014 को भी ऐसी ही एक 82 डिब्बों वाली मालगाड़ी को 21 दिनों में लगभग दस हजार किलोमीटर दूर स्पेन की राजधानी मैड्रिड भेजा था। अक्टूबर 2013 में भी चीन ने 9820 किलोमीटर दूर जर्मनी के तटीय शहर हैम्बर्ग तक एक ट्रेन भेजी थी। इन सभी रेल मार्गों से चीन का जबरदस्त आर्थिक सशक्तिकरण होगा।

बीसीआईएम के लिये भी चीन का अनुचित दबाव

चीन चाहता है कि भारत भी उसके सिल्क रूट का हिस्सा बनें और बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) गलियारे का स्वीकृति दे दे। इसके लिए चीन भारत पर अनुचित दबाव भी डालने की कोशिश में हैं, लेकिन भारत ने इस पर पहले ही इससे इनकार कर दिया है। वस्तुतः बीसीआईएम भी चीन के प्रस्तावित सिल्क रूट का हिस्सा है जो भारतीय स्वामित्व वाले कश्मीर से बिना भारत की अनुमति के ही जा रहा है। बीसीआईएम के लिए सहमति देने का मतलब ही है भारत के बाजारों पर चीनी सामानों

का और व्यापक आक्रमण। फिर चीनी माल भारत में बांग्लादेश और म्यांमार के मार्ग से भी आ जायेगा।

OBOR को आंशिक टक्कर भारत-रूस का ग्रीन कारिडोर देगा।

भारत और रूस भी अब साथ मिलकर दोनों देशों के बीच 7200 किलोमीटर लंबा ग्रीन कारिडोर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह ग्रीन कारिडोर भारत और रूस की मैत्री के 70 साल पूरे होने के अवसर पर शुरू होगा। यह ग्रीन कारिडोर ईरान होते हुए भारत और रूस को जोड़ेगा, इसके साथ ही भारत यूरोप से भी जूड़ेगा। यह सब चाबहार समझौते से सम्भव हुआ है। उसे (चाबहार समझौते को) भी भारत से छीनने के चीन ने अथक प्रयास किये थे। यह परियोजना वन बेल्ट वन रोड़ का भारतीय तोड़ है, जो भारत व यूरेशिया के बीच व्यापार व परिवहन के व्यय को कम करेगा। इस परियोजना में रेल, सड़क व सामूद्रिक मार्ग तीनों का उपयोग होगा। इससे भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया व यूरोप के बाजारों तक आसानी से व्यापार बढ़ा सकेगा।

चीन का बढ़ता औपनिवेशिक विस्तार:-

आज अफ्रीका के लगभग एक तिहाई प्राकृतिक संसाधनों पर चीन का स्वामित्व हो गया है। अफ्रीका व लेटिन अमेरिका का आज सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन हो गया है। अफ्रीका या आस्ट्रेलिया में बड़ी मात्रा में चीनी नागरिक बसे हुए है। चीन आज श्रीलंका, म्यांनमार, बांगलादेश, नेपाल व पाकिस्तान के साथ सघन आर्थिक व सामरिक गठबन्धन करने की ओर भी बढ़ रहा है। चीन द्वारा प्रवर्तित एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इनवेस्टमेन्ट बैंक (AIIB), जिसमें 57 देश सदस्य है, उसका चीन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसलिये (AIIB), के ऋणों का वितरण चीन के नियंत्रण में रहेगा। ऐसा होने से सम्पूर्ण एशिया पर चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा। वन बेल्ट वन रोड से चीन के सम्भावित वर्चस्व की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इन सबसे चीन एक नई औपनिवेशिक सत्ता के रूप में उभर सकता है। लेकिन यदि भारत और अमेरिका चीन के साथ अपना व्यापार घाटा शून्य पर लाने में सफल हो जाते हैं। तब चीन का सारा व्यापार अतिरेक (Trade Surplus) समाप्त हो कर घाटे की स्थिति बन सकती है। तब फिर चीन की एक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा भी विफल हो सकती है।

संसाधनों पर नियंत्रण और आर्थिक, तकनीकी व सामरिक उपनिवेशवाद:- चीन वर्तमान में अपने लिये कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों का विविधीकरण करने, अपने अल्प मूल्य के उत्पादों से विदेशी बाजारों पर इस प्राकर नियंत्रण करने की स्थानीय स्पर्द्धा समाप्त हो जाये, उसकी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों का निरन्तर काम मिलता रहे व अपनी सामरिक व सब प्रकार से शक्ति का वर्चस्व स्थापित करते हुये पूर्वी व पश्चिमी गोलार्द्ध दोनों में शीर्ष शक्ति के रूप में उभरना।

चीन वर्तमान में चार प्रकार के लक्ष्यों पर काम कर रहा है -

1. अपने लिए कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों का अधिकतम विविधीकरण करने में लगा हुआ है। ऊर्जा के स्रोतों से लेकर खनिज संसाधनों के लिए चीन, एशिया, लेटिन अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि सभी प्रमुख महाद्वीपों के अधिकतम देशों में संसाधनों में निवेश कर उन पर अपना स्वामित्व व नियंत्रण कर रहा है। इससे वह विविध देशों में चीन को आपूर्ति के लिये एक स्पर्द्धा निर्माण करता जा रहा है। इन देशों में सारा खनन व उत्पादन वह अपने संयंत्र, श्रम व कम्पनियों के माध्यम से करने को प्राथमिकता दे रहा है। इससे कई देशों में उसके विरूद्ध, वहाँ के स्थानीय जन समाज व शासन भी असहाय अवस्था में होने तक का अनुभव करने लग जायेंगे।

2. विश्व के विविध देशों के विविध उत्पादों के बाजारों पर इस प्रकार एकाधिकार करना कि वहां के स्थानीय उद्योग बन्द हो जाये व चीनी उत्पादों के लिये एक-एक कर स्थानीय स्पर्द्धा पूरी तरह समाप्त हो जाये। ऐसा एकाधिकार निर्माण करने तक अपने उत्पाद लागत से अल्प मूल्य पर बेचना और उस देश की स्थानीय स्पर्द्धा समाप्त होने के बाद मूल्य बढ़ा कर शोषण करना।

3. चीन जहाँ-जहाँ भी संभव है प्रत्येक देश में व्यापक स्तर पर अपने व्यय पर व अपनी श्रम शक्ति से अवसंरचनाओं यथा मल्टीलेन राजमार्गों, रेल मार्गों, बन्दरगाहों, हवाई अड्डों, विद्युत जनन संयंत्रों, न्यूक्लियर प्लांट, कण्टेनर टर्मिनल आदि का निर्माण कर रहा है। उसके उपरांत उस निवेश के बदले उन अवसंरचनाओं पर अपना अधिपत्य स्थापित कर उसके बदले अपनी कई शर्तें आरोपित कर उस देश के संसाधनों को

अपने नियंत्रण में लेता चला जा रहा है। हाल ही में उसने श्रीलंका व कई अफ्रीकी देशों की ऐसी ही ब्लेकमेलिंग प्रारंभ कर दी है।

4. विश्व के सभी भागों में अपने सामरिक व सैन्य अड्डे विकसित करना।

यदि हम लेटिन अमेरिका अफ्रीका व आस्ट्रेलिया पर चीन के बढ़ते वर्चस्व पर विचार करें तो आज चीन-लेटिन अमेरिका व्यापार में 2000 के बाद 25 गुनी वृद्धि तो हुयी है। 2025 तक इसे 500 अरब डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। भारत-लेटिन अमेरिका व्यापार मात्र 49 अरब डालर ही है। वर्ष 2014 में ही चीनी विकास बैंक व एक्सिम बैंक ने मिलकर 29 अरब डालर के ऋण दिये हैं। वहाँ चीन का निवेश आज 100 अरब डालर तक पहुँच गया है, उसे 2025 तक 250 अरब डालर करने का लक्ष्य है। उदाहरणतः चीन ने इक्वाडोर नामक लेटिन अमेरिकी देश में अपने अनुभव व संसाधनों से एक अतिविशाल जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया है जो इक्वाडोर की 35 प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करता है। इक्वाडोर की सरकार की 2014 की 61 प्रतिशत ऋण पूर्ति के बदले में उसका 90 प्रतिशत खनिज तेल हथिया लिया। इसी क्रम में अर्जेण्टाइना में उसने दो न्यूक्लिअर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के साथ उसे 20 लड़ाकू विमान व कई नौसैनिक गश्ती जलपोत एक अरब की लागत पर दिये हैं। कोलम्बिया में राजमार्ग निर्माण, ब्राजील में कण्टेनर पोर्ट का निर्माण आदि अवसंरचना विकास के अनगिनत उदाहरण है।

लेटिन अमेरिकी देशों को वर्ष 2005 से 2015 के बीच चीन ने 125 अरब डालर के ऋण दिये हैं। जो लेटिन अमेरिका के जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के बराबर है। आज चीन लेटिन अमेरिका से इतना दूर होते हुए भी दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ब्राजील का वह सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। चीन-ब्राजील व्यापार आज 78 अरब डालर का है और ब्राजील के 18 प्रतिशत व चिली के 24.4 प्रतिशत निर्यात चीन को हो रहे हैं।

आज आस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि व आबादी भूमि का बड़े पैमाने पर चीन, चीनी कम्पनियाँ व चीनी नागरिक निवेश कर रहे हैं। चीन-आस्ट्रेलिया व्यापार भी आज

120 अरब डालर के निकट है। भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार मात्र 20 अरब का ही है। आस्ट्रेलिया में 2016 में सर्वाधिक विदेशी निवेश 47.3 अरब डालर चीन का था। इसमें 31.9 अरब डालर रीयल एस्टेट अर्थात भू-सम्पदा में था। चीन के 30,611 भू-सम्पदा खरीददारों को आस्ट्रेलियाई विदेशी निवेश बोर्ड ने अनुमोदन किया है। चीन आस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि व कृषि फार्म भी खरीद रहा है। पिछले वर्ष आस्ट्रेलिया का 70,000 हेक्टर (700 वर्ग किमी) का सबसे बड़ा गेहूँ का फार्म भी एक चीनी कम्पनी ने ही 2.4 करोड़ डालर में खरीदा है। चीन आज आस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि भूमि धारक देश बन गया है। पूर्व में इंग्लैण्ड के बाद दूसरा स्थान अमेरिका का था। आज चीन तेजी से आस्ट्रेलियाई जमीने खरीद रहा है। आवासीय मकानों की खरीद में चीन पहले स्थान पर है। एक तिहाई से अधिक नये मकान चीनी लोग खरीद रहे हैं। चीन, न्यूजीलैण्ड में भी इसी स्तर पर कृषि भूमि खरीद रहा है, अफ्रीका में भी चीन बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीद रहा है। विश्व की 60 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि अफ्रीका में है।

आज यदि चीन द्वारा एक नव उपनिवेशवादी सत्ता की तरह व्यापार, निवेश, सैन्य बल विस्तार, शस्त्रास्त्रों के उत्पादन, सैन्य अड्डों की स्थापना, वैश्विक संसाधनों पर नियंत्रण एवं विविध देशों को अपनी विदेश नीति के हस्तक या टूल के रूप में प्रयुक्त कर अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। उसके विपरीत हम सभी देशों को उसके चंगुल से मुक्त करना है तो सभी प्रकार के उत्पादों को सुलभ करने अवसंरचना विकास आदि के उपक्रम हमें विकसित करने होंगे।

यदि चीनी उत्पादों को हम खरीदते चले गये तो हम कभी भी विश्व को विकल्प नहीं दे सकेंगे। यदि वे सारे उत्पाद व अवसंरचनाओं के विकास सामर्थ्य हमें विकसित करनी होंगी। लेकिन चीनी उत्पादों को खरीदना बन्द कर, ये सबकुछ हमें विकसित करने होंगे। हम चीनी पेन, बल्ब, सोलर पेनल, कम्प्यूटर, मोबाइल पावर प्लाण्ट से ले कर रेलों के उपकरण चीनी खरीदेंगे तो देश के इन क्षेत्रों के उद्योग बन्द होंगे व हम एक उद्योग रहित व प्रौद्योगिकी विहीन देश बनने की ओर अग्रसर होंगे। दूसरी ओर हमने

चीन उत्पादों के स्थान पर भारतीय उत्पाद खरीदे तो अपने देश में इन उद्योगों का विकास होगा और हम भी विश्व बाजारों में ये ही उत्पाद बेचने की स्थिति में आयेंगे।

चीन-अफ्रीका व्यापार व निवेश के साथ-साथ चीन अफ्रीका में अपने सैन्य अड्डे भी विकसित कर रहा है। अफ्रीकी देशों को सहायता को भी वह संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्बन्धित देशों द्वारा चीन को दिये जाने वाले समर्थन के अनुरूप ही चीन विविध देशों को सहायता देता है। चीन की विदेश नीति के समर्थन में खड़े होने के अनुपात में ही वह अफ्रीकी, लेटिन अमेरिकी व एशियाई देशों को सहयोग देता है और उनकी ब्लेकमेलिंग भी करता है। यथा दक्षिण अफ्रीका को 2014 में चीन ने इस बात के लिये बाध्य कर लिया कि उसने बौद्ध गुरू व तिब्बत की निर्वासन में बनी सरकार के प्रमुख श्री दलाई लामा के पूर्व निर्धारित प्रवेश की अनुमति को निरस्त कर दिया। इसी प्रकार 2014 में ही केन्या को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि उसने अपने यहाँ से 50 ताइवानी नागरिकों को निर्वासित कर दिया, जो वहाँ वैद्य वीसा लेकर आये थे। ''साओ टोम एण्ड प्रिन्सिपल'' नामक अफ्रीकी देश को तो ताइवान से राजनायिक सम्बन्ध ही विच्छेद करने को बाध्य कर लिया। अफ्रीकी देश ''जीबूती'' में तो उसने अपना सैन्य अड्डा ही विकसित कर लिया है, जो उसे ''रेड सी'' एवं हिन्द महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनायेगा। उसका यह सैन्य अड्डा अमेरिकी सैन्य अड्डे 'अफ्रीकाम' से मात्र 10 मील की दूरी पर ही है। भारत को घेरने के लिए तो चीन ने पाकिस्तान में ग्वाडर, बाग्लादेश में चटगाँव, म्याँमार के द्वीप, श्रीलंका में हम्बनतोटा आदि बन्दरगाहों पर अपनी सैन्य उपस्थित बना रहा है। ग्वाडर में तो उसने अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है।

चीन के औपनिवेशिक विस्तार के समाजशास्त्रीय आयाम-:

चीन जहाँ भी निर्माण कार्य व उत्पादक उद्योगों का संचालन कर रहा है, वहाँ वह चीनी श्रमिक नियोजित कर रहा है। उनमें बड़ी संख्या में वहाँ की जेलों के बन्दी है। उनकी सजा की अवधि पूर्ण होने पर वह उन्हें वहीं बसाता जा रहा है। ऐसा वह अफ्रीका में विशेष रूप से करता जा रहा है। अब वे बन्दी वही अफ्रीकी महिलाओं से विवाह रचा

कर उन देशों में एक समाजशास्त्रीय परिवर्तन ला रहे हैं। एक चीनी द्वारा वहाँ अफ्रीकी महिलाओं से विवाह कर लेने पर उसका संबंध उस पूरे कबीले से हो जाता है। इस प्रकार चीन अपना समाजशास्त्रीय विस्तार भी कर रहा है। अब वह 65 देशों में 'वन बल्ट वन रोड' परियोजना का निर्माण करने वाला है, उसका निर्माण भी वह प्राथमिकता से अपने ही निवेश व अपनी ही श्रम शक्ति से करने वाला है। चीन की सरकार आज पूरे विश्व में कन्फ्यूशियस केन्द्र चलाने के लिये भी आर्थिक सहायता दे रही है। भारत में भी कई विश्वविद्यालय ऐसे केन्द्र, चीनी सहायता से चला रहे हैं।

भू-राजनैतिक सन्तुलन की आवश्यकता

चीन ने विगत एक दशक में विश्व के सभी भागों में, विभिन्न देशों के साथ अपने आर्थिक समझौतों व सैन्य सहयोग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ किया है। उनके बाजारों में अपनी पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ, अपने लिये ऊर्जा सुरक्षा व कच्चे माल की आपूर्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त इन देशों के साथ उसके सम्बन्धों में उपजी प्रगाढ़ता के फलस्वरूप उसका भू-राजनीतिक वर्चस्व भी पर्याप्त रूप से बढ़ा है। पारम्परिक रूप से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ रहने वाले कई देशों के साथ चीन के पारस्परिक अन्तनिर्भरता वाले आर्थिक सम्बन्ध और इन देशों की चीन से बढ़ती निकटता के बाद वे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर किसके साथ रहेंगे, यह भी विचारणीय है। वस्तुतः चीन आने वाले समय में अपने लिए रामेटेरियल सिक्यूरिटी, एनर्जी सिक्यूरिटी जैसे सुरक्षा के सभी प्रमुख आयामों पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। अभी सऊदी अरब के साथ उसके गैस और तेल को खरीदने के लिए चीन ने 30 साल का अनुबंध किया है। अफ्रीका में एक दर्जन से अधिक ऐसे शासक हैं जहाँ पर स्थानीय आन्दोलन बहुत होते हैं, स्थानीय आन्दोलनों के विरूद्ध छोटे हथियारों की आपूर्ति व वहाँ के कुछ शासकों को व्यक्तिगत ऋण देने के बदले में अफ्रीका के लगभग एक तिहाई तेल भण्डारों सहित बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के खनिज संसाधनों को चीन ने अधिगृहीत किया है। आने वाले 70-80 वर्षों की अपनी कच्चे माल की आपूर्ति व ऊर्जा सुरक्षा (रामेटेरियल और

एनर्जी सिक्योरिटी) उसने कर ली है। चीन का प्रभाव अफ्रीका में इस सीमा तक बढ़ा है कि कई अफ्रीकी देशों के अनेक शहरों में 'चाईना टाऊन' बनने लग गये हैं, जहाँ पर अब वहाँ के स्थानीय अफ्रीकी लोगों का भी प्रवेश निषेद्ध है। आज अधिकांश अफ्रीकी देशों में सारे के सारे उत्पाद चीन के ही बिक रहे हैं, यूरो अमेरीकी व भारतीय उत्पाद गायब हो रहे हैं। आज अफ्रीका के लगभग एक दर्जन देशों में उनके विकास और निर्माण के सारे कार्य अब चीनी ही कर रहे हैं। कई अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिन्होंने यह राज्याज्ञा जारी कर रखी है कि उनके देश का 70 प्रतिशत निर्माण का काम चीनी कम्पनियों को ही जायेगा। कई ऐसे अफ्रीकी देश हैं जैसे जिम्बाब्वे, इक्वेटोरियल गिनी, सूड़ान आदि, जहाँ स्थानीय आन्दोलनों को कुचलने के लिए चीन के द्वारा कर्ज में दिये हथियारों का खुल कर उपयोग हुआ है। इसी कर्ज के बदले में उसे अफ्रीकी संसाधनों पर स्वत्व मिल रहा है। इन सभी देशों को छोटे हथियारों की अपूर्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगा रखा था। उस प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए वह इन शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति करता रहा है। हमको ध्यान में होगा कि सूड़ान के विभाजन के पूर्व, वहाँ 20 लाख, गैर अरब मूल के किसानों पर चीनी हथियारों और चीनी सैन्य विशेषज्ञों की सहायता से इतने भयावह अत्याचार हुए थे कि अब दक्षिणी सूडान ही अलग हो गया हैं। वहाँ तब साढ़े तीन लाख लोग हत्या, बलात्कार, जिन्दा जलाये जाने आदि के शिकार हुए थे। चीन के प्रभाव मे इक्वेटोरियल गिनी नामक देश है वहाँ पर तख्ता पलट हुआ तो नये राष्ट्रपति ने स्वयं पुराने राष्ट्रपति को एक बहुत बड़े आडिटोरियम में एक पिंजरे से लटकाकर सार्वजनिक रूप से गोली मारी थी।

चीनी शस्त्रास्त्रों के सहयोग से जहाँ मानवाधिकारों का इस तरह से नृशंस हनन हो रहा है उसी चीन के उत्पाद अगर पूरे विश्व में बिकें तो यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है। हमारे देश में भी आज इन्टरनेट पर सवांद करने वाले लोग बड़ी संख्या में बढ़े है। अगर हम चीन के सहयोग से मानवाधिकारों का जो नृशंस हनन हो रहा है, इसके विरूद्ध एक आव्हान नेट पर करें तो चीन के सारे के सारे उत्पादों की बिक्री का बहिष्कार न केवल अपने देश में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में सम्भव है। इन्टरनेट का उपयोग

करते हुए अपने घर बैठकर बिना युद्ध लड़े आराम से यह किया जा सकता है। भारत में नेटीजन्स (Netizens) की बड़ी संख्या है।

कई अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले 25 साल में 2 करोड़ चीनीयों को अफ्रीका में बसाने की भी चीन की अपनी वैकल्पिक योजना है। वहाँ पर उसने बड़ी मात्रा में संसाधनों का अधिगृहण किया है, अब वहाँ बड़ी संख्या में चीनी उद्योग व अन्य प्रतिष्ठान लग रहे हैं व दीर्घ परियोजनाएँ चल रहीं हैं। अफ्रीका के कई देशों में 70 प्रतिशत निर्माण के प्रोजेक्ट उसके हाथ में है, वहाँ चीन बड़ी मात्रा में टेक्नोक्रेट्स, कार्मिक, श्रमिक व बंधुआ मजदूर ले जा रहा है। विश्लेषकों के ऐसे भी आकलन हैं कि वह अपने यहां पर जेलों में बन्द कैदियों को भी ले जा रहा है। जिस कैदी की जितने वर्ष की जेल की सजा शेष है, उतना समय वह वहाँ अवैतनिक काम करेगा, उसके बाद में उसे वहीं बसा दिया जायेगा। आज भी पूरे अफ्रीका में ऐसे 12-20 लाख लोगों के होने का अनुमान है।

अफ्रीकी जनता भी चीनी उत्पादों के एकाधिकार से बहुत परेशान है। चीनी उत्पादों के लिए अफ्रीकी लोग जो शब्द काम में लेते हैं वह है (Zing-Zong) जींग-जांग अर्थात् जब तक चले जींग और जब खराब हो जाए जोंग। वहां जिन जहाजों चीनी माल जाता है उसे वहाँ पर खाली करते है और अफ्रीका के आन्तरिक क्षेत्रों से जो खनिज पदार्थ लेकर ट्रक आते हैं (अर्थात् अफ्रीका के आन्तरिक क्षेत्रों से वहाँ तांबा, सीसा आदि सभी खनिज पदार्थ लेकर आते) उसे चीनी जहाजों पर लाद दिया जाता हैं और चीनी साज सामान उन ट्रकों में लद कर अफ्रीकी बाजारों में पहुँच जाता है।

आज दुनिया का 70-80 प्रतिशत जो तांबा आदि खनिज हैं, उनका उपयोग चीन कर रहा है क्योंकि चीन विश्व के महानुमाप उत्पादन (मैन्यूफैक्चरिंग) के केन्द्र के रूप में उभरता जा रहा है। इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण भी चीन ही फैला रहा है। विश्व मे प्रदूषणकारी ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन चीन का है। ये प्रदूषणकारी गैसें जिनमें विशेष हैं। कार्बनडाई आक्साईड, कार्बन मोनो आक्साईड, मिथेन, सल्फर डाइ आक्साईड, नाईट्रस आक्साईड आदि जो वायु मण्डल में, उत्सर्जित

हो रही उसमें सर्वाधिक 21 प्रतिशत चीन का उत्सर्जन है। चीन इतना ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है कि सभी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यक्ति चीनी प्रोडक्ट्स का खुशी-खुशी बहिष्कार करेंगे। चीन की प्रौद्योगिकी भी इतनी प्रदूषणकारी है कि उसके बहिष्कार का आव्हान बड़े आसानी से किया जा सकता है।

चीन ने पूरी दुनिया में उद्योगों के अधिग्रहण की भी एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है जिससे विश्वभर में उसका ही व्यावसायिक जाल खड़ा हो जायेगा। लिनोवो चीन की कम्प्यूटर बनाने वाली कम्पनी है। अपने देश में भी लिनोवो के कम्प्यूटर आजकल सर्वाधिक बिकते हैं। उसी लीनोवो कम्पनी ने, अमेरिका की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी एवं प्रतिष्ठित कम्प्यूटर कम्पनी 'इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स' (आई.बी.एम.), का पर्सनल कम्प्यूटर डिवीजन खरीद लिया था। इस तरह से चीन अमरीका व यूरोप में निरन्तर कम्पनियों का अधिग्रहण कर रहा है। इसी क्रम में उसने अमेरिका की ऊर्जा के क्षेत्र की महत्वपूर्ण कम्पनी 'यूनोकल' को साढ़े अठारह अरब डॉलर में (चीन की एक सरकारी कम्पनी ने) खरीदने की पेशकश कर दी थी। वह कम्पनी बिकने को थी, अमेरिकी सीनेट में कई बार इस बात पर चर्चा हुई कि यदि इस यूनोकल कम्पनी को चीनी सरकारी कम्पनी ने खरीद लिया तो अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा चीनियों के हाथ में पड़ जायेगी। अन्त में अमरीकी सीनेट में चर्चा के बाद यह चेतावनी देनी पड़ी कि यदि चीन अपने क्रय प्रस्ताव को वापस नही लेता है तो हमको संसद से अर्थात सीनेट से कानून बनाकर इस अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाना होगा। आज अमेरिका जैसा देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के प्रति इतना चिन्तित और सजग है जबकि चीन उसकी सीमा से बहुत दूर है। ऐसे में आज हम बड़ी संख्या में अपने पावर प्लान्ट, अपनी सारी टेलिफोन सेवाएँ प्रमुख राजमार्गों व अन्य निर्माण कार्य आदि में चीन पर अवलम्बित हो रहे हैं। एक प्रकार से चीन पर हमारा यह अवलम्बन हमारे लिए और ज्यादा चिन्ता का विषय होना चाहिये। इसी क्रम में आज चीन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों (साऊथईस्ट एशियन कन्ट्रीज) में भी आब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया है, जिससे एसोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स में चीन का वर्चस्व बढ़ा है। इसी प्रकार से एशिया के नौ बड़े देश, जिनको ए-9 कहा जाता है, उनका व्यापार अमेरिका

की तुलना में भी चीन से ज्यादा बढ़ा है। लेटिन-अमेरिका के साथ चीन का व्यापार मात्र 5 अरब डॉलर का था वह आज 2017 में 310 अरब डॉलर का हो गया है। जबकि भारत लेटिन अमेरिकी व्यापार आज भी मात्र 49.1 अरब डालर ही है। अफ्रीका के साथ उसका व्यापार 2000 तक केवल 50 लाख डॉलर का था, वही 2012 में वह 200 अरब डॉलर व 2015 तक 280 अरब डालर तक पहुँच गया था। जबकि अमरीका व अफ्रीका व्यापार मात्र 108 अरब डालर रह गया है। भारत-अफ्रीकी व्यापार चीन-अफ्रीकी व्यापार के 1/6 से कम, 2016-17 में मात्र 52 अरब डालर ही है। जबकि पूर्व मे 'भारत-अफ्रीका' व 'भारत-लेटिन अमरीका' व्यापार, चीन से इन देशों के व्यापार से अधिक रहा है। हमारे उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने भी इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। घटते व्यापार का भारत-अफ्रीका मैत्री पर भी प्रभाव होता है। यही बात हमारी लेटिन अमरीकी देशों के साथ भी लागू होती है। वैसे भी सिविल सोसाइटी आन्दोलन से उपजे वर्ल्ड सोशल फोरम और नव वामपंथ की गुलाबी लहर से लेटिन अमरीका के लगभग एक दर्जन देशों में बनी वामपंथी सरकारें भी चीन से अधिक निकट सम्बन्ध बनाये हुये हैं। इसलिये भारत-लेटिन अमरीकी व्यापार व मैत्री सम्बन्धों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। चीन ने व्यापार विस्तार के साथ ही लेटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देशो के साथ करेन्सी स्वॉप के एग्रीमेन्ट भी किये हैं। करेन्सी स्वॉप यानि वह अब डॉलर में व्यापार नहीं करेगा। यथा अर्जेन्टाईना के साथ चीन के करेन्सी स्वॉप समझौते के बाद अब चीनी मुद्रा यूआन और अर्जेन्टाईना की में उनका व्यापार होगा। आज यूनाईटेड अरब-अमीरात व सऊदी अरब का अधिकांश तेल चीन खरीद रहा है। इन सभी व्यापारिक प्रगाढ़ता के सम्बन्धों के कारण उनके कूटनीतिक सम्बन्ध इन सभी देशों से इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि अब तक सारे अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर जहाँ सभी विकासशील देश भारत के साथ मतदान करते रहे हैं, अब आने वाले समय में हमारे लिए यह एक चुनौति होगी। पारम्परिक रूप से हमारे मित्र देशों का जो समूह था, उनमें से बड़ी संख्या में देश चीन के निकट होते जा रहे हैं। 'ऑर्गेनाईजेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज' के नाम से 57 इस्लामिक देशो का जो संगठन है, उसने अब तक कश्मीर के लिए कभी भी यह नहीं कहा कि कश्मीर भारत का अंग नही है। अब उसने उस पर प्रश्न उठाना आरम्भ कर ''भारत अधिकृत कश्मीर''

जैसे शब्दों का प्रयोग आरम्भ कर दिया है। इस प्रकार हमारे कूटनीतिक सम्बन्धों की दृष्टि से भी चीन चिन्ता बढ़ा सकता है।

अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और लेटिन अमेरिका में, सर्वत्र चीन का प्रभाव एवं वहाँ अधिकाधिक देशों के साथ उसकी व्यापारिक व आर्थिक सम्बन्धों में सघनता अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। इस प्रकार भारत के चारों ओर स्थित देशों से संरक्षक व संरक्षित जैसे सम्बन्ध बना कर चीन भारत की घेराबन्दी कर रहा है और सुदूर देशों में भी उसका प्रभाव बढ़ रहा है। साथ ही देश के अन्दर जिस ढंग से चीनी कम्पनियों का अन्तर्जाल फैल रहा है, और हमारे द्वारा बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादों की खरीद कर चीन को जो आर्थिक सम्बल दिया जा रहा है, इसे देखते हुये हमें भू-राजनैतिक, आर्थिक व रणनीतिक दृष्टि से पुनर्विचार करना चाहिये और हमें अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नया धरातल देना होगा।

पर्यावरण और मानवाधिकार संकट :- विश्व के वातावरण परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान का एक प्रमुख कारण चीन द्वारा फैलाया जाने वाला प्रदूषण है। विश्व में जो कुल कार्बन-डाई-ऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का 9.8 गीगा टन का उत्सर्जन है। उसमें से 4 गीगा टन अकेले चीन द्वारा किया जा रहा है। चीन अमेरिका की दुगुनी ग्रीन हाउस गैसें वायुमण्डल में छोड़ रहा है। सर्वाधिक प्रदूषणकारी ईंधन कोयले का सबसे अधिक और विश्व का लगभग 50 प्रतिशत दहन चीन द्वारा किया जा रहा है।

चीन द्वारा तिब्बत में अत्यन्त नृशंसतापूर्वक मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। श्रीलंका में तमिलों के नरसंहार से लेकर सूडान सहित कई अफ्रीकी देशों में चीन के सैन्य सहयोग व छोटे हथियारों की आपूर्ति से व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन होता रहा है। गार्जियन अखबार में छपे समाचारों के अनुसार चीन निर्यात के लिये सौन्दर्य प्रसाधनों में काम लेने के लिये ''मानव कोलाजन'' (Human Collagen) वहाँ मौत की सजा पाये हुए कैदियों की चमड़ी उतारकर तक प्राप्त कर लेता है। एक पूर्व चीनी स्वास्थ्य उप मंत्री हुआंग जेफू यह भी स्वीकार कर चुका है कि चीन में मृत्यु

दण्ड पाये कैदियों के अंग प्रत्यारोपण आम बात है। जून 2001 में वांग गुओकि नामक पूर्व चीनी मिलिट्री चिकित्सक जिसने अमेरिका में शरण ले ली ने यहाँ तक स्वीकार किया है कि उसने गोली मारकर मौत की सजा पाये हुए 100 से अधिक कैदियों के अंग प्रत्यारोपण में सहयोग किया था। उसने यहाँ तक भी स्वीकार किया कि 1995 में गोली मारकर मृत्युदण्ड पाये हुए कैदी की त्वचा उतारी है जिसका हृदय उस समय धड़क रहा था। गार्जियन में छपे इन समाचारों के अनुसार ही चीन में प्रतिवर्ष लगभग 3 से 7 हजार लोगों को मृत्युदण्ड दिया जाता है। (देखें दि गार्जियन, मंगलवार 7 फरवरी 2017 एवं दि गार्जियन 13 सितम्बर 2005)

वस्तुतः ऐसे सभी प्रकार के अमानुषिक कृत्यों के आधार पर आर्थिक होड़ में लगे चीन का माल विश्व के कितने लोग खरीदेंगे? यदि लोगों को चीन के औपनिवेशिक विस्तार की महत्वाकांक्षाओं, पर्यावरण विनाश एवं मानवाधिकारों के हनन की इन घटनाओं की ठीक-ठीक जानकारी हो जाये। बस! आज यही करना है देश व विश्व के सजग नागरिकों को, जिससे चीन के प्रति सभी लोग सजग हो जायें।

अध्याय - 4

चीन की भारत विरोधी व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियाँ

विगत 60 वर्षों में चीन की सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां उसकी भारत के विरूद्ध जारी हैं। हाल ही में उसने भारत सीमा में अरूणाचल व उत्तराखण्ड में भारत की सीमा में हमारे नहरों आदि के निर्माण को बाधित किया है। वह वर्ष में 300-400 बार सीमा का अतिक्रमण करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के मामलों में भारत के प्रस्तावों के विरूद्ध वीटों का उपयोग कर रहा है। उसने भारत के आणविक आपूर्ति समूह (Nuclear suppliers Group) में प्रवेश का विरोध किया है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के विरोध के बाद भी वह व्यापक स्तर पर निर्माण कर वहीं से 46 अरब डालर के चीन-पाक आर्थिक गलियारे का विकास कर रहा है। भारत में जल संकट उत्पन्न करने के लिये ब्रम्हपुत्र नदी का पानी रोक रहा है। सिंधु नदी का अतिरिक्त जल हम पाकिस्तान में जाने दें, इसके लिये धमकियां दे रहा है। हाल ही में 3 नवम्बर को उसने अरूणाचल में सीमा से 29 किमी अंदर हमारा नहर निर्माण का कार्य रूकवाने का दुस्साहस किया है।

इस प्रकार चीन का आर्थिक व सामरिक सशक्तिकरण भारत के लिये सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण होगा और हमें अपने संसाधन विकास के स्थान पर चीन-पाक से सुरक्षा में लगाने होंगे। इसके लिये भारत के विकास के लिये चीन पर आर्थिक अंकुश सर्वाधिक आवश्यक है। अतएव आज जब चीन एक आर्थिक, वित्तीय बैंकिंग व कार्पोरेट संकट

के ज्वालामुखी पर बैठा है, चीनी वस्तुओं का परित्याग ही इस संकट के विस्फोट की संभावना निश्चित करेगा। चीन की प्रमुख शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों अग्रलिखित है :

1. घुसपैठ व बार-बार सीमा का अतिक्रमण कर सामरिक घेराबन्दी

चीन द्वारा निरन्तर एवं बार-बार घुसपैठ के माध्यम से उत्तरोत्तर नये-नये क्षेत्रों में भारतीय भू-भाग पर अनवरत अतिक्रमण, जल व थल सीमा पर चारों ओर से अमित्रतापूर्ण घेराबन्दी, वायु सीमा का आये दिन अतिक्रमण, हमारे दक्षिणी तटीय क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ाने के लिये और वियतनाम में तेल खोज से दूर रहने की चेतावनी देने के उद्देश्य से श्रीलंका के बन्दरगाहों पर अकारण आणविक पनडुब्बियों की कवायद आदि जैसी अनगिनत शत्रुवत कार्यवाहियाँ जारी है। तथापि, हमारे द्वारा चीन को अनवरत व बिना किसी पारस्परिक आर्थिक प्रति-लाभ के व्यापार व निवेश की सुविधाएँ देते चले जाने की नीति, आत्महीन समर्पण से कम नहीं है। चीन के साथ हमारे विवादों की सूची अत्यन्त लम्बी है। चीन के 1962 में अक्सई चिन के 38,000 भू-भाग को आक्रमण करके हस्तगत कर लिया था, जो पूरे स्विट्जरलेंड के 41,000 वर्ग किमी. के लगभग बराबर एवं इजरायल के क्षेत्रफल से कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर का 5180 वर्ग किमी. भारतीय भू-भाग को उसने पाकिस्तान से ले लिया था। शेष पाक अधिकृत कश्मीर सैन्य उपस्थिति के साथ निर्माण कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त चीन 90,000 वर्ग किमी. भू-भाग पर अपना और दावा जता कर वहाँ बार-बार घुसपैठ कर छुट-पुट नये क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है। सीमावर्ती गाँवों एवं चारागाहों में बार-बार चीनी सेना वहाँ के स्थानीय गाँववासियों को आतंकित कर वहाँ से पलायन को बाध्य कर रही है। जम्मू-कश्मीर को भारत का अंग नहीं मान कर वहाँ के निवासियों को वीजा प्रदान करने के मामले में उनके भारतीय पासपोर्ट पर वीजा अंकित करने के स्थान पर अलग कागज पर वीजा देकर उसे स्टेपल कर रहा है। अरूणाचल के नागरिकों को वीजा देने से इन्कार कर अरूणाचल को चीनी क्षेत्र ठहरा कर उन्हें बिना वीजा चीन में प्रवेश करने का आग्रह कर रहा है। सितम्बर के मध्य में जम्मू-कश्मीर के डेमचोक में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ

कर हमारी सेना से उसकी सेना का आमने-सामने होना, चुमार में निरन्तर घुसपैठ, वहाँ के नागरिकों की हंटर व बैंतों से पिटाई कर उन्हें क्षेत्र से पलायन को बाध्य करना।

चीनी घुसपैठ की आवृत्ति व अतिक्रमण का क्षेत्र निरन्तर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2008 तक उसकी घुसपैठ की घटनायें 100-147 तक रही हैं, 2011 तक 200 व 2013 से 400 से अधिक हो गयी हैं। सर्वाधिक आश्चर्यजनक है कि चीनी राष्ट्रपति शी. जिनपिंग की 3 दिन की भारत यात्रा व हमारे प्रधानमंत्री के साथ वार्ताओं के दौर में भी भारत पर दबाव लाने के लिये अत्यधिक दबावकारी घुसपैठ चीनी सैनिकों ने की थी। वह घुसपैठ और सैन्य गतिरोध शी.जिनपिंग के लौट जाने के बाद पूरा सितम्बर माह बीतने पर ही समाप्त हुआ और दोनों ओर के सैनिक नियन्त्रण रेखा से पीछे अपने-अपने क्षेत्र में लौटे। सम्भवतः चीनी घुसपैठ उनके राष्ट्रपति की सौदाकारी क्षमता बढ़ाने व दबाव पूर्वक भारत में अधिकतम निवेश व व्यापार सुविधायें पाने के लिये ही की गयी भी हो तो आश्चर्य नहीं। चीन भारत के साथ होने वाली किसी भी उच्च स्तरीय वार्ता के दौर में यह करता रहा है। ऐसे में भारत के लिये अपना रोष प्रकट करने की दृष्टि से ऐसी वार्ताओं के दौर की रणनीति अपनाने का भी प्रयोग करना चाहिये, जब तक कि चीन घुसपैठ समाप्त न कर लेवें। चीन ऐसी घुसपैठ से हमारे धैर्य व सहनशीलता का ही परीक्षण करता है। ऐसे में हमको चीन को किसी प्रकार की नवीन आर्थिक सुविधाओं को देने से ही इन्कार करने पर न रुक कर चीनी आयातों को भी स्थगित करके अपने तेवर दिखलाने की रणनीति का भी परिचय देना चाहिये। हम आज चीनी वस्तुओं के लिये साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक का बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। व चीनी कम्पनियाँ 3 लाख 72 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर भारत में काम कर रही हैं। चीनी कम्पनियों द्वारा बिलों में कम राशि या बिना बिल का जो चीनी माल बिक रहा है, वह अलग हैं। ऐसे में भारत द्वारा चीन से सभी प्रकार के व्यापार व निवेश सम्बन्ध स्थगित करने का दबाव अधिक श्रेयस्कर होगा। चीनी सैन्य व घुसपैठ के दबाव के आगे उसको अधिकाधिक व्यापार व निवेश सुविधाओं के उपहार देना यू.पी.ए. सरकार की परंपराओं से चीन को अधिक सैन्य दबाव बनाने व घुसपैठ व अतिक्रमण करने का अवसर देगी।

वस्तुतः चीन जब तक, उसके द्वारा किये जा रहे 150-400 से अधिक वार्षिक अतिक्रमण बन्द न करे तो भारत सरकार को भी उसे भारत में प्रदान की गयी व्यापार व निवेश सुविधायें निलम्बित कर देनी चाहिये। हाल ही में जो 16 सहमति पत्र चीन के साथ हमने हस्ताक्षरित किये हैं, उनमें देश में रेलों के आधुनिकीकरण से लेकर प्रत्यक्ष निवेश आदि की जो सुविधायें हम दे रहे हैं। उनकी भी हमारे राष्ट्रीय आर्थिक हितों पर होने वाले प्रभावों की दृष्टि से भी समीक्षा भी अनिवार्य है। द्रुतगामी रेलों से सम्बन्धित आज जो साज-सामान चीन से आयेंगे, उनका उत्पादन वहां होने पर रोजगार सृजन वहीं होगा, प्रौद्योगिकी समुन्नयन उनके वहाँ होगा, कम्पोनेन्ट निर्माता सहायक उद्योग उनके ही विकसित होंगे। जबकि यदि ये साज-सामान हम विकसित करेंगे तो इससे देश का रेल सम्बन्धी उत्पादन तंत्र व प्रौद्योगिकी विकसित होगी और उन साज-सामानों का मूल्य व उन पर अर्जित लाभ देश से बाहर चीन के हाथ नहीं लगेगा। आज सामान्य उपभोक्ता के रूप में भी जो भारतवासी कम्प्यूटर लीनोवो, जियोनी या मोटो स्मार्टफोन, टी.एस.एल के टी.वी., टेक्सन के केल्कुलेटर, जेड.टी.ई. या हुवाई के सामान और पेन से लेकर बड़े विद्युतीय यन्त्र आदि खरीदते है, उन्हें बन्द कर दें तो भी देश के हजारो करोड़ रूपये बचेंगे। इसलिये चीन द्वारा हाल ही में निरंतर किए जा रहे सीमा के अतिक्रमणों को देखते हुए देश वासियों को चीन के उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए। चीन ने इतने बड़े भारत जैसे बाजार के व्यापक लाभों की भी परवाह न करते हुये हमें आलसी तक कह दिया। इतने बड़े लाभों के उपरांत भी जिस प्रकार उसने उसकी घुसपैठ की आवृतियाँ व उसके पैमाने में वृद्धि की है, उससे यह लगता है कि वह हमें सैन्य घुसपैठों से डरा कर अधिक से अधिक सुविधायें हथियाने की रणनीति अपना रहा है। इसलिये भारत की जनता की चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर उसे करारा उत्तर देना चाहिये। हाल ही कुछ घुसपैठ की बड़ी घटनायें यही दर्शाती है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया जा रहा है :-

1. बॉर्डर पर 60 वर्षों से तनाव एवं बुलडोजर लगाकर अभी जून 2017 में भारत के दो बंकर तोड़ना: चीन ने वर्ष 1957 से ही भारतीय सीमा पर तनाव बनाये रखा है। 1962 में युद्ध कर हमारी 38,000 वर्ग किमी. भूमि पर अधिकार कर रखा है। वह वर्ष

भर में 150-400 बार तक सीमा का अतिक्रमण करता रहा है। अभी जून 2017 में ही चीन की आर्मी ने सिक्किम सेक्टर में घुसकर भारतीय जवानों से हाथापाई की। इस दौरान चीन के सैनिकों ने हमारे 2 बंकर भी बुलडोजर लगा कर तोड़ दिए। चीनी सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ह्यूमन चेन बनाकर चीनियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे धक्का-मुक्की करते रहे। उधर, चीन ने 26 जून 2017 को देर रात उलटा भारतीय सैनिकों पर ही बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगा दिया। पिछले 10 दिनों से सिक्किम के दोका ला जनरल इलाके में चीन की सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही है। सीमा पर इस तनाव के चलते अभी तो एक सम्पादकीय में इस दौरान चीनी जवानों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को भी रोक दिया। चीन की यह हरकत जून के पहले हफ्ते में दोका ला जनरल एरिया की लालटेन पोस्ट के पास हुई। वहां इंडियन आर्मी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान आपस में उलझ गए। इस हाथापाई के बाद चीन की आर्मी के जवान भारतीय इलाके में घुसे और आर्मी के दो बंकर्स बुलडोजर्स लगा कर तोड़ दिए। आज जब दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी चरम पर है। भारत का चीन की वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) समिट से बायकॉट और चीन द्वारा एनएसजी में भारत की एंट्री रोकने जैसे मुद्दों पर गम्भीर मतभेद है।

चीन का उल्टा मिथ्या आरोप - चीन ने भारतीय सेना पर ही सिक्कम में बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया है। उसने भारत से सैनिकों को फौरन वापस बुलाने की मांग की है। चीन ने इसी कारण नाथु ला दर्रे से कैलास मानसरोवर यात्रा को भी रोक कर इसके पीछे बॉर्डर पर जारी गतिरोध को ही वजह बताया है।

2008 में इसी इलाके में चीनी सैनिकों ने तोड़े थे बंकर। वहाँ नवंबर, 2008 में भी चीनी सैनिकों ने इसी इलाके में घुसकर भारतीय सेना के कुछ अस्थायी बंकर ध्वस्त कर दिए थे। वैसे 1962 के भारत-पाक युद्ध के बाद से यह इलाका भारतीय सेना और आईटीबीपी के नियंत्रण में रहा है। हमारे सुरक्षा बलों का कैम्प अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 15 किमी दूर है। चीन ने पहले भारतीय सीमा में सड़क निर्माण प्रारम्भ कर दिया था, जिसे

हमारे सैनिकों ने रूकवाया था। इसलिये पहले चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय सैनिकों के उसकी सीमा में घुसने और वहां बनाई जा रही सड़क का काम रोकने का आरोप लगाया था।

चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रेन ग्यूकियांग ने यह भी स्वीकार करते हुये कहा है कि हाल ही में चीन के डोंगलांग इलाके में रोड बनाने का काम शुरू किया था, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) क्रॉस करके आए भारतीय सैनिकों ने रोक दिया। इस सड़क के निर्माण की वजह से ही चीन ने नाथु ला पास से मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 47 भारतीयों के दल को रोका था। इस पर इंडिया-चाइना के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई। बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए इंडियन आर्मी ने दो बार चीन को फ्लैग मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

20 जून 2016 को चीन आर्मी मीटिंग के लिए तैयार हुई, जिसमें उसने कहा कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को तिब्बत से होकर जाने की परमीशन नहीं दी जाएगी। उन्हें 23 जून तक वहीं रखा गया और इसके बाद उन्हें गंगटोक वापस भेज दिया गया।

मानसरोवर के लिए सिक्किम रूट जो तिब्बत से गुजरता है, उसे 2015 में खोला गया था। इसके पूर्व 1954 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की सन्धि के पूर्व मानसरोवर के रास्ते पर तिब्बत में भारतीय रक्षा चौकियाँ व डाकतार कार्यालय रहे हैं। भारतीय यात्रियों की सहायतार्थ ये सुविधायें हमने विकसित कर रखीं थी। यदि हमने तिब्बत पर चीन को नियन्त्रण स्थापित करने में सहयोग नहीं किया होता व अपना यह अधिकार 1954 के पंचाल के समझौते में छोड़ा नहीं होता तो आज हमारी बेहतर स्थिति होती।

2. नवम्बर 3 को अरूणाचल में भारतीय सीमा निर्माण में बाधा डालना : चीनी सैनिकों ने 3 नवंबर को एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के करीब भारतीय इलाके में चल रहे नहर के कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया। आईटीबीपी के 70 और चीन के 55

सैनिक कई घंटे तक आमने-सामने रहे। इस बीच, इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से 29 किलोमीटर नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट सी-17 ग्लोबमास्टर उतार दिया। ग्लोबमास्टर को 6200 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ 4200 फीट लंबे इलाके में उतरना पड़ा। वहाँ चीनी सैनिकों ने कहा कि भारत को लद्दाख में साब के पास कंस्ट्रक्शन से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। इस घटना में दोनों देशों के सैनिकों ने फ्लैग लगाकर पोजिशन ले ली थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी प्रकार 19 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली में भी चीनी सैनिक नहर का काम रुकवा चुके हैं। तब भी भारतीय जवानों ने उन्हें वापस भेज दिया था। वर्ष 2014 में भी लद्दाख के निलुंग नाले का काम चीनी सैनिकों ने रुकवाकर मजदूरों के टेंटों को नुकसान पहुंचाया था।

3. अरूणाचल में सितम्बर 9, 2016 घुसपैठ : चीन पहले भारतीय सीमा में स्थानीय लोगों को आतंकित कर पलायन को विवश करता है। उसके बाद ऐसे निर्जन क्षेत्रों में घुसपैठ कर वहाँ अपने सुरक्षा बलों के अस्थायी कैम्प बना लेता है। ऐसी ही उसने अभी अरूणाचल प्रदेश के अन्जा जिले की प्लम चौकी तक एक निर्जन क्षेत्र में सीमा पार 45 किमी भारतीय सीमा में घुसकर अस्थायी कैम्प व आशियाने भी बना लिये। सीमा में इतनी गहराई तक आने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र खाली करने को कहने पर इस क्षेत्र को अपना (चीनियों का) बताया। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चीनी सैनिकों को अत्यंत कड़ा रूख अपनाने पर चीनी सैनिकों को 4 दिन बाद 13 जून को इस क्षेत्र को खाली करना पड़ा।

4. जून 10, 2016 को 250 सैनिकों की घुसपैठ : अरूणाचल प्रदेश के ही कामेंग जिले के यागत्से क्षेत्र में जून 10, 2016 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 250 जवानों ने घुसपैठ कर ली। वहाँ सीमा क्षेत्र में गश्त का काम चीनी बोर्डर गार्ड्स का है, चीनी सैनिकों का वहाँ आना सुनियोजित घुसपैठ ही कही जा सकती है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा कड़ा रूख अपनाने के बाद ही वे लौटे हैं। इसी अवधि में चीन 48 सदस्यीय आणविक आपूर्ति समूह में भारत के प्रवेश के विरोध में भी लगा हुआ था।

5. मार्च 8, 2016 को फिंगर टप्प्प् - सिरजेप - प् से 5.5 किमी घुसपैठ: इसी प्रकार के लेह लद्दाख क्षेत्र की ओर भार ठाकुग चौकी से 5.5 किमी अन्दर तक चार वाहनों व भारी शस्त्रास्त्रों साथ चीनी प्लाटून ने घुसपैठ कर के भारतीय बलों पर भारी दबाव उत्पन्न किया। इनमें एक कर्नल व दो मेजर टेंक के अधिकारी दो हल्के वाहन एक मध्यम व एक भारी वाहन था। यह क्षेत्र पेगांग झील के पास पड़ता है, जहाँ वे आये दिन तनाव पैदा करते रहते हैं।

6. जुलाई 2016 में उत्तराखण्ड में घुसपैठ: चीनी सैनिकों ने उत्तराखण्ड के चमोली जिले के बारहोती क्षेत्र में 80 वर्ग किमी के चारागाह क्षेत्र में घुसपैठ कर वहाँ भी तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। चीन के साथ तनाव न हो, इसलिये वहाँ भारतीय सुरक्षा बल बिना शस्त्र व बिना गणवेश के ही गश्त करत हैं। वैसे भारत इतना संकुचित व सिमटा रहना भी उचित नहीं है। इस क्षेत्र में चीन ने 2013 व 2014 में भी कई बार घुसपैठ की है और हमारी वायु सीमा का भी अतिक्रमण किया है।

इस प्रकार से चीन वर्ष में कुल 300- 400 बार तक घुसपैठ कर लेता है। अनेक क्षेत्रों में वह इंच दर इंच करके कई क्षेत्रों में स्थायी रूप से भी आगे बढ़ रहा है। ऐसी घुसपैठों व दौलत बैग ओल्डी में 21 दिन तक रहकर भारत की ब्लेकमेलिंग की समीक्षा लेखक ने अपनी तीन अन्य पुस्तकों में किया है।

भारत के सीमा क्षेत्र में विकास की आवश्यकता : चीन ने पूरी 4057 किमी लम्बी भारत तिब्बत सीमा पर अत्यंत व्यवस्थित सड़कें रेलमार्ग, विद्युतीकरण व संचार साधनों का विकास कर लिया है। वह जब चाहे बड़े पैमाने पर सैन्य बल जमा कर सकता है। लेकिन अब वह भारतीय सीमा में किसी भी प्रकार की गतिविधी या हलचल होने पर वहां अडंगा लगा देता है। इसलिये वहाँ के ग्रामीणों को भारी असुविधा होती है। सर्दी में रास्तों से बर्फ हटाने तक की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परेशानी में पलायन करने तक को विवश हो जाते हैं। चीन चाहता है इन सबसे चीन वहाँ के निवासियों को बताना चाहता है कि यदि वे अपने क्षेत्र में चीन का स्वागत करे तो ही उनके वहाँ सारी नागरिक सुविधायें विकसित होगी।

भारत में आंतकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान व पाक आंतकियों को समर्थन

चीन लगभग 10 वर्षों से निरंतर भारत द्वारा विविध जेहादी आंतकवादी संगठनों व आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में लाए गए प्रस्तावों का विरोध करता रहा है। हाल ही में ताजा घटनाक्रम के अधीन अक्टोबर 1 को पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी, मौलाना मसूद अजहर जिसने जेश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन की स्थापना की थी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का चीन ने अकारण पुनः विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में निरन्तर व अकारण विरोध व वीटो वह केवल भारत को अपमानित व आहत करने व कूटनीतिक पराजय का अनुभव कराने के लिये कर रहा है। वह केवल भारत में हिंसा व जेहादी आतंक फैलाने के दोषी आतंकवादी संगठनों व आतंकवादियों को बढ़ावा देने और पाकिस्तान को भारत में आतंक व हिंसा फैलाने में सहयोग देने हेतु ही चीन, संयुक्त राष्ट्र संघ में विगत 10 वर्षों में अनेक बार भारत के प्रस्तावों का विरोध व उस पर वीटो करता रहा है। इस प्रकार के भारत विरोधी और भारत के विरूद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देने हेतु चीन द्वारा वीटो किये जाने के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से कुछ अग्रलिखित हैं

1. मौलाना मसूद अजहर के बचाव में भारत के प्रस्ताव पर अनेक बार वीटो : मौलाना मसूद अजहर एक खतरनाक आतंकवादी है। 1990 में एअर इण्डिया का विमान अपहरण हो जाने पर भारत की उसे विमान के कन्धार में बन्धक बनाये यात्रियों को आतंकवादियों के चुंगुल से बचाने के बदले में छोड़ना पड़ा था। वह लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी रहा है। उसने ही 'जैश ए मोहम्मद' नामक आतंकी संगठन बनाया था। वर्ष 2009 से भारत द्वारा बार-बार उसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर प्रत्येक बार चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो किया है। पठानकोट आक्रमण के बाद भारत द्वारा हाल ही में मार्च 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्ताव क्रमांक 1267 के अधीन एक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने का नये सिरे से पुनः आवेदन किया था उस पर मार्च 31 को चीन ने वीटो का उपयोग कर उसे अवरूद्ध

कर दिया था। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से अकेले चीन भारत को आहत व अपमानित करने के लिए भारत के प्रस्ताव के विरूद्ध बार-बार वीटो करता रहा है। इसी क्रम में अभी अक्टोबर 1, 2016 को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो 'चीनी दिवस 1 अक्टोबर' पर चीन व उसके नागरिकों की मंगल कामना करते हुये उनकी चतुर्विध प्रगति का सन्देश दिया उसी दिन चीन ने एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने से बचा लिया। उसने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रस्ताव को फिर से वीटो कर दिया। चीन की ओर से मार्च 2016 में लगाए गए वीटो की समय सीमा सितम्बर में खत्म हो रही थी और अगर चीन ने फिर से वीटो नहीं किया होता तो भारत का प्रस्ताव स्वतः पारित हो गया होता।

अब चीन की यह रोक अगले छः महीने के लिए फिर बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, ''भारत की ओर से मार्च, 2016 में 1,267 समिति को सौंपे गये आवेदन पर तकनीकी रोक को पहले ही आगे बढ़ा दिया गया है।'' उन्होंने कहा, 'भारत के आवेदन पर अब भी मतभेद हैं। तकनीकी रोक के आगे बढ़ जाने के बाद समिति को इस मामले पर विचार करने और संबंधित पक्षों को आगे विचार-विमर्श के लिए समय मिल जाएगा। इसी साल 31 मार्च को भी चीन ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड इसी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने के कदम पर रोक लगा दी थी। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होने की वजह से चीन को यह वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में चीन ही इकलौता देश रहा जिसने भारत के आवेदन का विरोध किया, जबकि 14 अन्य देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया।

यदि ''संयुक्त राष्ट्र 1,267 समिति'' की सूची में अजहर का नाम शामिल हो जाये तो उसकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और उसकी यात्राओं पर भी रोक लग जाएगी। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की '1,267 समिति' ही आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है। अक्टूबर 1999 में सुरक्षा

परिषद ने ही यह 1,267 रेजॉलूशन पास किया था जिसके अधीन ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित कर उसके और अलकायदा पर प्रतिबंध लगाया था।

अर्थात अक्टूबर 1, 2016 को उसने छठी बार भारत के विरूद्ध वीटो करने की अवधि बढ़ाने जैसा कदम उठाया है। इसके भी दो दिन बाद ही चीन ने जले पर नमक छिड़ते हुए भारत पर उल्टा यह आरोप जड़ दिया कि भारत आतंकरोधी अभियान के नाम पर अपने राजनैतिक फायदे निकाल रहा है। मौलाना मसूद अजहर के मामले में एक ही वर्ष में दूसरी बार वीटो करके चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह घोर भारत विरोधी और एक प्रबल पाकिस्तान परस्त देश है।

अपनी पाकिस्तान परस्ती और भारत विरोधी रूख को सुदृढ़ता ही नहीं, निर्लज्जता पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए ही चीनी विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को एक अन्तर्राष्ट्रीय आतंक प्रायोजक देश के रूप में सन्दर्भित करने के कथन में विरूद्ध तो चेतावनी ही दे डाली कि भारत पाकिस्तान को 'आतंकवाद की मां' कहने से बाज आये। गोवा में हुये ब्रिक्स समूह के 5 देशों के सम्मेलन में भारत द्वारा पाकिस्तान को 'आतंकवाद को जननी' कहा गया था। उस पर चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ''हुवा चुनयिंग'' ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया की चीन किसी भी देश के समुदाय था सांस्कृतिक समूह को आतंकवाद से जोड़ने के विरूद्ध है। उसने यहाँ तक भी कह दिया कि भारत-पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के बराबर के शिकार है और विश्व समुदाय द्वारा पाकिस्तान के आतंकनिरोधी कदमों व त्याग का समान किया जाना चाहिए।

2. **लखवी के मामले में वीटो :** ताज होटल के हमलावर लखवी की जमानत के मामले में भी चीन ने वीटो का उपयोग किया था। भारत के विरूद्ध मुम्बई में 2008 में ताज होटल पर हमले के प्रायोजक रहमान लखवी की पाकिस्तान में जेल से रिहाई के विरूद्ध भारत द्वारा लाये प्रस्ताव का चीन ने अकारण विरोध कर दिया। वर्ष 2008 में मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गये थे। इस हमले का सरगना, उसके विरूद्ध पाये गये प्रमाणों के आधार पर पाकिस्तान के सड़ियाला जेल में बन्द था।

लेकिन, उसे अप्रेल 10, 2015 को जेल से रिहा कर दिया गया। इस पर भारत ने पाकिस्तान से इस बात पर सवाल कर लिया कि लखवी घोषित आतंकवादी है जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव क्रमांक 1267 के अधीन प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। ऐसे में उसको जमानत की राशि कहाँ से आई? लखवी ने जमानत के लिए 5 लाख रूपये कैसे चुकाये? उसकी जमानत के लिए दो मुचलकों पर भी 10-10 लाख रूपये जमा किये गये थे। भारत सरकार ने कूटनीतिक नोट के जरीये यह भी जाना चाहा कि यह सारी राशि किसने चुकाई है? भारतीय खुफिया एजेन्सी रॉ के अनुसार यह राशि आईएसआई द्वारा चुकाई गई थी। इसलिये भारत के संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी ने मई 3, 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की ''प्रस्ताव 1267 समिति'' से इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के अधीन प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही लखवी की सारी सम्पत्ति व धन जब्त किया जा चुका था। ऐसे में यह 25 लाख रूपये की राशि कहां से आई इसके जाँच करने का आग्रह किया था। भारत द्वारा इस संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग पर भी चीन ने जून 25, 2016 को वीटो कर दिया। वीटो का उपयोग कर इसे टेक्नीकल होल्ड पर रखवा दिया।

3. जमात उद दावा, लश्कर ऐ तैयबा व अल अख्तर ट्रस्ट के मामलों में वीटो :

भारत द्वारा जब भी किसी आतंकवादी या आतंकी संगठन के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 के अधीन प्रस्ताव लाया गया तब केवल 2008 के मुम्बई आक्रमण के अत्यंत वीभत्स मामले को छोड़ कर चीन ने प्रत्येक बार वीटो किया है। मुम्बई आक्रमण में 166 लोगों की मृत्यु व सम्पूर्ण विश्व में इसकी निंदा के कारण चीन ने जमात उल दावा, हाफिज सईद और लखवी को आतंकवादी घोषित किये जाने के मामले में इस मुम्बई आक्रमण के बाद 1267 के अधीन लाये प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया था। स्मरण रहे कि जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित करने के प्रस्ताव पर इसके पूर्व चीन 3 बार वीटो कर चुका था। चीन ने लश्कर ए तैयबा व जैश ए मोहम्मद के अगुआ संगठन अल अख्तर ट्रस्ट पर प्रतिबन्ध के भारत के प्रस्ताव को भी, भारत पर यह आरोप लगा कर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अवरूद्ध कर दिया कि भारत पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

4. वर्ष 2010 में भी जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर और लश्कर के आतंकी अब्दुर रहमान मक्की व आजम चीमा पर प्रतिबन्ध के प्रस्ताव पर भी चीन ने पुनः वीटो का उपयोग किया था। इस प्रकार 2016 में मसूद अजहर के मामले में वह लम्बे समय से वीटो उपयोग कर रहा है।

5. वर्ष 2015 के प्रारम्भ में ही चीन ने हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर भी वीटो किया था।

भारत का अवमाननाकारक उपहास

मई माह में भारत के प्रधान मंत्री की मई 2015 में चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों (भारत व चीन) ने आतंकवाद के विरूद्ध मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता अभिव्यक्तकरने वाला संयुक्त वक्तव्य जारी कर सब देशों व संगठनों से आतंकवादियों के जाल को नष्ट करने उनके वित्तीय व देशों के बीच सीमा पार आने जाने पर पूर्ण रोक का आवाहन किया था। उसके अगले ही महीने जून में लखवी के मामले में और उसके ठीक पहले मार्च में मसूद अजहर व पुनः अक्टूबर 1 को भी मसूद अजहर के मामले में वीटो किया। यह अक्टूबर 1 का वीटो तो ठीक उसी दिन किया जिस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन दिवस पर चीन की सरकार व चीन की जनता को अभिनन्दन संदेश दिया। प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं का उपहास ही उड़ाया है।

ये सभी आतंकवादी न तो चीन के नागरिक है, न उनके संगठन चीन में स्थित हैं और न ही इनका चीन से कोई संबंध है। केवल भारत के विरूद्ध आतंकवाद, उत्तरोत्तर अधिकाधिक बलवान बने और पाकिस्तान को भारत के विरूद्ध आतंकी लड़ाई जारी रखने में कठिनाई नहीं हो, इसलिये ही वह बार-बार वीटो कर रहा है। वीटो के साथ उसने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को गोवा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के समय आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की चेतावनी तक दे दी। इससे अधिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्या हो सकता है।

3. पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जल रोकना

भारत की सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने की प्रतिक्रिया में एवं सिन्धु नदी जल बँटवारे की भारत द्वारा पुनर्समीक्षा व उसे निरस्त करने की चेतावनी देने के विरूद्ध पाकिस्तान को भारत विरोधी कार्यवाहियों में सम्बल देने की गरज से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जेंग पो के जल को अवरूद्ध कर चीन ने भारत के विरूद्ध बदले की कार्यवाही के रूप में जल संकट उत्पन्न करने की चेतावनी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भारत को अपने पांरपरिक रूप से प्राप्त जल से वंचित करना अवैधानिक है। लेकिन, केवल पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीन ने यह भारत विरोधी कदम उठाया है। चीन का प्रत्यक्ष रूप में भारतीय सेना के द्वारा सितम्बर 28-29 की रात को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के विरूद्ध पाक अधिकृत कश्मीर में की गई 'सर्जिकल' कार्यवाही के विरूद्ध पाकिस्तान के पक्ष में उठाया गया यह भारत विरोधी कदम है। चूंकि भारत ने 1960 के अयूब समझौते के अधीन पाकिस्तान के हिस्से के जल से, पाकिस्तान में अतिरिक्त मात्रा में जा रहे जल को रोकने की चेतावनी दी थी। इसके विरूद्ध भारत तो जब जल रोकेगा तब रोकेगा, पर चीन ने तो पाक समर्थन में यह गैर कानूनी कदम उठा ही लिया है।

वस्तुतः उड़ी में आतंकवादी आक्रमण के बाद भारतीय सेना की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के विरूद्ध शल्य क्रिया जैसी सीमित सैन्य कार्यवाही (Surgical Strikes) के विरोध में पाकिस्तान के प्रति अपनी मित्रता का प्रदर्शन करते हुये चीन ने जेंगबो नामक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी अवरूद्ध कर भारत को परोक्ष में यह चेतवनी दी है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के विरूद्ध आतंकवाद विरोधी कार्यवाही करने पर या सिन्धु नदी के जल से पाकिस्तान को वंचित करने पर वह ब्रह्मपुत्र नदी के जल से भारत को वंचित कर देगा। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की उपरोक्त सहायक नदी का पानी रोकने के लिये ही वहाँ एक हाईड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। भारत के लिए यह भारी चिंता की बात है क्योंकि, चीन के इस कदम से भारत समेत कई देशों में ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। इससे भारत की 10 करोड़ से अधिक आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

चीन ने यह काम ऐसे वक्त में किया है जब उड़ी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सिन्धु जल समझौते से अतिरिक्त पाकिस्तान में जा रहे जल को रोकने हेतु यह बैठक की थी। साथ ही इस समझौते की समीक्षा करने का भी फैसला किया था। भारत ने समीक्षा का यह निर्णय और सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय केवल पाक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के विरूद्ध दबाव बनाने के लिए किया था। ऐसे में चीन, भारत का जल अवरूद्ध करने वाला यह कदम पाकिस्तान के साथ मिलकर उल्टा भारत पर दबाव बढ़ाने की धमकी के रूप में उपयोग कर रहा है।

पठानकोट व ज़ड़ी में आतंकवादी आक्रमणों के विरूद्ध पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिये ही पाक के साथ हुए सिंधु समझौते पर मोदी बोले थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। भारत-पाक के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। उड़ी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश के क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंधु जल समझौते पर रिव्यू मीटिंग की थी। इसमें विदेश सचिव एस जयशंकर नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र शामिल थे। 1960 के सिंधु जल समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को भारत से बहने वाली छः नदियों का पानी मिलता है। इसी पानी से पाकिस्तान में कई प्राजेक्ट चल रहे हैं और सिंचाई की जा रही है। लेकिन भारत द्वारा अपने हिस्से के जल का पूरा उपयोग नहीं कर पाने से ही पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी मिल रहा है। इसलिये प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुई मीटिंग में यह फैसला हुआ कि भारत झेलम सहित पाक के हिस्से में बहने वाली नदियों के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत सिंधु जल समझौते के अधीन पश्चिमी नदियों के पानी से 18 हजार मेघावाट बिजली बना सकता है। नेहरू - अयूब समझौते के अधीन भारत के अधिकारों की पहचान करने के लिए एक इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स बनाने का भी निर्णय लिया गया था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि तुलबुल प्रोजेक्ट का भी रिव्यू किया जाएगा जिस पर 2007 में काम बंद हो गया था। भारत ने इस नेहरू-अयूब समझौते को निरस्त करने तक की धमकी भी दे दी थी।

इस समझौते के तहत छः नदियों - व्यास, रावी, सतलज सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी भारत और पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा कि भारत उसे समझौते की शर्तों से कम पानी देता है। वह दो बार इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में शिकायत भी कर चुका है। समझौते के अनुसार सतलज, व्यास और रावी का अधिकांश पानी भारत के हिस्से में रखा गया था। जब कि सिंधु, झेलम और चिनाब अधिकांश पानी पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया था। यदि यह समझौता कैंसल हुआ तो प्यासा रह जाएगा पाकिस्तान। सिंधु और बाकी पांच नदियां पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून ने भी पिछले दिनों कहा था कि सिंधु के पानी के बगैर देश का एक हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। सिंधु, झेलम और चिनाब में वाटर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की वैसे ही भारी परेशानी है। अगर यह समझौता कैंसल हो गया तो पाकिस्तान में बिजली संकट भी खड़ा हो सकता है। इसके अलावा, इन तीनों नदियों से एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई भी की जाती है। इसलिये इसकी संवेदनशीलता व गम्भीरता को दखते हुये ही पाकिस्तान को बल देने के लिये चीन ने पाकिस्तान की ओर से यह बदले की कार्यवाही करने जैसा कदम उठाया। ब्रह्मपुत्र नदी के जल को रोकने का काम चीन में 2008 से ही चल रहा है। लेकिन अभी जेंग पो नदी का पानी रोककर एक नयी चेतावनी दी है।

तिब्बत में यारलुंग जेंगबो नाम से जानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र की इस सहायक नदी पर चीन ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 75 करोड़ डॉलर (5100 करोड़ रूपये तुल्य) का निवेश केवल इसलिये किया है कि वह पाकिस्तान से अपनी मित्रता दृढ़ करने हेतु भारत को क्षति पहुंचा कर दण्डित करे। चीन का यह प्रोजेक्ट तिब्बत के जाइगस क्षेत्र में है, जो सिक्किम के निकट पड़ता है। वस्तुतः जाइगस से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरूणाचल प्रदेश में बहते हुए प्रवेश करती है। इसलिये यहाँ बांध बना कर भारत का सर्वाधिक पानी रोक भी सकता है और जब चाहे तो जल प्लावन करके वहाँ कृत्रिम बाढ़ का प्रकोप भी पैदा कर दे। पूर्व में 2000, 2001 और 2005 में चीन, हिमाचल में अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ कर बाढ़ का संकट पैदा कर चुका है। चीन द्वारा 2000 में अचानक सतलज के बेसिन में बिना किसी पूर्व सूचना के पानी छोड़ने से

हिमाचल में बाढ़ का संकट पैदा होने से 100 लोग मारे गये थे। 2000 के मध्य में अरूणाचल में भी अचानक बिना पूर्व सूचना के ब्रह्मपुत्र में बाँधों का पानी छोड़ देने से ब्रह्मपुत्र का जल स्तर 30 मीटर चढ़ गया, जिसमें अरूणाचल में 26 लोग मारे गये व 35,000 लोग बेघर हो गये। भारत में प्रवेश के पूर्व ब्रह्मपुत्र के तिब्बत के ऊपरी भाग के प्रवाह में जल स्तर चढ़ने के समाचारों को भी उसने वहाँ के संचार माध्यमों में आने से भी केवल इस कारण रोक दिया, ताकि भारत को उस कृत्रिम बाढ़ की अग्रिम सूचना न हो सके। हिमाचल में बाढ़ का संकट खड़ा करने के लिये ही छोड़ा था, जिसकी उसने भारत को कोई अग्रिम सूचना नहीं दी। दूसरी ओर पाकिस्तान व बांग्ला देश में, भारत से जाने वाली नदियों में जब भी जल स्तर बढ़ता है तो भारत उसकी हाइड्रोलॉजिकल सूचनायें तत्काल उन्हें देता है। इस प्रकार चीन भारत के विरूद्ध यह नये प्रकार के युद्ध की तैयारी कर रहा है। इन बाँधों के निर्माण से वह भारत के विरूद्ध बनावटी अकाल व बाढ़ के द्वारा आक्रमण कर सकेगा।

चीन अपने इस अत्यन्त महंगे प्रोजेक्ट को 2019 में पूरा कर लेना चाहता है। यह पानी रोकने से भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में ब्रह्मपुत्र के बहाव पर भी व्यापक असर पड़ेगा। पिछले वर्ष भी चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में डेढ़ अरब डालर की लागत वाला सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस पर भी भारत ने चिंता जताई थी। लेकिन, चीन ने इसकी अनदेखी कर दी है। चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना से इस बात के संकेत मिलते हैं कि तिब्बत के स्वायत क्षेत्र में चीन 3 और जल विद्युत परियोजनायें (हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट) केवल भारत का जल हड़पने के लिये लाने वाला है। इससे सम्पूर्ण पूर्वोत्तार में गम्भीर जल संकट पैदा होगा और चीन इन बांधों का पानी कभी भी छोड़कर पूर्वोत्तार में जलप्लावन का संकट खड़ा कर सकेगा। आज चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मोड़ने की कोशिश केवल इसलिये कर पा रहा है, क्योंकि 1951 में चीन को तिब्बत को हड़प लेने में भारत ने सहयोग किया था। ब्रह्मपुत्र सहित तिब्बत से 10 बड़ी नदियाँ निकलती हैं और जिनसे 11 देशों को जलापूर्त्ति होती है, चीन उन नदियों के जल को मन चाहे ढंग से मोड़ रहा है। यदि जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में समझौता करा कर तिब्बत पर चीन को अधिकार करने में सहयोग नहीं दिया होता और

वह स्ततंत्र देश बना रहता तो यह जल संकट ही नहीं उपजता। उत्तर पूर्वी चीन में जलापूर्त्ति के लिये उसका तीन घाटियों वाला बांध पहले से ही है तब भी वह बड़ी मात्रा में जल को तिब्बत से उल्टी दिशा में इसलिये मोड़ रहा है, ताकि वह उधर से भारत का पानी रोक सके। इस हेतु उसने ब्रह्मपुत्र नदी को व्यापक स्तर पर अवरूद्ध करने के लिए अनेक बांध बनाने शुरू कर दिये हैं। उन बांधो से उसने सुरंगों (टनल), पाईप लाईनों और नहरों का निर्माण शुरू कर दिया है। उपग्रहों के चित्रों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों, अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं व चीनी समाचार पत्रों के अनुसार वहाँ व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। स्मरण रहे, मेकॉन्ग नाम की नदी भी वहीं तिब्बत से निकलती है जिससे लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम और थाइलैण्ड इन चार देशों को जलापूर्त्ति होती रही है। उसके प्रवाह को चीन ने अवरूद्ध किया है। वहां उन देशों में बड़ी मात्रा में भू-भाग सूखे में बदल रहा है क्योंकि चीन ने मेकॉन्ग नदी का पानी रोक दिया है। इसी विवाद के चलते पाँच देशों का मेकान्ग नदी आयोग बना हुआ है, चीन या तो उसकी बैठकों में जाता नहीं है और जाता है तो कहता है कि हमने तो आपका कोई पानी नहीं रोका है, कोई डाईवर्जन नहीं किया है। चीन इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है कि उसने इन देशों का जल प्रवाह रोका है, जबकि ये चार देश बहुत परेशान हैं। आज जब हमारे देश के 10 करोड़ लोगों का जीवन ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर है, हमको इस विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद के रूप में उठाना चाहिये। ब्रह्मपुत्र का जल अवरूद्ध होने से बांग्ला देश भी प्रभावित होगा। इसलिये हमें उसे भी साथ लेना चाहिये। चीन को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिये तथा उसकी प्रतिबद्धता लेनी चाहिये कि वह ब्रह्मपुत्र के जल को मोड़े नहीं (डाईवर्ट नहीं करे)। अन्यथा अरूणाचल प्रदेश और असम सूखे में बदल जायेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में सवा लाख क्यूबिक फीट पानी प्रति सैकण्ड बहता है, ग्लेशियरों का एकदम विशुद्ध जल। बाढ़ के समय तो 10 लाख क्यूबिक फीट पानी उसमें प्रति सैकंड बहता है। ब्रह्मपुत्र को मोड़ देने से सारी जल राशि हमको मिलनी बन्द हो जायेगी और स्थिति यह हो जायेगी कि ब्रह्मपुत्र नदी मौसमी नाले में बदल सकती है।

4. आणविक आपूर्ति समूह में विरोध

भारत ने 48 देशों के आणविक आपूर्ति समूह (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) की सदस्यता चाही थी। उस समूह के अधिकांश राष्ट्रों ने भारत की सदस्यता के पक्ष में प्रबल समर्थन दिया। लेकिन चीन ने भारत का प्रबल विरोध कर भारत की सदस्यता के प्रस्ताव को इसी वर्ष 2016 के जून में अवरूद्ध का दिया। उसके दोनों ही विरोध के बिन्दु अत्यंत हास्यास्पद थे। उसके द्वारा भारत व पाकिस्तान को समान धरातल पर रखना भी अव्यावहारिक था। केवल चीन के विरोध के कारण ही भारत इस समूह की सदस्यता से वंचित रहा है। यह चीन का भारत विरोध व भारत के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार का एक बड़ा उदाहरण है। आज भी जून 2017 में भी उसने यही दोहराया है कि वह भारत की सदस्यता का विरोध जारी रखेगा।

5. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विरोध

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का इच्छुक है। विश्व के अधिकांश देश भारत के इस दावे का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चीन ही इसका विरोध कर रहा है। स्मरण रहे जब चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता नहीं मिल पा रही थी, तब 1950 में साम्यवादी देशों को छोड़कर अन्य देशों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश था, जिसने चीन की सदस्यता के लिये सर्वाधिक सशक्त आग्रह किया था।

6. पाक अधिकृत कश्मीर में सैन्य उपस्थिति व निर्माण

भारत के सतत विरोध के बाद भी चीन की पीपुल्स लिबटेशन आर्मी के सैन्य प्लाटून व वरिष्ठ अधिकारी वहां बड़ी संख्या में रह रहे हैं। चीन वहाँ स्थायी निर्माण कर रहा है और वहां से राजमार्ग भी निकाल रहा है। आज पाकिस्तान व चीन के पास कुल मिलाकर 1,06,000 वर्ग किमी भूमि अवैध नियंत्रण में है। इसमें 68,000 वर्ग किमी कश्मीर की भूमि पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में व 38,000 किमी भूमि चीन के पास है। चीन ''चीन-पाक आर्थिक गलियारे''(China Pak Economic Corridor) का 46 अरब डालर अर्थात 3 लाख करोड़ की लागत से विकसित कर रहा है, वह पाक अधिकृत कश्मीर के भारतीय भू-भाग से निकल रहा है। ऐसे में भारत की आपत्ति को

उसने ठुकरा दिया। वहाँ यह सारे निर्माण अवैध है क्यों कि उस क्षेत्र की स्थिति को 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण से पुरानी स्थिति में लौटाने का संयुक्त राष्ट्र संघ का भी प्रस्ताव है। अब तो उसका ‘वन बेल्ट वन रोड’ नाम वाला नया सिल्क रूट भी वहीं से निकल रहा है।

7. भारत के आर्थिक हितों को हानि पहुंचाने के लिए चीन ने अफ्रीका में ‘मेड इन इण्डिया‘ ब्राण्ड की वस्तुएं विशेष कर दवाईयाँ भी प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। इसका स्पष्ट उद्देश्य अफ्रीका में भारतीय वस्तुओं को बदनाम करना था।

8. चीन ने 2011 में भारत के सूती वस्त्र उद्योग को चौपट करने के लिए देश में उत्पन्न अधिकांश कपास को अत्यन्त ऊँचे दाम पर खरीद लिया था। जब देश में कपास का मूल्य 4000/- रूपये क्विटल था तब उसने 7000/- रूपये प्रति क्विंटल खरीद कर भारतीय वस्त्र उद्योग को चौपट करने का प्रयत्न किया था।

9. चीन द्वारा जम्मू-कश्मीर को अपने नक्शों में भारत का अंग नहीं दिखाया जाता है। अरूणाचल प्रदेश को चीन का अंग दिखाकर वहाँ के नागरिकों को बिना पासपोर्ट वीजा के चीन आने का आमन्त्रण दिया जाता है।

10. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अरूणाचल को ‘‘हमारा सूरज का प्रदेश’’ कहने पर चीन हमारी महिला राजदूत को रात्रि 2 बजे उठाकर कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए चेतावनी देता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अरूणाचल प्रदेश के तवांग जिले में प्रवेश नहीं करने की धमकी देता है और मनमोहन सिंह वहां की यात्रा निरस्त कर देते हैं।

11. चीन ने भारतीय सीमा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है जिनके मारक क्षेत्र में सम्पूर्ण भारत आता है।

12. भारत की चारों ओर से घेराबन्दी की दृष्टि से चीन ने पाकिस्तान (ग्वादर बंदरगाह), नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश (चटगांव बंदरगाह) एवं श्रीलंका में सैन्य गतिविधियों का विस्तार किया।

13. चीन का रक्षा बजट 200 अरब डालर है जबकि भारत का रक्षा बजट मात्र 40 अरब डालर है। इसे हम भारतीय माल खरीद कर अपना कर राजस्व बढ़ा कर ही बढ़ा सकेंगे।

14. 14 अप्रैल, 2 013 की रात्रि में बिना टेंकों या तोपखाने के 40 चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा में 19 किमी. तक घुसपैठ कर दौलत बेग ओल्डी में तम्बू गाड़ दिये। भारत सरकार उन्हें बाहर धकेलने के स्थान पर उनसे ब्लेकमेल होती चली गयी और उन्हें बाहर जाने को मनाने के लिये हमारे द्वारा अपनी ही सीमा में अपनी सेना को सीमा में 38 किमी. पीछे ले जाना पड़ा और हमारी सीमा में अपनी रक्षा संरचनाएँ यथा सेना के बंकर आदि अपने ही हाथों से तोड़ने पड़े थे। चीन की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों पर 3 हिन्दी व एक अंग्रेजी में लेखक की पुस्तकें पहले से प्रकाशित हैं। इसलिये इस पुस्तक में आर्थिक विषय को ही प्रमुखता से लिया है।

अध्याय - 5

समाधान

इसलिए आज हम संकल्प ले कि चाहे हमें किसी भी वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़े तो भी कोई चीनी उत्पाद नहीं खरीदेंगे। समाज में भी अभियान चला कर सभी देशवासियों से आग्रह करें कि वे भी कोई चीनी सामान नहीं खरीदें। आजकल चीन कई वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही कर रहा है। इसलिए उन पर 'मेड इन इण्डिया' भी लिखा होता है। इसलिए चीनी ब्राण्डों की पहचान करने हेतु कुछ चीन के सामानों व मोबाइल फोनों के ब्राण्डों के नाम यहाँ दिए जा रहे है। लेनोवा, ओपो, हुवाई, क्जिमी, एमआई 4, एल्काटेल, अमोई, बीबीके, कूलपेड, कबोट, जी 5, जियोनी, हेयर, हिसेन्स, कोन्का, मोटा, जेडटीई, लिईको, मैजु, वनप्लस, क्हु 360 आदि इसलिए इन ब्राण्डों एवं अन्य भी चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। अंग्रेजी में इन ब्राण्डों की स्पेलिंग अग्रानुसार है – **Lenovo, Oppo, Huawei, Xiomi, mi4, Alcatel, Amoi, BBK, Coolpad, Cubot, Gfive, Gionee, Haier, Hisense, Konka, Motto, ZTE, LeEco, Meizu, OnePlus, Qihoo360, QiKU, Ningbo Bird, Smartisan, Technology Happy Life, Vivo, Vsun, Wasam, Xiomi, Zopo Mobile, Zuk Mobile.**

चाहे पेन व स्टेशनरी के सामान हो, थाली या प्लेट अथवा क्रॉकरी हो, मोबाइल फोन व कम्प्यूटर हो, एल.ई.डी. बल्ब या विद्युतीय सजावटी समान हो, काँच के सामान

हो या ट्रकों के टायर, हमें सभी चीनी उत्पादों व ब्राण्डों का सम्पूर्ण परित्याग कर देना चाहिये। चीनी ब्राण्ड व उत्पाद चाहे चीन में बने हो या भारत में, चाहे चीनी ब्राण्डों पर मेड इन इण्डिया लिखा हो, हमें उनका परित्याग करना ही है। चीन मेड इन चाइना करें या मेक इन इण्डिया करें, सारे चीनी उत्पादों व ब्राण्डों का पूर्ण बहिष्कार करना ही होगा।

इसी प्रकार चाहे टेलीफोन में 2जी, 3जी, व 4जी सेवाओं के उपकरण या रेलों का आधुनिकीकरण हमें स्वदेशी सेवा प्रदाताओं व उपकरणों का ही उपयोग करना चाहिये। अतएव सौर ऊर्जा हो या स्मार्ट सिटी विकास या रेलों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव, उनमें यदि विदेशी निवेश या चीनी निवेश लायेंगे, आयात करेंगे या विदेश भू-संपदा विकास-कर्त्ताओं (foreign real estate developers) व विदेशी सेवा प्रदाताओं को अपने देश में उत्पादन के लिये निमन्त्रित करते चले जायेंगे तो उसके लाभों व अन्य भुगतानों की इतनी अधिक राशि देश से बाहर जायेगी कि हमारी आगामी पूरी पीढ़ी उनके भुगतानों में ही चुक जायेगी। इसके कारण देश से इतनी विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष देश से बाहर जायेगी कि हम एक बड़ी सीमा तक और हम आर्थिक दृष्टि पंगु हो जायेंगे। आज देश में जो उच्च आयातों और 1993 से 2017 के बीच हुये विदेशी निवेश पर देश से वाहर ले जाये जा रहे लाभों के कारण तेजी से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा में भुगतानों का संकट और भी भयावह रूप में सामने आयेगा। तब हमें उस भुगतान संकट से उबरने के लिये और नये-नये अवसंरचना क्षेत्र के व लोक कल्याण के अधिष्ठानों में विदेशी निवेश आमंत्रित कर उस संकट से उबरना पड़ेगा। इसलिये, विदेशी निवेश पर हमारी बढ़ती ही जा रही निर्भरता के इस संकटकारी दुष्चक्र से बाहर निकलने की पहल हमें कभी तो करनी ही होगी। ऐसे में सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक पार्क व रेल विकास आदि को हम अभी प्रारम्भ से ही विदेशी निवेश व आयात आधारित कर लेंगे तो, उस पर होने वाले लाभों व आयातों के रूप में विदेशी मुद्रा के बाह्य-प्रवाह (out-flow) के संकट से हम मध्यमावधि तो क्या दीर्घावधि में भी कदाचित ही उबर पायेंगे। वस्तुतः यह विदेशी निवेश, हमारे लिये विदेशी कर्ज से भी अधिक घातक सिद्ध हो सकता है।

अतएव देश के विकास के लिये उपभोक्ता उत्पादों, मशीन टूल, औषधियाँ, निर्माण परियोजनाओं और आधारिक रचनाओं यथा, दूर संचार, सौर व पवन ऊर्जा सहित स्मार्ट शहरों के विकास से लेकर बुलेट ट्रेन पर्यन्त सभी क्षेत्रों में 'मेड बाई भारत' को छोड कर कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। हम सभी देश भक्त हैं। देश के लिये आवश्यक है कि ऊर्जा व सौर ऊर्जा ही नहीं हम अपनी सभी प्रकार की खरीददारी में रोजगार प्रधान स्थानीय उद्योगों की वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान करें। देश में उत्पादन वृद्धि विकेन्द्रित उत्पादन व मेड बाई इण्डिया उत्पादों व ब्राण्डों के चलन से ही समावेशी विकास सम्भव है। लघु उद्योगों के उत्पाद व ब्राण्ड उपलब्ध नहीं होने पर ही रोजगार विस्थापक बड़े उद्योगों के उत्पाद खरीदें। स्वदेशी उत्पादों की तुलना में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एवं विदेशों से आयातित उत्पादों से यथा सम्भव बचें। यदि विदेशी कम्पनियों के उत्पाद देश में नहीं बिकेंगे तो वे कुछ माह भी यहाँ नहीं टिक पायेंगी। स्वदेशी भाव जागरण से ही देश में स्वदेशी एक सशक्त मुद्दा बनेगा। स्वदेशी जागरण मंच 1991 से देश में वैश्वीकरण की शुरूआत के समय से ही यह आवाहन करता रहा है एवं भारत को उन्नत व सशक्त राष्ट्रों की अग्र पंक्ति में स्थापित करने हेतु इस मुद्दे पर जन जागरण करता रहा है। आइये हम सब स्वेदशी भाव जगाकर स्वावलम्बी राष्ट्र बनायें। यदि अमेरिका जैसा देश (Be American-Buy American) का उद्घोष (Slogan) लगाता है तो हम भारत में 'मेड बाई इण्डिया' और स्वदेशी की बात क्यों नहीं करें। यदि एक सैनिक देश की राजनीतिक समप्रभुता के संरक्षण के लिए सीमा पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है तब हम भी देश की आर्थिक सम्प्रभुता के लिये सौर ऊर्जा ही नहीं, एक उपभोक्ता के रूप में अपनी छोटी-बड़ी खरीद में भी आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा व्यक्त करते हुए विदेशी व चीनी वस्तुओं के स्थान पर मेड बाई इण्डिया को बढ़ावा क्यों नहीं दें? हम सामान्य उपभोक्ता उत्पादों से लेकर सभी प्रकार के स्वदेशी साज सामान खरीदेंगे, तब ही देश में उत्पादन, रोजगार, आय, माँग व निवेश में वृद्धि होगी और हमारी प्रौद्योगिकी समुन्नत होगी।

सौर ऊर्जा में देश में फोटो वाल्टॉइक सेल उद्योग अपनी 25-35 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर पा रहा है। यदि विद्यमान घरेलू उद्योगों को काम नहीं मिला तो देश

का इस क्षेत्र में विगत 20 वर्षों इस उद्योग में हुआ 20,000 करोड़ रुपयों का निवेश व्यर्थ जायेगा। आयातों व विदेशी पूंजी के कारण सभी उद्योग श्रेणियों में हमारे पहले से चले आ रहे उत्पादक उद्योग भी बन्द हुये हैं। विदेशी कम्पनियां अपने वैश्विक श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर कुछ पुर्जे देश में बना कर शेष हिस्से पुर्जे बाहर से ला कर यहाँ पर केवल उन्हें जोड़ने या एसेम्बल करने का ही काम करती हैं। वे अपनी तकनीक को सुरक्षित रखने हेतु ही यह करती हैं। इससे प्रौद्योगिकी का विकास (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट) भी वहाँ पर उनके देश में ही होती है और हम एक प्रकार से पूरी तरह से उन पर अवलम्बित हो जायेंगे। विदेशी कम्पनियाँ, विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी वाले साज सामान बाहर से ही लायेंगी। दूसरी और देश के सौर ऊर्जा संयंत्र, बुलेट ट्रेन या रेल्वे आदि के सभी साज सामानों का उत्पादन देश में होगा और औद्योगिक पार्कों व स्मार्ट शहरों का विकास भी देश के उद्यमों द्वारा किया जायेगा तो निम्नवर्ती मूल्य श्रृंखला (downstream value chain) में साज सामान बनाने वाले उद्यमों को कई गुना काम मिलेगा। उस अनुभव से देश के उद्यम विश्व भर में अपने कारोबार के विस्तार में समर्थ होंगे। इन सब कामों के देश में होने पर उनमें कार्यरत कार्मिकों को मिलने वाले वेतन से जो बाजार में खरीददारी करेंगे उससे कई क्षेत्रों में कारोबार व उत्पादन बढ़ेगा। वहाँ कार्मिकों को वेतन भुगतान से और मांग, कारोबार उत्पादन, निवेश व रोजगार बढ़ेगा और इससे एक स्वतःस्फूर्त व अनवरत मांग, उत्पादन, रोजगार आय, कारोबार निवेश वृद्धि का चक्र चलता व बढ़ता ही जायेगा। इसलिये 'मेड बाई इण्डिया' को बढ़ावा देने के अतिरिक्त विकास का अन्य कोई मार्ग ही सम्भव नहीं है। विश्व के सभी औद्योगिक व धनी देश, केवल 'मेड बाई इण्डिया' जैसे स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर ही विकसित हुये है। विदेशी निवेश व आयात उदारता केवल पराश्रयता व परावलम्बन के अधोगामी मार्ग पर ही ले जायेगी। इसलिये सौर ऊर्जा का यह 6.5-7.0 लाख करोड़ रुपये व पवन ऊर्जा का 3.0-3.5 लाख करोड़ रुपये का काम भारतीय उद्यमों के हाथ में जाये, यह अति आवश्यक है। यह दस लाख करोड़ रुपये के कारोबार का सृजन करेगा। इससे देश में उत्पादन, निवेश रोजगार को ापबोजंतज करने का हमें जो अवसर मिलेगा, वह हमने खो दिया तो आगामी दस वर्ष तक इतने बड़े घरेलू निवेश से विकास को kickstart करने का दूसरा अवसर कठिन है।

वस्तुतः चाहे पेन व स्टेशनरी का सामान हो अथवा मोबाइल फोन, चाहे सजावटी सामान व फर्निचर हो या कम्प्यूटर व कार,, हमें चीनी या अन्य भी विदेशी ब्राण्ड छोड़ कर स्वदेशी उत्पाद व ब्राण्ड ही खरीदने चाहिये। चीन की वस्तु तो कदापि नहीं खरीदनी चाहिये। इसी देश में चाहे सौर ऊर्जा उपकरण हो या स्मार्ट सिटी विकास के उपकरण या रेलों के आधुनिकीकरण व बुलट ट्रेन के प्रस्ताव, उनमें यदि चीनी या विदेशी निवेश लायेंगे या विदेशी निर्माण कम्पनियों व विदेशी सेवा (foreign real estate developers) को अपने देश में उत्पादन के लिये निमिंन्त्रत करेंगे तो उसके लाभों व अन्य भुगतानों की इतनी अधिक राशि देश से बाहर जायेगी कि हमारी आगामी पूरी पीढ़ी उनके भुगतानों में ही चुक जायेगी। इसके कारण देश में इतनी विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष देश से बाहर जायेगी कि हम एक बड़ी सीमा तक और हम आर्थिक दृष्टि पंगु हो जायेंगे। आज देश में जो उच्च आयातों और 1993 से 2017 के बीच हुये विदेशी निवेश पर देश से बाहर ले जाये जा रहे लाभों के कारण तेजी से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा में भुगतानों का संकट और भी भयावह रूप में सामने आयेगा। तब हमें उस भुगतान संकट से उबरने के लिये और नये-नये अवसंरचना क्षेत्र के व लोक कल्याण के अधिष्ठानों में विदेशी निवेश आमंत्रित कर उस संकट से उबरना पड़ेगा। इसलिये, विदेशी निवेश पर हमारी बढ़ती ही जा रही निर्भरता के इस संकटकारी दुष्चक्र से बाहर निकलने की पहल हमें कभी तो करनी ही होगी। ऐसे में सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक पार्क व रेल विकास आदि को हम अभी प्रारम्भ से ही विदेशी निवेश व आयात आधारित कर लेंगे तो, उस पर होने वाले लाभों व आयातों के रूप में विदेशी मुद्रा के बाह्य-प्रवाह (out-flow) के संकट से हम मध्यावधि तो क्या दीर्घावधि में भी कदाचित ही उबर पायेंगे। वस्तुतः यह विदेशी निवेश, हमारे लिये विदेशी कर्ज से भी अधिक घातक सिद्ध हो सकता है।

यदि देश में रोजगार सृजन करना है एवं विद्यमान रोजगार को बचाना है तो देश में विद्यमान उद्योगों को बन्द होने से बचाना होगा एवं देश में घरेलू निवेश बढ़ाना होगा। देश के उद्यमी निवेश करना चाहते हैं, लेकिन चीन द्वारा की जा रही सस्ती डम्पिंग के कारण निवेश का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये चीनी व अन्य विदेशी उत्पादों व

ब्राण्डों पर निर्भरता समाप्त कर अपनी क्षमताओं का आंकलन कर स्वदेशी भाव से देश को धारणक्षम व समावेशी विकास के पथ पर ले जाना होगा।

स्वदेशी के सन्दर्भ में हमारा स्वरूप व सामर्थ्य : चीन को पीछे छोड़ेंगे हम

आज देश के हम 132 करोड लोग हैं। देश में 6 लाख से अधिक गाँव हैं, विश्व का सर्वाधिक पशुधन है, विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत के पास है, 127 प्रकार के विविध कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, और 400 से अधिक विविध प्रकार के संगठित लघु उद्योग संकुल (SSI clusters) व 7000 से अधिक असंगठित सूक्ष्म उद्योगों के संकुल हैं। इसी क्रम में देश में 3 करोड़ 10 लाख लघु व सूक्ष्म उद्यम है, जिनमें 7 करोड़ 30 लाख लोग नियोजित हैं और इन लघु उद्यमों के द्वारा 6000 से अधिक प्रकार के उत्पाद या वस्तुओं का उत्पादन व कारोबार किया जाता है। इनमें से एक करोड़ 24 लाख ग्रामीण उद्यम है। इन उपरोक्त कुल 3 करोड़ 10 लाख लघु व सूक्ष्म उद्यमों में से 1 करोड़ 90 लाख सेवा प्रदाता उद्यम है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो देश के 13 लाख विद्यालयों में 32 करोड़ छात्र और 800 विश्वविद्यालय व तत्सम डिग्री प्रदाता संस्थानों सहित 45,000 महाविद्यालयों में 3.2 करोड़ छात्र नामांकित हैं। यूरोप के 28 देशों की कुल जनसंख्या ही हमारी कुल जनसंख्या के दो-तिहाई से भी कम है। ऐसे में हमारे देश की विशाल जनसंख्या व उपरोक्त वर्णित विविधताओं को देखते हुए हमें विकेन्द्रित नियोजन व समावेशी विकास का मार्ग अपनाना चाहिये।

ऐसे में हम स्वदेशी अर्थात 'मेड बाई भारत' या भारतीयों अर्थात भारतीय उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ ही क्रय करेंगे तो देश में उत्पादन, निवेश, रोजगार, प्रौद्योगिकी विकास, आय वृद्धि मांग वृद्धि, पुनः निवेश व उत्पादन वृद्धि का विकास चक्र गतिमान होगा। यदि विदेशी ब्राण्ड अपनायेंगे तो इसका लाभ उन देशों को जायेगा। विकेन्द्रित नियोजन के अन्तर्गत हमें विकेन्द्रित उत्पादन, लघु उद्योग संकुलों के विकास, उसके लिये उत्पादक सहयोग संघों (Industry Consortium) के गठन की ओर भी तेजी से बढ़ना चाहिये। इसके लिये चीन की भांति तकनीकी राष्ट्रवाद एवं फ्रांसिसी आर्थिक राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र निष्ठा या स्वदेशी की रीति-नीति पर बल देना ही होगा। इसमें हमारी मितव्ययी प्रौद्योगिकी विकास (Frugal Engineering) की परम्परा को भी

यथेष्ट बल प्रदान कर देश में उद्योग, व्यापार वाणिज्य व कृषि के विकास को बढ़ावा देना होगा।

विकेन्द्रित नियोजन व समावेशी विकास : चीन से चुनौति के अलावा भी हमें केन्द्रीकृत नियोजन के स्थान पर हमें विकेन्द्रित नियोजन की नीति भी अपनानी होगी। विकास का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे इस हेतु समावेशी विकास व समावेशी आर्थिक वृद्धि ही स्वदेशी के केन्द्र बिन्दु होने चाहिये। विकेन्द्रित नियोजन पर विचार करें तो कोई एक तहसील तालुका या मंडल है वहाँ कितना पशुधन है? वहाँ कितने लोग काम करने योग्य हैं? वहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन (raw materials) हैं, वहाँ की कृषि सामर्थ्य (agriculture potential) किस तरह की है? किस प्रकार के कुटीर, सूक्ष्म, लघु व बड़े उघोग हैं? वहाँ कितने विद्यालय-महाविद्यालय हैं, लोगों में किस प्रकार का तकनीकी, व्यावसायिक या शिल्प ज्ञान है? इन सबके आधार पर वहाँ पर किस प्रकार के उद्यमों व कार्यो पर आधारित विकास की रचना होनी चाहिए? यह सभी विचार करके वैसी योजना विकसित करनी होगी। फिर पूरे देश के ग्रामों तहसीलों, जिलों व प्रदेशों की इन विकेन्द्रित स्थानीय योजनाओं को जोड़कर ही राष्ट्रीय योजनाओं में उन्हें समेकित (integrate) करना चाहिए। हम चीन से अधिक प्रभावशाली व विश्व मंगलकारी राष्ट्र के रूप में विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिये हमें चीनी वस्तुओं व चीनी निवेश पर निर्भरता छोड़कर स्वावलम्बी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिये।

चीन के सन्दर्भ मे प्रभावी रीति-नीति आवश्यक

चीन के बढ़ते भू राजनैतिक, आर्थिक व तकनीकी वर्चस्व, सीमा पर बढ़ते दबाव एवं देश के अन्दर बढ़ते चीनी कम्पनियों के जाल के आलोक में भारत को प्रभावी प्रतिकार की रीति-नीति विकसित करनी चाहिये। अब तो चीन ने उच्च प्रौद्योगिकी व सामरिक तैयारी के क्षेत्र में भी अमेरिका को पीछे छोड़कर क्रमांक एक पर आने के लिये सशक्त पहल की है। इस दृष्टि से भी हमको उपयुक्त व्यूह रचना पर विचार करना होगा।

सर्वप्रथम भारत-तिब्बत सीमा की रक्षा व उसका प्रबन्ध गृह मंत्रालय के स्थान पर सीधे सेना को सौंप देना चाहिये। इस हेतु भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का दैनिन्दिन संचालकीय नियन्त्रण सेना को दे देना चाहिये। भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल व बांग्ला सीमा पर आसाम राइफल्स पर भी नियन्त्रण सेना का रहता है। तब फिर भारत-चीन सीमा, जहाँ अधिक तनाव है, वहाँ पर गृह मंत्रालय का क्या औचित्य है? इस सीमा पर प्रभावी पेट्रोलिंग के लिये यह आवश्यक है।

हमारी रक्षा तैयारियाँ, चीन व पाक से बेहतर होनी चाहिये। आज हमारी 1.06 लाख वर्ग किमी. भूमि पर पाक व चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे मुक्त कराने के लिये हमें सशक्त बनना होगा। शेष सीमावर्ती क्षेत्र में भी चीन की बार-बार की घुसपैठ रोकने के लिये भी सीमा पर अवसंरचना विकास, पर्याप्त सैन्य बल की तैनातगी एवं उन्नत शस्त्रास्त्रों का विकास कर उनको सेना में सम्मिलित करना भी आज की अनिवार्य आवश्यकता है। चीन के पास 6 नाभिकीय पनडुब्बियाँ जहाज भेदी प्रक्षेपास्त्र, उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र, एक से अधिक नाभिकीय बम ले जाने वाले इण्टरकाण्टिनेण्टल बैलिस्टिक मिसाइलें आदि हैं। उनके प्रतिकार की भी हमारी तैयारी आवश्यक है। चीन (J-20 व J-31) दो पाँचवी पीढ़ी के ऐसे युद्धक विमानों का परीक्षण कर चुका है, जो रडार से नहीं देखे जा सकते हैं (Fifth Generation Stealth Fighter Aircraft)। इसमें से एक को वह अपनी वायु सेना में सम्मिलित कर भी चुका है। चीन अपने विमानवाही जहाजों पर भी पाँचवी पीढ़ी के J.31 को तैनात कर रहा है। भारत अभी तीसरी पीढ़ी के तेजस पर ही काम कर रहा है और राफेल्स जो खरीद रहा है, वहीं भी पाँचवी पीढ़ी का नहीं है। F.16 जो अब हम एसेम्बल करने वाले हैं, वह भी चौथी पीढ़ी का ही है। इस दिशा में भी हमारी प्रभावी पहल होनी चाहिये।

दौलत बेग ऑल्डी, चूमार व सिटी जेप सहित लद्दाख के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिये। इस हेतु देश को अपना रक्षा व्यय बढ़ाना चाहिये। हम रक्षा पर अपने जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत ही व्यय कर पा रहे हैं, 1987-88 में हमारा व्यय 3.8 प्रतिशत था।

चार वर्ष पूर्व हुये दौलत बेग ओल्डी जैसे अतिक्रमणों का तत्काल सैन्य प्रत्युत्तर देकर, घुसपैठ करने वाले सैन्य बल को बलपूर्वक निकाल बाहर करने की नीति निर्धारित करनी चाहिये।

चीन ने सभी क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी के समुन्नयन के लिए 1.5 ट्रिलीयन डॉलर (75 लाख करोड़ रूपये, जो आज हमारे देश के जी.डी.पी. के बराबर है) का अनुसन्धान व विकास (आर एण्ड डी) के लिये प्रावधान किया है जिससे वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अमेरिका से आगे निकले। इसलिए भारत को चीन की इस सम्पूर्ण बढ़त को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूरसंचार के क्षेत्र में चीन पाँचवी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें भी पाँचवी पीढ़ी की दूर संचार प्रौद्योगिकी के विकास की पहल करनी चाहिये।

इसके साथ ही हमें तत्काल पहल करते हुये सबसे पहले तो चीन के उत्पादों का सम्पूर्ण बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिये। उसके लैम्प, खिलौने, मोबाइल फोन से लेकर, उसके कम्प्यूटर पर्यन्त जितनी आम उपभोक्ता चीजे खरीदते उनके ऊपर हम अंकुश लगा ही सकते साथ ही यदि जन चर्चाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों और व्यक्तिगत बातचीत, साक्षात्कार आदि में लोगों को चीन के इन खतरो के प्रति आगाह करते हैं, तब एक ऐसा वातावरण बनेगा कि सरकार भी चीनी निर्यातकां व कम्पनियों को मिल रही सुविधाएं, बन्द करने का सोचेगी।

बड़ी संख्या में चीन के कर्मचारी और टैक्नोक्रेट्स, जो अवैधानिक रूप से देश में रह रहे है, उनको भी डीपॉर्ट करना चाहिये। चीनी कम्पनियों को बड़ी मात्रा में जो विविध परियोजनाएं दी जा रहीं हैं उन पर भी अंकुश लगाया ही जाना चाहिये।

इन्टरनेट पर फेसबुक से लेकर सभी प्रकार के सोशल नेटवर्क्स हैं, उनके माध्यम से चीन के द्वारा जो मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, और अबोध रूप से जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसके आलोक में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आव्हान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना चाहिये।

यह चीन को अपने वैश्विक व मानवोचित दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनायेगा। चीन ने तो आज एक लाख साईबर योद्धा नियुक्त कर रखे हैं जो इन्टरनेट पर जाते है और हमारी सुरक्षा सम्बन्धी व अन्य संवेदनशील सूचनाएँ हड़प कर ले जाते है। हमारे रक्षा मंत्रालय के कम्प्यूटर सिस्टम से भी बड़ी मात्रा में सूचनाएं उसने चुराई हैं। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के कम्प्यूटर से सारी की सारी संवेदनशील जानकारियां चीन के साईबर योद्धा चुराकर ले गये हैं। जिस प्रकार का साईबर युद्ध चीन ने भारत के विरूद्ध छेड़ रखा है, हमें भी वैसा ही साईबर युद्ध और चीनी उत्पादों में बहिष्कार का अभियान छेड़ना चाहिये। चीन का आज जो कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) है, उसका 60 प्रतिशत निर्यात आधारित है। अगर चीन के उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो में खपत बन्द हो जाती है तो उसके सारे के सारे कारखाने तीन गुनी ओवर कैपेसीटी के शिकार होकर बन्द होंगे और वहां के बैंको का ऋण डूबने का शिकार होकर, अर्थ व्यवस्था चौपट हो सकती है। 2008 की जो आर्थिक मंदी थी, उस आर्थिक मंदी के दौर में चीनी अर्थ व्यवस्था बिल्कुल धूल धूसरित होने की स्थिति में हो गई थी। चीन के बैंको को 1.2 ट्रिलीयन डॉलर (60 लाख करोड़ रूपये) के कर्जे बांटने पड़े थे, ताकि लोगो की घरेलू खपत बढ़े और उसके कारखाने चालू रह सकें और वह बेरोजगारी, मंदी व उद्यम बन्दी का शिकार न हो। उन ऋणों में से आज 400 अरब डॉलर के ऋण नान परफार्मिंग एसेट (डूबते हुए कर्जो) में बदल गये हैं। चीन के बैंकों के कुल ऋणां का अनुमानतः 17 प्रतिशत आज नान परफोर्मिंग एसेट की श्रेणी में हैं। हमारे देश में यह ऋण दो प्रतिशत से कम है। इसलिये दीर्घकालिक दृष्टि से चीन की अर्थ व्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था इस दृष्टि से सुदृढ़ है। बस, यह बहिष्कार अभियान ही भारत को क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति बनायेगा।

आज चीन और भारत को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत विश्व की खाद्य शक्ति की सामर्थ्य रखता है। हमारे पास साढ़े सोलह करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। चीन के पास 9 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि ही है। उसके पास 11 करोड़ हैक्टेयर कृषि युक्त भूमि थी लेकिन इन्फॉस्ट्रक्चर डवलपमेन्ट के चक्कर में उसकी 2 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गई और वह खेती करने के योग्य नहीं रही। सिंचित क्षेत्रफल

की दृष्टि से भी भारत आज विश्व में क्रमांक एक पर है। भारत जितनी (5 करोड़ 70 लाख हैक्टेयर) सिंचित कृषि योग्य भूमि किसी भी देश के पास नही है। चीन भी दूसरे स्थान पर है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आज भी भारत कई क्षेत्रों में चीन की तुलना में बेहतर स्थिति रखता है। चीन के प्रोडक्ट्स, आज हम भी अपने देश में देखते है कि, टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार चाहे हमारी प्रौद्योगिकी हो, या कृषि सामर्थ्य अथवा चाहे हमारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव हो या विश्वसनीयता, भारत की अपनी छवि है।

भारत को विश्व के अधिकांश देश एक विश्वसनीय सत्ता के रूप में देखते हैं। चीन को एक निरंकुश शक्ति के रूप में आँकते हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध जगत में भारत अच्छा प्रभाव बना सकता है। चीन के इन वक्तव्यों कि ''बौद्ध पंथ की विरासत चीन के पास है न कि भारत के पास'' को बौद्ध जगत गम्भीरता से नहीं लेता है। आज बौद्ध जगत के साथ अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने की बात हो या साईबर युद्ध, चीन के उत्पादों के बहिष्कार से चीनी विकास को शिथिल करना हो अथवा चाहे हमारी प्रौद्योगिकी का जो स्तर है, और हमारी जो कृषि सामर्थ्य है, उस सब दृष्टि से भारत आज बहुत द्रुत गति से चीन से आगे बढ़ने की स्थिति में है। चीन में आने वाले समय में वृद्धों के बढ़ते अनुपात का संकट आने वाला है। वहां प्रति एक कार्यशील व्यक्ति पर 6 वृद्धों का जो अनुपात होगा वह भी उनके विकास में बाधक सिद्ध होगा। दूसरी ओर 2020 तक दुनिया की 28 प्रतिशत श्रम शक्ति भारत की होगी। विश्व के सारे ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय होंगे। ऐसे में हमको चीन के उपभोक्ता उत्पादों की जो भारत में बाढ़ आई हुई है, हमारे देश में सारी निर्माण परियोजनाओं से लेकर टेलिफोन, विद्युत संयन्त्र स्थापना के कार्य जो चीन को दिये जा रहे हैं और चीन के उत्पादों की जो विश्व में बिक्री हो रही है, विश्व बाजारों में यदि मानवाधिकारों के हनन व पर्यावरण क्षरण आदि के आधार पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है, जिसकी पहल हम कर सकते हैं तो शायद एक या दो वर्ष में ही चीन की अर्थ व्यवस्था अपने ही बोझ के तले दबकर पिछड़ सकती है। आज उसके सकल घरेलू अनुपात में 60 प्रतिशत निर्यातों का अनुपात है। उसकी अत्यधिक निर्यात निर्भरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध होगा। चीन उत्पादों को यदि

भारतीय उत्पाद प्रतिस्थापित करते हैं, तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से अधिक व विश्व में सर्वोच्च हो सकती है।

इसलिये यदि भारत में चीन निर्मित वस्तुओं का उपयोग बन्द होता है तो चीन को, भारत से जो 4-5 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा व उस पर चीन की सरकार को जो 50 से 60 हजार करोड़ रूपयों की कर राजस्व (टेक्स) की आय मिल रही है, उसमें भी कमी आयेगी और देश का धन देश में रहेगा। यदि भारत सरकार पर चीन के विरूद्ध प्रभावी जन दबाव बनता है, तो सरकार चीन के देने वाली व्यापारिक सुविधाओं में कटौति के लिये बाध्य होगी और सीमा विवाद पर भी कठोर रूख अपनायेगी। इसके साथ ही यदि चीन द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के हनन, तिब्बती जनता के दमन और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबन्धों की अवहेलना कर कई देशों में जन आन्दोलनों को कुचलने हेतु छोटे हथियारों की आपूर्त्ति और पर्यावरण को विनष्ट करने में अग्रणी होने के तथ्य इण्टरनेट आदि के माध्यम से विश्व जन समुदाय में प्रसारित होते है। तो चीन निर्मित वस्तुओं का उपभोग सम्पूर्ण विश्व में घटेगा। चीन भारत के निर्यात बाजारों पर कब्जा करने में सफल नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त चीन की अर्थव्यवस्था निर्यातों पर अवलम्बित है। उसके गैर कृषि क्षेत्र का लगभग दो तिहाई उत्पादन निर्यात आधारित है। यदि चीन के निर्यात घटते हैं और उसकी आर्थिक वृद्धि दर में कमी आती है, तो भारत की आर्थिक वृद्धि दो क्रमांक एक पर होगी। चीनी आर्थिक वृद्धि दर नियन्त्रण में रहेगी तो उसकी सामरिक बढ़त व महात्वाकांक्षाएँ भी सीमा मे रहेंगी। अस्तु देश, समाज व विश्व-मानवता के प्रति संवेदनशील जन-मानस को चीन की बढ़त को नियंत्रित रखने हेतु सक्रियता दिखलानी चाहिये। विश्व-मानवता के हितार्थ भारत को अपने वैश्विक दायित्व निर्वहन हेतु आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व नेतृत्व के अपने वैश्विक दायित्व के प्रति सजगता बढ़ानी होगी।

संक्षेप में देशवासियों को चीन में बनी वस्तुओं का सम्पूर्ण बहिष्कार करना चाहिये। सरकार पर भी इस बात के लिये दबाव बनाना चाहिये कि वह चीनी आयातों को नियंत्रित करे और चीनी कम्पनियों को देश की परियोजनाओं में काम नहीं दे। भारत-तिब्बत सीमा पर नियन्त्रण गृह मंत्रालय के स्थान पर सेना को सौंप दिया जाना चाहिये।

चीन की सामरिक सामर्थ्य से बेहतर रक्षा सामर्थ्य विकसित करना आवश्यक है। विदेश नीति को प्रभावशाली बनाते हुये भारत के मित्र देशों पर बढ़ते चीनी प्रभाव को परिमित करने की पहल करनी चाहिये। उन सभी देशवासियों को इण्टरनेट व सोशल मीडिया पर, चीनी उत्पादों के वैश्विक बहिष्कार का वातावरण बनाना चाहिये, जो इन साधनों का उपयोग करते हैं। चीन द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के हनन व विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने के इतिवृत्त को देखते हुये इसमें अत्यन्त अच्छी सफलता मिलेगी। चीनी अर्थव्यवस्था निर्यातों पर अवलम्बित होने से इस प्रकार के आर्थिक बहिष्कार से उसका पराभव अवश्यम्भावी है।

चीन की सभी शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां का उत्तर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार से बहुत आसानी से दिया जा सकता है। इस संबंध में निम्न कार्य विशेष रूप से हमें करने हैं -

1. भारत में चीनी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार।

2. सभी व्यापारियों एवं उद्यमियों से भी चीनी वस्तुओं को आयात नहीं करने का आग्रह करना।

3. चीनी वस्तुओं पर तकनीकी आधार पर यथा सम्भव रोक लगाने के लिए सरकार से आग्रह करना।

4. चीन को स्पष्ट चेतावनी देना कि उसके द्वारा विविध अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध जारी रहा और उसके द्वारा सीमा का अतिक्रमण भी जारी रहेगा तो भारत सरकार चीन से आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देगी।

5. यदि तब भी चीन की सरकार नहीं माने तो पहले सीमित अवधि के लिए और बाद में पूरी तरह से चीनी आयात पर प्रतिबन्ध लगा देना। भारत के लोगों को सोशल मिडिया पर सम्पूर्ण विश्व समुदाय पर चीनी उत्पाद का बहिष्कार करने का आग्रह करना चाहिये।

6. चीन जिस प्रकार से विश्व के अनेक भागों में मानवाधिकार के हनन में लिप्त है। तिब्बत में भी व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन किया है इसके साथ ही उसने

पर्यावरण विनाश की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कर रहा है। अतएव सम्पूर्ण विश्व में ही चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाह्न किया जाना चाहिये।

7. चीन के इन सभी दुष्कृत्यों का ठीक-ठाक प्रसार करने पर सम्पूर्ण विश्व में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारम्भ हो जायेगा और इससे ही चीन सही मार्ग पर आएगा।

स्वलिखित

1. प्रबंध
2. प्रबंध एवं संगठन व्यवहार
3. व्यावसायिक सान्नियम
4. प्रतिभूति विनियम एवं वित्तिय बाजार
5. कंपनी अधिनियम
6. व्यावसायिक वातावरण
7. उद्यमिता
8. अन्तराष्ट्रीय विपण्न
9. व्यावसायिक संचार
10. विक्रय प्रबंध
11. औद्योगिक एवं व्यापारिक सान्नियम

संपादित

1. Ethics and Indian Ethos in Management-Text and Cases
2. Innovative Practices in HR: Contemporary Issues and Challenges
3. Green Marketing: Issue and Perspectives
4. Consumer Behavior: Emerging Issues and Perspectives
5. Contemporary Issues in Marketing
6. Enhancing Human Capabilities: Big Challenge in Indian Perspective
7. Service Sector: Contemporary Issues
8. Emerging Issues in Accounting and Finance
9. Ethics and Values in Resource Management
10. Economic and Socio-Cultural Environment of Business

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

लेखक परिचय

प्रो. शर्मा 1978 से वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकायों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कर रहे हैं। आपने वाणिज्य एवं प्रबन्ध के क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिये 11 पुस्तकें लिखी हैं जो हिमालय पब्लिकेशन सहित राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गयी हैं। इनके मार्गदर्शन में 15 छात्रों ने पीएच.डी. स्तर का शोध किया है एवं इन्होंने 80 से अधिक अन्य शोध परियोजनाओं का निर्देशन किया है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनके 230 से अधिक लेख एवं शोध पत्र प्रकाशित हुये हैं।

आर्थिक एवं वैश्विक व्यापार सम्बन्धी विषयों में रुचि होने से प्रो. शर्मा ने स्वदेशी जागरण मंच की ओर से, विश्व व्यापार संगठन ; (W.T.O.) के पाँचवे, छठे एवं दसवें मंत्रिस्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन में क्रमशः 2003 में केन्कुन (मैक्सिको), 2005 में हाँगकाँग व 2015 में नैरोबी (केन्या) में भाग लिया है।

प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रो. शर्मा अन्तर्व्यक्ति व्यवहार की प्रभावशीलता, समय प्रबन्धन, संगठन विकास, शून्य आधारित बजट परिवर्तनों के प्रबन्ध, नेतृत्व विकास आदि विषयों के प्रशिक्षक भी हैं।

इन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, स्वदेशी, विनिवेश आदि विषयों पर 21 लघु पुस्तिकाएँ भी लिखी हैं। वर्तमान में प्रो. शर्मा स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक भी हैं।

इनका ई-मेल आई.डी. bpsharma131@yahoo.co.in है।